Ranchi ● Friday, 29 August 2025 ● Year : 03 ● Issue : 224 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published From Ranchi

नेशनल स्पोर्ट्स डे आज

SHARE
सेंसेक्स : 80,080.57
निफ्टी : 24,500.90

SARAFA
सोना : 9,570
चांदी : 130.00
(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

एसीबी के हत्थे चढ़ा चैनपुर प्रखंड का क्लर्क

GUMLA : गुरुवार को गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड कार्यालय में एसीबी ने सह प्रधान सहायक (क्लर्क) राजकुमार साहनी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के

अनुसार, सेवानिवृत जनसेवक धनंजय प्रसाद से भविष्य निधि से राशि निकासी संबंधी कागजात तैयार करने के एवज में 20 हजार रुपये की मांग की गई थी। मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने एसीबी से शिकायत की थी। शिकायत दर्ज होने के बाद एसीबी ने तय योजना के तहत साहनी को रिश्वत की रकम लेते ही पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम राजकुमार साहनी को गुमला सदर थाना ले गई। बताया जाता है कि साहनी लंबे समय से प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित था और विभिन्न कार्यों में विलंब करने तथा फाइलों को बढ़ाने के एवज में पैसे की मांग करता था। गुमला अंचल कार्यालय में पदस्थापन के दौरान भी रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ था। मामले में तत्कालीन उपायुक्त ने साहनी को निलंबित कर दिया था।

तीसरे दिन भी वैष्णो देवी यात्रा रही स्थगित

NEW DELHI : वैष्णो देवी यात्रा रूट के अर्धकुंवारी में हुए लैंडस्लाइड के बाद यात्रा रोकी गई है। तीसरे दिन भी यात्रा स्थगित रही। इसके कारण कई श्रद्धालु फंस गए हैं। कुछ यात्री कटरा के होटलों में यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें मलबा साफ होने तक इंतजार करने को कहा गया है। घटना के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शवों को उनके घर भेजने की जिम्मेदारी ली है। 24 मृतकों की पहचान हो गई है।

रूस के हमले में यूक्रेन के14 लोगों की मौत

NEW DELHI : गुरुवार को रूस और यूक्रेन ने एक-दूसरे के यहां ताबड़तोड़ हमले कर कहर बरपाया। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में स्थित अफिप्सकी तेल रिफाइनरी पर रणनीतिक हमला किया। इससे रिफाइनरी में आग लग गई। दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस दौरान कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। कीव पोस्ट की खबर में यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के हवाले से दावा किया गया है कि गुरुवार तड़के रक्षा बलों ने रूस में रणनीतिक ठिकानों और अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों पर रुक-रुक कर कई हमले किए। यूक्रेनी बलों ने इस दौरान रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में स्थित अफिप्सकी तेल रिफाइनरी पर हमला किया। इससे रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यह रिफाइनरी रूसी सेना को ईंधन की आपूर्ति करती है।

मानसून सत्र का अंतिम दिन : मंत्री दीपक बिरुआ ने रखा प्रस्ताव, सर्वसम्मति से पास

विधानसभा ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारतरत्न देने के लिए पारित किया प्रस्ताव

PHOTON NEWS RANCHI : गुरुवार को झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र संपन्न हो गया। सत्र के अंतिम दिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारतरत्न से सम्मानित करने के लिए विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। इस फैसले से केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा। सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुए इस आशय के प्रस्ताव को भू-राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सभा पटल पर रखा। इसे सदन ने ध्वनि मत से सर्वसम्मति से पारित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं, लेकिन झारखंड अलग राज्य के योगदान में जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो का भी योगदान रहा है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते समय इन दो विभूतियों का भी नाम उसमें जोड़ा जाना चाहिए। मंत्री दीपक बिरुआ ने शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलन का जननायक बताते हुए कहा कि आदिवासी, मूलवासी, किसान, शोषित वर्ग के अधिकारों, मान और स्वाभिमान की रक्षा और अलग राज्य की लड़ाई के निर्माण में उन्होंने संपूर्ण जीवन लगा दिया। उनका जीवन सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनआकांक्षाओं की पूर्ति में ऐतिहासिक महत्व रखता है। वह एक विचार और आंदोलन थे। उनके अथक संघर्ष और त्याग से हमे एक नया राज्य और नई पहचान मिली। ऐसे जननायक को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतरत्न देना सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बता दें कि पिछले मानसून सत्र के दौरान 4 अगस्त 2025 को उनका निधन हो गया था।

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया समर्थन, अब जल्द ही इस फैसले से केंद्र को कराया जाएगा अवगत

- प्रस्ताव पास होने के दौरान सदन में मौजूद थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
- जयपाल सिंह मुंडा व विनोद बिहारी महतो का नाम भी जोड़ने का किया गया अनुरोध

सदन शुरू होते ही हुई नारेबाजी

झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का अंतिम दिन भी शोर-शराबे के साथ शुरू हुआ। सुबह 11 बजकर 8 मिनट पर सदन की कायावाही शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वेल में घुस गए और हंगामा करने लगे। सदन के भीतर भी पक्ष और विपक्ष दोनों ने नारेबाजी की। पक्ष ने जहां विपक्ष पर वोट चोरी के आरोप लगाए, तो वहीं विपक्ष ने गोड्डा एनकाउंटर और रिम्स 2 को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष ने वेल में विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर भी प्रदर्शन किया। स्पीकर ने विधायकों को चेतावनी दी पर विधायकों का हंगामा जारी रहा।

अब तक किसी भी आदिवासी को नहीं मिला है भारतरत्न

शिबू सोरेन को भारतरत्न देने के अनुरोध से जुड़ा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होने पर संसदीय कार्यमंत्री ने सुझाव दिया कि पारित प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख हो कि आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। आजादी के 78 वर्ष बाद आजतक किसी भी एक आदिवासी को भारतरत्न की उपाधि नहीं दी गई है। इस प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सदन में मौजूद थे। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी एक सुझाव पेश किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा कैंपस में शिबू सोरेन के साथ-साथ शहीद सिदो-कान्हू और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि 26 अगस्त को सदन में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया था। इस पर आसन ने कहा कि यह प्रस्ताव स्वतः पारित है। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस प्रस्ताव को केंद्र को प्रेषित किया जाए।

गुरुजी हमारे बीच नहीं, उनके बताए मार्ग पर बढ़ेंगे आगे : हेमंत सोरेन

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित किया। कहा कि मानसून सत्र हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण और न भूलने वाला सत्र है। आज हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति को खोया, जो केवल विधायक, सांसद, सीएम या केंद्रीय मंत्री तक ही नहीं, उससे उपर उठकर वे इंसान थे। इसकी वजह से सिर्फ झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के आदिवासी समुदाय के लोग उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते रहे हैं। अब तो वे हमारे बीच नहीं है। लेकिन, निश्चित रूप से उनके बताए मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। इस राज्य को अस्तित्व दिलाना और झारखंड आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाना बहुत आसान काम नहीं था। इस राज्य की आवाज, संघर्ष, राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान का संघर्ष इतना मजबूत रहा कि इसके साथ साथ कई राज्यों का सृजन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने गुरुजी को भारतरत्न देने को लेकर प्रस्ताव तो पारित कर दिया। लेकिन, केंद्र में इनकी सरकार है। अब देखें कि ये लोग क्या करते हैं।

पूरे देश के आदिवासी समुदाय के लोग मानते हैं प्रेरणास्रोत

- बुजुर्गों और राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मान दिलाने का करेंगे काम
- आसान नहीं था इस राज्य को अस्तित्व दिलाना व आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाना
- तेलंगाना राज्य के विषय को लेकर भी गुरुजी ने वहां के लोगों का किया था मार्ग-दर्शन

देश के कोने-कोने से आए लोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह का संघर्ष इस राज्य में जल, जंगल और जमीन के लिए किसान, मजदूर ने किया, ऐसा संघर्ष कहीं और देखने को नहीं मिला। इस भावुक समय में जब गुरुजी का निधन हुआ तो देश के कोने-कोने से लोग आए। तेलंगाना के सीएम भी आए थे। उन्होंने भी कहा था कि जब झारखंड राज्य अलग हुआ, तब तेलंगाना के अलग राज्य के विषय को लेकर गुरुजी ने वहां भी लोगों का मार्ग-दर्शन किया था। कहीं न कहीं गुरुजी के जो कार्य रहे, वह झारखंड तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देशव्यापी रहे। हम सब लोगों ने यह संकल्प कर सरकार चलाने का निर्णय लिया है। यहां के लोगों का आर्थिक, सामाजिक सुधार कैसे हो। हमारे आने वाली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले।

हंगामे की भेंट चढ़ गए 235 अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न

चार दिनों के मानसून सत्र में 235 अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न धरे के धरे रह गए। ये सभी जनता के मुद्दों से जुड़े सवाल थे। 73 अल्पसूचित और 162 तारांकित सवालों पर चर्चा नहीं हो पाई। स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने कहा कि प्रश्न काल का यही हश्र होगा तो अगली बार से प्रश्न नहीं डालिएगा। अगली बार से प्रश्न भी घटेगा। प्रश्न घटने की पूरी जवाबदेही सदस्यों की होगी। इस बार एक भी प्रश्न का उत्तर

नहीं हुआ। आने वाले समय में इसपर विचार होगा।

जब दिल्ली में अटल मोहल्ला क्लिनिक बंद है तो भाजपा यहां क्यों हंगामा कर रही : डॉ. इरफान

सूबे के हेल्थ मिनिस्टर डॉ. इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में अटल मोहल्ला क्लिनिक बंद है, तो भाजपा यहां हंगामा क्यों कर रही है। भाजपा को दिल्ली में अटल मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहिए। इरफान अंसारी ने कहा कि जिस योजना को भाजपा ने बंद कर दिया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा दिल दिखाते हुए उस योजना को राज्य में जारी रखने का फैसला किया, ताकि सूबे के गरीबों को उनके इलाके में ही गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को क्या दिक्कत हो रही है, यह समझ से परे है। इधर, जदयू के विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर में बन रहे फलाईओवर पर जाम की समस्या से बचने के लिए वन वे की जगह दोनों तरफ से सड़क खोलने की मांग की। इसपर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है। लेकिन सरकार फिर से सभी तथ्यों को ध्यान रखकर इसपर निर्णय लेगी। वहीं कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने राज्यर के पॉलिटेक्निक कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढा रहे शिक्षकों के समायोजन की मांग की।

प्रदीप ने उठाया अडानी पावर प्लांट का मुद्दा

विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि अडानी पावर प्लांट के लिए ली गई जमीन की अनियमितता की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। अब अडानी की कलई खुलेगी। रैयतों को न्याय मिलेगा। नीरा यादव ने कहा कि कोडरमा में मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। चोर दानपेटी पर हाथ साफ कर रहे हैं। स्कूलों से कंप्यूटर सहित अन्य उपकरणों की चोरी हो रही है। पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने पांकी विधानसभा के प्रखंडों में सीओ और बीडीओ के पदस्थापन की मांग की। वहीं चंद्रदेव महतो ने 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने का सवाल उठाया। इस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की राशि पंचायतों को नहीं दी गई है। केंद्र से 1700 करोड़ की राशि नहीं मिली है। 2020 से 2023 तक का ऑडिट रिर्पोट और उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को दे दिया गया है।

हालचाल जानने के लिए पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन

मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, पारस अस्पताल में भर्ती

PHOTON NEWS RANCHI : गुरुवार को झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री

हफीजुल अंसारी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें रांची स्थित पारस एचईसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है। फिलहाल मंत्री की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। लगातार जांच की जा रही है। हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पारस अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से उनके इलाज की जानकारी ली। इसके अलावा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, परिवहन मंत्री तथा कई विधायक भी अस्पताल पहुंचे। सभी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

जम्मू-कश्मीर के गुरेज में मुठभेड़, मारे गए दो आतंकी

SRINAGAR : गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में गुरुवार को भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने 'एक्स' पर बताया कि उन्हें आतंकियों के घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके आधार पर, भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 2 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में कुलगाम जिले के अखल देवसर इलाके में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के तीन आतंकवादी मारे गए थे।

फंदे पर लटकी मिली डेड बॉडी, परिवार ने बलात्कार का लगाया आरोप

गोड्डा के मदरसे में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी

GODDA @ PTI : गुरुवार को गोड्डा जिले के एक मदरसे में 14 साल की लड़की का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। लड़की महागामा क्षेत्र में स्थित इस्लामी शिक्षण संस्थान की छात्रा थी। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि मदरसे के मौलवी ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसके कारण उसने अपनी जान दे दी। अब्दुल रज्जाक (60) नामक मौलवी ने सुबह करीब सात बजे पुलिस को घटना की जानकारी दी। महागामा के एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आजाद ने कहा, हम केवल आरोपों के आधार पर निर्णय नहीं ले रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे ताकि पता चल सके कि यह आत्महत्या थी या कुछ और। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।

पीड़ित परिवार ने किसी के खिलाफ दर्ज नहीं कराई है औपचारिक शिकायत

महागामा क्षेत्र में स्थित इस्लामी शिक्षण संस्थान की थी छात्रा

मौलवी पर यौन उत्पीड़न का आरोप

एसडीपीओ ने कहा कि पीड़ित परिवार ने अब तक किसी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लड़की के मामा ने आरोप लगाया कि मौलवी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने कहा, उसका शव कमरे से निकालकर दूसरी जगह क्यों रखा गया। गालों पर चोट के निशान हैं। हमें शक है कि मौलवी ने उसका यौन उत्पीड़न किया होगा, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। उन्होंने दावा किया कि मौलवी पर पहले भी इसी तरह के आरोप लग चुके हैं। स्थानीय कांग्रेस विधायक एवं राज्य सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने घटना की उचित जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

न्यू स्टडी कार्बन संतुलन जैसी चुनौतियों को प्रभावित कर सकते हैं माइक्रोब

पेड़ों में मौजूद अदृश्य जीव जलवायु के हालात सुधारने में सक्षम

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : जीव वैज्ञानिकों के अनुसार, वातावरण में तथा अन्य जीवों में अदृश्य जीव करोड़ों की संख्या में विद्यमान हैं। इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये माइक्रोब यानी सूक्ष्मजीव कहे जाते हैं। ये नकारात्मक ही नहीं, सकारात्मक भूमिका भी निभाते हैं। हाल में हुए एक नए रिसर्च में यह बताया गया है कि हर जीवित पेड़ में करीब एक लाख करोड़ सूक्ष्मजीव बसते हैं। हमें दिखाई न देने वाले ये नन्हे जीव न केवल पेड़ की जीवनयात्रा में सहयात्री हैं, बल्कि पृथ्वी पर कार्बन संतुलन और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा येल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 16 प्रजातियों के 150 पेड़ों पर अध्ययन के बाद किया है। आईआईटी दिल्ली के पर्यावरण विज्ञान विभाग से जुड़े प्रो. रमेश चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि यह अध्ययन हमें दिखाता है कि पेड़ केवल कार्बन सोखने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि उनके भीतर एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। भारतीय जंगलों, विशेषकर हिमालय और गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन के वनों में अगर इस प्रकार के विस्तृत शोध अध्ययन हों तो हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए समाधान मिल सकते हैं।

येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 16 प्रजातियों के 150 पेड़ों पर किया है स्पेशल रिसर्च

शोधकर्ताओं ने जीवित पेड़ों में सांस लेने वाले ऐसे नन्हे जीवों को बताया है उनका सहजीवी

- एक पेड़ के बाहरी और भीतरी हिस्से में अलग-अलग रूप में पाए गए हैं सूक्ष्मजीव
- इस अध्ययन ने यह स्पष्ट किया है कि एक सामूहिक जीवन जीते हैं सभी जीव
- इस धरती पर पेड़ और सूक्ष्मजीव मिलकर एक साझा जीवन इकाई का करते हैं निर्माण

300 गीगाटन से अधिक कार्बन को संजोकर रखते हैं धरती पर उगे सभी पेड़-पौधे

क्लाइमेट चेंज से लड़ने की नई रणनीति

जब पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया काफी हद तक उनके भीतर के सूक्ष्मजीवों से प्रभावित होती है। ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इन सूक्ष्मजीवों की भूमिका को बेहतर समझा जाए तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने की नई रणनीतियां सामने आ सकती हैं।

बाढ़ नियंत्रण में निभा सकते हैं अहम रोल

शोधकर्ताओं का कहना है कि गंगा-ब्रह्मपुत्र जो दुनिया के सबसे बड़े नदी बेसिनों में से एक है, लाखों पेड़-पौधों और घने जंगलों का घर है। इस क्षेत्र में बसे पेड़ों के भीतर के सूक्ष्मजीव न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं, बल्कि गंगा की बाढ़ नियंत्रण प्रणाली और जल प्रवाह चक्र को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह हिमालयी ग्लेशियरों से जुड़े जंगल जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील हैं। यहां मौजूद पेड़ों के भीतर का सूक्ष्मजीव संसार बर्फ के पिघलने की दर, मिट्टी में कार्बन के संग्रहण और पारिस्थितिकीय विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आईआईएससी बेंगलुरु की शोधकर्ता डॉ. प्रीति नायर का कहना है, पेड़ों के भीतर के सूक्ष्मजीवों की समझ से हम यह जान सकते हैं कि कौन-से जीव प्रजातियां पेड़ को मजबूत बनाती हैं और कौन-सी उन्हें बीमार करती हैं।

सीएम ने दिवंगत सरकारी कर्मियों के परिजनों को सौंपा एक-एक करोड़ का चेक

RANCHI : गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के परिसर में राज्य सरकार के तीन दिवंगत कर्मियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की राशि का चेक सौंपा। इन कर्मियों में कांस्टेबल अजीत कुमार, आरक्षी अनिल कुमार झा और शिक्षक सुशील कुमार मरांडी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मियों के साथ खड़ी है और उनके परिजनों को ससम्मान उनका पूरा हक-अधिकार देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विशेष बीमा कवरेज योजना के अंतर्गत दिवंगत कर्मियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। दिवंगत कर्मियों के परिजनों ने मुख्यमंत्री के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं और मुख्यमंत्री के प्रयास से उन्हें यह राशि प्राप्त हुई है, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण और बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलेगी।

आतंकियों के बारे में बताने पर मिलेंगे 50 हजार

नेपाल के रास्ते 3 आतंकी बिहार में घुसे, हाई अलर्ट

AGENCY MOTIHARI : पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन खूंखार आतंकवादियो के नेपाल के रास्ते बिहार में घुसने के खुफिया इनपुट के बाद पूरे जिला को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ही जिला के सभी थाना क्षेत्र में वाहनो की सघन जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इसकी जानकारी देते बताया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन खूंखार आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस गए हैं और वे किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उन्होने इन संदिग्धों की पहचान के लिए उनके स्केच को जारी करते हुए लोगों से इन चेहरों को पहचान करने और इस संदर्भ में कोई जानकारी मिलने पर तुरंत नजदीकी थाने से संपर्क करने या 112 डायल कर सकते हैं।

- वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बढ़ाई गई सुरक्षा, रोड शो स्थगित

BRIEF NEWS

देवघर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग

DEOGHAR : जिले में टावर चौक के पास बुधवार की देर रात करीब 2.30 बजे एक बहुमंजिला कपड़े के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपये के कपड़े व सामान जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पहले दमकल की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। आग तेजी से फैलती जा रही थी, जिसको देखते हुए दमकल की और दो गाड़ियों को बुलाया गया। दमकल कर्मियों की साढ़े तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक दुकान का पूरा सामान और सजावटी वस्तुएं जलकर राख हो चुकी थीं। इस मामले में कुंडा थाना के इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि शुरूआती जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने के असली कारण का पता चल पाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात दुकान से धुआं निकलता देख उसे बुझाने के लिए वे दौड़े। लेकिन, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। देखते ही देखते आग पूरे शोरूम में फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत दुकान मालिक और अग्निशमन विभाग को दी। तब तक काफी देर हो चुकी थी। कपड़ा शोरूम के मालिक ने बताया कि इस आग से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। कपड़ों से लेकर दुकान के सभी सजावटी सामान तक जलकर राख हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बात की जांच कराएंगे कि सिर्फ शॉर्ट सर्किट से इतनी बड़ी आग कैसे लगी।

दिगंबर जैन मंदिर में आरंभ हुआ दशलक्षण पर्व

RAMGARH : रामगढ़ में दिगम्बर जैन समाज के दोनों जिनालयों में जैन समाज के महान पर्व दशलक्षण आरंभ हो गया। दशलक्षण पर्व के पहले दिन उत्तम क्षमा धर्म की पूजा हुई। बाहर से आए हुए विद्वान निवेश शास्त्री ने उत्तम क्षमा धर्म पर प्रकाश डालते हुए कहा कि क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध न करना क्षमा है। सामर्थ्य रहने पर भी क्रोधात्पादक निंदा, अपमान, गाली गलौज और प्रतिकूल व्यवहार होने पर भी मन में कटुता न आने देना उत्तम क्षमा धर्म है। इसके पूर्व जिनालयों में पार्श्व गायक के भजनों के बीच अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न हुई। प्रथम अभिषेक का सौभाग्य रामगढ़ जिनालय में अरुणा जैन परिवार, अशोक जैन, अमित काला परिवार ,संजय जैन युग-आयुष सेठी परिवार, हीरालाल जैन परिवार, विद्या प्रकाश पद्म जैन छाबड़ा परिवार एवं जीवन मल जैन, जम्बू पाटनी परिवार तथा रांची रोड जिनालय में पाना देवी सेठी परिवार को प्राप्त हुआ था। शांतिधारा का सौभाग्य जीवन मल जम्बू परिवार एवं उषा अजमेरा परिवार को प्राप्त हुआ।

दुमका में डंपर की टक्कर से बाइक चालक की हुई मौत

रामगढ़-दुमका मुख्य मार्ग पर हुई भीषण दुर्घटना

PHOTON NEWS DUMKA : रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़-दुमका मुख्य मार्ग पर प्लस टू उच्च विद्यालय, रामगढ़ के पास गुरुवार को डंपर की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई। घटना दोपहर लगभग एक बजे की है। मृतक रुबीलाल मोहली अमड़ापहाड़ी पंचायत के पुनसिया गांव का निवासी था। घटना के बाद डंपर चालक वाहन छोड़ कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर रामगढ़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और रुबीलाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त डंपर एवं बाइक को जब्त कर लिया है। वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कमलेंद्र कुमार सिन्हा भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और परिजनों को नियमानुसार सरकारी मदद देने का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार, रुबीलाल रामगढ़ बाजार से घर लौट रहा था और इसी दौरान दुर्घटना हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रुबीलाल बाइक से काफी दूर बीच सड़क पर सिर के बल गिर गया। सिर के पिछले हिस्से में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। उसने हेलमेट नहीं पहना था।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे परिजन व अन्य ● फोटोन न्यूज

बेरमो में सर्पदंश से महिला की मौत

BERMO : बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के तिसरी गांव की सोनिया देवी (26) की गुरुवार को सर्पदंश से मौत हो गई। मृतका के पति विलास तुरी ने बताया कि बुधवार की रात करीब 11.30 बजे वह अपनी पत्नी व चार बच्चों के साथ घर में जमीन पर सो रहे थे। तभी पत्नी के हाथ में किसी जहरीले सांप ने डंस लिया। काफी देर तक इसका पता नहीं चला। इस दौरान उसकी पत्नी उठी भी थी, लेकिन फिर वह सो गई। रात दो बजे के करीब सिर दर्द, चक्कर आने सहित सांप काटने के लक्षण दिखाई देने लगे। लेकिन, सांप नहीं दिखाई देने के कारण घटना से वे बेखबर रहे। हालत गंभीर होने पर उसे स्थानीय स्तर पर झाड़-फूंक कराया गया। इस दौरान उसकी बांह में सांप काटने का निशान दिखा। इसके बाद उसे तुरंत गोमिया के आईईएल अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने हालत गंभीर देख उसे रेफर कर दिया। परिजन सोनिया देवी को बोकारो ले जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सोनिया देवी अपने पीछे दो पुत्र सन्नी कुमार, विक्की कुमार और दो पुत्री पूजा कुमारी व नंदनी कुमारी छोड़ गई है। पति विलास तुरी ने बताया कि काफी खोजबीन के बाद भी सांप का कोई पता नहीं चल सका। घटना की सूचना पर पहुंची चतरोचट्टी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल, तेनुघाट भेज दिया है। इधर, पंसस यशवंत कुमार व पूर्व पंसस बुधन रविदास ने प्रशासन को घटना की सूचना देते हुए पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है।

करम डाली लेकर दामोदर नदी में उतरी पांच बच्चियां बहीं

DHANBAD : झरिया स्थित सुदामडीह थाना क्षेत्र में बाई क्वार्टर छठ घाट पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। करमा पूजा के अवसर पर दामोदर नदी में स्नान करने गईं पांच बच्चियां अचानक गहरे पानी में चली गईं और तेज बहाव में बह गईं। हादसे की सूचना मिलते ही सुदामडीह पुलिस और गोताखोरों की एक विशेष टीम तुरंत मौके पर पहुंची। काफी खोजबीन के बाद रुक्मिणी कुमारी (12) का शव बिरसा पुल के पास से बरामद कर लिया गया। वहीं, दूसरी लापता बच्ची संध्या कुमारी की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि, स्थानीय लोगों और मछुआरों ने तुरंत साहस दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया। उनके त्वरित प्रयासों से तीन बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं, दो बच्चियां नदी की धार में बह गईं। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चियों को नदी की तेज धारा और गहरे पानी का अंदाजा नहीं लगा, जिसके कारण वे सभी संतुलन खो बैठीं। देखते ही देखते घाट पर अफरातफरी का माहौल हो गया।

विश्वविद्यालय विधेयक के खिलाफ अभाविप ने निकाली आक्रोश यात्रा

बिल की प्रति जलाकर किया विरोध प्रदर्शन, वापस लेने की मांग

AGENCY RAMGARH : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने झारखंड सरकार की ओर से पारित राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 का विरोध शुरू किया है। रामगढ़ कॉलेज के समीप गुरुवार को संगठन के लोगों ने विधेयक की प्रति जलाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। अभाविप के सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रति कुलपति, वित्तीय सलाहकार, परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्ति के अधिकार को राज्यपाल से हटाकर राज्य सरकार को देने का प्रावधान गलत है। यह विधेयक न केवल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर प्रहार है, बल्कि एक संवैधानिक पद के अधिकारों में सीधा हस्तक्षेप है। जिला संयोजक सुदीप महतो ने कहा अभाविप इस विधेयक के अंतर्गत गठित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का स्वागत करती है। लेकिन इस विधेयक के अंतर्गत केवल शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी की नियुक्ति एवं प्रमोशन का कार्य होना चाहिए, ना कि कुलपति, प्रति कुलपति की नियुक्ति का अधिकार होना चाहिए। सरकार जैक, जेपीएससी, जेएसएससी जैसी शैक्षणिक एवं नियुक्ति संस्थाओं के संचालन में लगातार विफल रही है। नगर मंत्री यशपाल महतो ने कहा सरकार इस विधेयक के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से कैंपस में होने वाले छात्र संघ चुनाव पर भी प्रहार कर रही है।

वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निगलना चाह रही है। विश्वविद्यालय में छात्र संघ के लिए अलग से चुनाव न कराना यह दशार्ता है कि यह सरकार छात्र संघ के माध्यम से उभरने वाले नए राजनीतिक, सामाजिक विमर्श और विद्यार्थी नेतृत्व को कुचलना चाह रही है।

रामगढ़ कॉलेज के पास प्रदर्शन करते छात्र

हाथियों ने घर पर बोला धावा, मलबे में दबकर मां-बेटे की हो गई मौत

KHUNTI : जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बकसपुर गांव में बुधवार की रात लगभग एक बजे हाथियों ने एक घर पर धावा बोल दिया। घर ध्वस्त होने से उसके मलबे में दबकर मां और उसके बेटे की मौत हो गई। मृतकों में एतवारी बारला (28) और पुत्र तुलसी बारला (4) शामिल हैं। मां बेटे की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलने पर तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया ने झामुमो कार्यकताओं को बकसपुर जाने का निर्देश दिया। झामुमो के पदाधिकारियों ने गांव में पहुंच कर घटनास्थल का जायजा लिया और वन विभाग को बुलाकर तत्काल मुआवजा राशि दिलाई और गाड़ी कर पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को सदर अस्पताल खूंटी भेजवाया। मौके पर झामुमो नेताओ ने शोक व्यक्त किया और दिगवंत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

हाई स्कूल के क्लर्क के घर से हुई चार लाख की चोरी

घर में बिखरे सामान ● फोटोन न्यूज

PALAMU : सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द में बुधवार की रात गिरेंद्र शुक्ला के घर चोरी हो गई। गिरेंद्र शुक्ला ब्राह्मण उच्च विद्यालय में क्लर्क हैं। चोरों ने नकद और गहनों समेत लगभग चार लाख रुपये की चोरी कर ली। सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि बुधवार की रात घर के सभी सदस्य सो गए थे। सुबह में जब वे उठे तो देखा कि घर के एक कमरे का दरवाजा खुला है और कमरे में बक्से व सामान बिखरे पड़े हैं। गिरेंद्र शुक्ला की पत्नी ने हाल ही में तीज मनाने के बाद अपने गहनों को उसी कमरे में रखा था। हैरानी की बात यह है कि गहने और नकदी घर के सबसे अंतिम कमरे में रखे थे। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि चोरों को पूरी जानकारी थी। घरवालों का मानना है कि चोरी में स्थानीय लोग शामिल हो सकते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर दर्ज हो प्राथमिकी : सांसद

LOHARDAGA : लोहरदगा जिला परिषद सभाकक्ष में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला विकास समन्वय और दिशा की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के उपायुक्त डॉ कुमार ताराचंद,एसपी सादीक अनवर रिजवी सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जिले के स्वास्थ्य, सड़क, आपूर्ति, आवास योजना, बिजली आपूर्ति, शिक्षा सहित सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही जिले के अधिकारियों को कई निर्देश दिये गये। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि जो भी सरकार की योजनाएं आम लोगो के लिए आती है उसे धरातल पर उतार कर आमलोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान सांसद सुखदेव भगत ने जिले में चल रहे करीब 32 विभागों के कार्यों को बारी बारी से समीक्षा कर विकास योजनाओं का हाल जाना और कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के कार्यों में एफआई आर और शोकॉज करने का निर्देश भी दिया है। दिशा की बैठक के दौरान कई विभागों के अधूरे कार्य और उदासीन रवैये को लेकर सांसद सुखदेव भगत ने अधिकारियों की जमकर फटकार भी लगाई है।

झारखंड के दो मंत्रियों को धमकी देने वाला युवक पटना से गिरफ्तार

AGENCY GIRIDIH : राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी दिये जाने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरिडीह पुलिस सक्रिय हुई और देर शाम को युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त जानकारी एसपी डॉ विमल कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि युवक को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। बताया कि बुधवार को सोशल मीडिया पर गिरिडीह के बाभनटोली - राजेंद्र नगर के रहने वाले एक युवक अंकित कुमार मिश्रा का वीडियो सामने आया था। जिसमें युवक ने मंत्री सुदिव्य कुमार और मंत्री इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो एसपी डॉ. बिमल कुमार ने तुरन्त इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया। टीम में सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, साइबर डीएसपी आबिद खान, मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन, साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत को शामिल करते हुए छापेमारी की गई। बताया गया कि टीम को आरोपित युवक का लोकेशन बिहार मिला। इसके बाद साइबर डीएसपी के साथ साइबर थानेदार और टेक्निकल टीम पटना पहुंची जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार ने युवक की गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगे जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता है कि इन युवाओं का संबंध किसी बड़े गैंगस्टर से है।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी व मामले की जानकारी देते एसपी डॉ. बिमल कुमार

फंदे पर लटकी मिली महिला की लाश

PALAMU : चैनपुर थाना क्षेत्र के अवसाने गांव निवासी प्रेम प्रकाश की पत्नी रोशनी कुमारी (20) की बुधवार रात फंदे पर लटकी लाश मिली। परिजनों के अनुसार, उसने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। रोशनी कुमारी की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती थी। इसके कारण वह काफी परेशान और चिंतित रहती थी। हालांकि, फंदे से उतार कर परिजन मेदनीराय मेडिकल कालेज-अस्पताल ले गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने रोशनी कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस चौकी की एएसआई सुशीला तियू गुरुवार की सुबह अस्पताल पहुंचीं और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही चैनपुर थाना की पुलिस घटना से संबंधित मामले की छानबीन में जुट गई है।

होमगार्ड जवानों के पीएफ व रिटायरमेंट बेनिफिट का रास्ता हो गया साफ

धनबाद में होगा राज्यस्तरीय सम्मेलन, निकलेगा विजय जुलूस

PHOTON NEWS DHANBAD : होमगार्ड जवानों के पीएफ व रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। एक-दो माह में ये दोनों लाभ जवानों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उम्मीद है कि शुक्रवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद इस मामले में आदेश जारी हो जाए। इस मामले पर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि जवानों को भविष्य निधि और एकमुश्त सेवानिवृत्ति लाभ देने के मामले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब की मांग की थी। इसी पर सरकार ने श्रम विभाग से मंतव्य मांगा था। विभाग ने भी इस मामले पर अपनी सहमति जता दी है और राज्य सरकार ने भी दोनों मांगों पर सकारात्मक जवाब दिया है।

फाइल फोटो

विजय जुलूस की हो रही तैयारी

रवि मुखर्जी ने बताया कि राज्य के होमगार्ड जवान काफी लंबे समय से भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 1.5 लाख रुपये एकमुश्त भुगतान की मांग करते आ रहे हैं। अब यह पूरा होने वाला है। इसी को लेकर सितंबर में विजय जुलूस निकालने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही राज्य सम्मेलन भी होगा। ये दोनों आयोजन धनबाद में होंगे।

नीरज सिंह हत्याकांड | संजीव सिंह ने हाईकोर्ट में लगाई थी न्याय की गुहार

आईओ व एपीपी को नोटिस जारी करने का आदेश

PHOTON NEWS DHANBAD : नीरज हत्याकांड में अदालत से बरी हुए झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के आवेदन पर अदालत ने बड़ा आदेश पारित किया है। संजीव सिंह के अधिवक्ता मो. जावेद ने बताया कि धनबाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने कांड के अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी एवं मुकदमे का संचालन करने वाले अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय के विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इस पर 8 सितंबर को सुनवाई होनी है।

संजीव सिंह ने 20 अगस्त को अदालत में अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी व अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय के विरुद्ध शिकायतवाद दर्ज कराकर जांच और कार्रवाई की गुहार लगाई थी। अधिवक्ता मो. जावेद ने बताया कि

पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह

पूर्व विधायक संजीव सिंह (फाइल फोटो)

तीनों के विरुद्ध कोर्ट में धारा 230 व 231 के तहत मुकदमा चलाने की प्रार्थना की गई थी। आवेदन में कहा गया है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध, जिसमें दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा हो सकती है। संजीव सिंह को सजा दिलाने के लिए अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी ,अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने सूचक अभिषेक सिंह के साथ मिलकर फर्जी सबूत तैयार किया और उसे अदालत में पेश किया गया। अनुसंधानकर्ता ने आदित्य राज के मोबाइल का फर्जी सीडीआर बनाया, ताकि उसे घटनास्थल पर दिखाया जा सके। इस बात की फर्जी इंट्री केस डायरी में की और कोर्ट में भी झूठा बयान दिया, ताकि संजीव सिंह को सजा मिल सके। यही नहीं, 13 अगस्त को अपर लोक अभियोजक ने सूचक के साथ मिलकर संजीव सिंह के मोबाइल का फर्जी दो पन्ने का सीडीआर अदालत में दायर किया और बताया कि यह प्रदर्श 16/4 है, जबकि प्रदर्श 16/4 वह दस्तावेज था, जिसे नोडल आफिसर द्वारा कोर्ट में साबित किया गया था। उसमें नोडल आफिसर आनंद माधव मिश्रा ने कहा था कि 15 मार्च 2017 से 23 मार्च 2017 तक आदित्य राज का लोकेशन गिरिडीह था।

अधिवक्ता मो. जावेद ने कहा कि अभियोजक का काम कभी भी किसी अभियुक्त को सजा दिलाने का नहीं होता, बल्कि न्याय व्यवस्था में सहयोग करना होता है। अदालत के फैसले से भी यह साबित हुआ कि आदित्य राज को फर्जी तरीके से घटनास्थल का चश्मदीद गवाह बताया गया था। उसका फर्जी काल डिटेल्ट दिया गया था।

विरोधाभासी बयानों से चाकूबाजी की गुत्थी सुलझाने में उलझ गई पुलिस

छह माह पूर्व पति-पत्नी के बीच महिला थाना में कराई गई थी सुलह

PHOTON NEWS DUMKA : गोपीकांदर थाना क्षेत्र के टेसाफुली में गोड्डा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मखनी मोहली टोला की खुशबू कुमारी बुधवार को खून से लथपथ हालत में मिली थी। उस पर मंगलवार की रात चाकू से जानलेवा हमला करने की बात सामने आई थी। इस मामले में गुरुवार शाम तक पुलिस कुछ भी स्पष्ट बता पाने की स्थिति में नहीं थी। खुशबू के बयान पर ही पुलिस अनुसंधान कर रही है। गुरुवार को गोपीकांदर थाना के एसआई मनोज सोरेन को बयान दर्ज करने के लिए फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इधर गुरुवार को अस्पताल में इलाजरत युवती का सीटी स्कैन और एक्सरे कराया गया। पीड़ित शारीरिक रूप से अब भी उठने-बैठने में असमर्थ है। ऐसे में एसआई बिना बयान लिए लौट गए।

वीरेन को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही छापेमारी

चाकूबाजी की घटना के बाद खुशबू का पति विरेन महतो फरार बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टया पुलिस इस मामले में विरेन की भूमिका को भी संदिग्ध निगाह से देखकर जांच को आगे बढ़ा रही है। उसे ढूंढने के लिए छापेमारी कर रही है। चर्चा तो यह भी है कि घटना वाले दिन मौके पर एक नहीं दो लोग थे। बहरहाल, इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।

मां ने कहा- भगवान का शुक्र है बेटी जिंदा बच गई

पीड़िता खुशबू की मां हेमंती देवी, मामा मंटू महतो और हेमंत महतो गुरुवार को फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में थे। पुलिस ने इन सभी से पूछताछ की। पीड़िता के पति वीरेन महतो के बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश की। वहीं हेमंती देवी अपनी बेटी की गंभीर स्थिति को देखकर काफी सहमी हुई है। कहा कि भगवान का शुक्र है कि बेटी जिंदा बच गई है। कहा कि चार बेटियों में खुशबू कुमारी सबसे बड़ी है। उसकी शादी तीन वर्ष पहले गोड्डा थाना क्षेत्र के जीतपुर निवासी वीरेन महतो से कराई थी। एक वर्ष से दोनों में विवाद चल रहा था। छह माह पहले ही गोड्डा महिला थाना में सुलह कराया गया था। दामाद वीरेन महतो बाहर काम करने चला गया था। इसलिए बेटी मायका मखनी मोहली टोला में रह रही थी। हेमंती देवी ने कहा कि बीते मंगलवार को वह अपने पिता के घर डहरडांगी गई थी। मखनी स्थित घर में खुशबू और दो छोटी बहनों के अलावा उसका पति था। उसका पति मानसिक रूप से बीमार है। मंगलवार को तीज था, इसलिए मोहल्ले के लोगों ने खुशबू को शाम छह बजे तक सामान्य अवस्था में घर की तरफ देखा था। हालांकि शाम ढलने के बाद खुशबू के पति को किसी ने उसके घर आते नहीं देखा। उसकी बेटी पर जिसने भी जानलेवा हमला किया है, पुलिस जल्द से जल्द पकड़ कर कड़ी सजा दे। इधर मामा मंटू महतो ने कहा कि उन्हें भांजी खुशबू ने कहा था कि वह वीरेन के कहने पर ही रात में घूमने निकली थी। जाहिर है खुशबू के बयान और परिजनों के विरोधाभासी बयानों के बीच पुलिस की जांच आगे बढ़ने वाली है।

बहुत शीघ्र घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस खुशबू के पति वीरेन महतो की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है।
– सुमित कुमार, थाना प्रभारी, गोपीकांदर, दुमका

झारखंड में आठ आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल की तादाद में हो रहा इजाफा

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में दुनियाके आतंकी संगठनों से जुड़े स्लीपर सेल की तादाद में इजाफा हो रहा है। राज्य के सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, आठ प्रमुख आतंकी संगठनों- इंडियन मुजाहिद्दीन, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी), लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस), इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस), पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई), जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) और हिज्ब उत-तहरीर से जुड़े स्लीपर सेल झारखंड में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इन आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल मुख्य रूप से झारखंड के नौ जिलों में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिनमें रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, गोड्डा, धनबाद, और गिरिडीह शामिल हैं। इन इलाकों को आतंकी संगठनों ने न केवल अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया है, बल्कि यहां वे अपनी अगली साजिशों की योजना भी तैयार कर रहे हैं। उनकी गतिविधियों और साजिशों को लेकर हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं और उन्हें सफल करने के लिए कमर कसी हुई हैं।

रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, लोहरदगा, पाकुड़, गोड्डा, धनबाद और गिरिडीह में सक्रियता अधिक

मुख्य रूप से राज्य के नौ जिलों में तेजी से गतिविधियों को दिया जा रहा अंजाम, प्रशासन भी अलर्ट

- हिज्ब-उत-तहरीर के चार संदिग्ध आतंकियों को धनबाद से किया गया है गिरफ्तार
- एटीएस ने 26 अप्रैल 2025 को वासेपुर में छापेमारी कर गुलफाम, आयान जावेद, शबनम और मोहम्मद शाहजाद को किया था अरेस्ट
- शबनम की निशानदेही पर इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा अम्मार यासर भी हुआ था गिरफ्तार

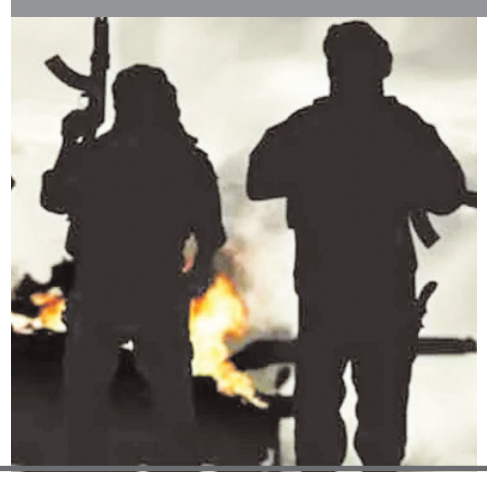

एक्यूआईएस का नेतृत्व कर रहा था इश्तियाक

झारखंड एटीएस ने 26 अप्रैल 2025 को धनबाद के वासेपुर में छापेमारी कर हिज्ब उत-तहरीर के चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इनमें गुलफाम हसन, आयान जावेद, शबनम परवीन और मोहम्मद शहजाद आलम शामिल हैं। बाद में शबनम की निशानदेही पर पांचवां संदिग्ध अम्मार यासर को भी पकड़ा गया, जो पहले इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा था। बता दें कि दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने 22 अगस्त 2024 को रांची के चान्हो और बरियातू से चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिनमें रेडियोलॉजिस्ट डॉ. इश्तियाक अहमद प्रमुख था। जांच में खुलासा हुआ था कि इश्तियाक अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस) के झारखंड मॉड्यूल का नेतृत्व कर रहा था। उसका मकसद देश में खिलाफत की स्थापना करना और गंभीर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। झारखंड एटीएस ने आठ नवंबर 2023 को गोड्डा व हजारीबाग से आतंकी संगठन आईएसआईएस के सक्रिय दो आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आतंकियों में आरिज हसनैन (गोड्डा के रहमतनगर महमूदनगर असनबनी निवासी) और नसीम (हजारीबाग के पेलावल ओपी स्थित महतो टोला निवासी) शामिल था। आरिज हसनैन और नसीम पाकिस्तान व अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। इनका लक्ष्य फलिस्तीन जाकर फिदायीन हमला कर मस्जिद-ए-अल अक्सा को यहूदियों से आजाद कराना था। इससे पहले 2 अक्टूबर 2023 को देश में आईएसआईएस नेटवर्क खंगाल रही एनआईए के मोस्ट वांटेड तीन आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था।

पाकुड़ बन रहा आतंक का नया गढ़

झारखंड एटीएस की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 285 लोग देश-विदेश में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े पाए गए हैं। जिन 285 संदिग्धों पर झारखंड पुलिस की नजर है, उनमें से सबसे ज्यादा 113 संदिग्ध अकेले पाकुड़ जिले से हैं, जो आतंकवाद का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। एटीएस एसपी ऋषभ जा का कहना है कि एक रिपोर्ट में इन संदिग्धों की पूरी जानकारी एकत्र की गई है, जिसमें उनके नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं। इनमें से कई व्यक्ति पहले आतंकी घटनाओं में संलिप्तता के आरोप में जेल जा चुके हैं या जमानत पर रिहा हुए हैं। एटीएस ने इनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के लिए

285 संदिग्धों पर रखी जा रही नजर

झारखंड जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, आज आतंकी संगठनों की गहरी पैठ के कारण सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। झारखंड एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) की एक ताजा खुफिया रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि राज्य के 285 लोग देश और विदेश में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। जिन 285 संदिग्धों पर झारखंड पुलिस की नजर है उनमे से सबसे अधिक 113 संदिग्ध पाकुड़ जिले से हैं, जो आतंकवाद के एक नए गढ़ के रूप में उभर रहा है। यह खुलासा न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चिंताजनक है, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है। एटीएस की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में 285 लोग विभिन्न प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।

BRIEF NEWS

राष्ट्रीय लोक अदालत 13 को, पक्षकारों को भेजा जा रहा नोटिस

RANCHI : राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को सिविल कोर्ट रांची में किया जाएगा। झालसा के निर्देश पर न्यायायुक्त सह डालसा अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा-एक के मार्गदर्शन में डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर की देखरेख में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायिक पदाधिकारियों, न्यायिक दंडाधिकारियों, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों, नोडल पुलिस पदाधिकारियों एवं पीएलवी के साथ बैठकें की जा चुकी है। सभी बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। डालसा सचिव रवि भास्कर ने गुरुवार को कहा कि किसी भी न्यायालय में लंबित सुलहनीय मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझाया जाएगा।

झारखंड जगुआर के जवान को सांप ने काटा, स्थिति गंभीर

RANCHI : झारखंड जगुआर के एक जवान को जहरीले सांप ने काट लिया। जिसके बाद उन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। जवान की पहचान मिथिलेश राम के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, घटना झारखंड जगुआर के कैंप में देर रात लगभग 12 बजे की है। जवान को सांप काटने के बाद आनन-फानन में रिम्स लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया।

स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों के लिए खतरा बन चुके हैं कुत्ते

राजधानी के कई इलाकों में बढ़ गया है आवारा कुत्तों का आतंक

PHOTON NEWS RANCHI : रांची में आवारा कुत्तों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक भी बढ़ा हुआ है। कुत्तों के झुंड अब आम जनता के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि नगर निगम के पास यह जानकारी नहीं है कि रांची में कुल कितने कुत्ते हैं। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले छह सालों से कुत्तों की कोई गणना या सर्वे नहीं हुआ है, जिससे वास्तविक संख्या का पता लगाना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह-शाम सड़कों पर दौड़ते और झुंड में घेरते कुत्ते डर का कारण बन रहे हैं। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों के लिए ये कुत्ते खतरा बन चुके हैं। कई बार ये लोगों को दौड़ा रहे हैं, जिससे कि दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। कुछ लोग कुत्तों की वजह से चोटिल भी हो रहे है। नगर निगम ने कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए कैचिंग एंड स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू तो की थी, लेकिन यह भी धीमी गति से चल रही है। इस काम की जिम्मेदारी नगर निगम ने होप एंड एनिमल ट्रस्ट नामक एनजीओ को सौंपी है। संस्था के पास संसाधनों और कर्मचारियों की कमी के कारण यह कार्य पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन एक दर्जन से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी नहीं की जा सकती, जबकि वास्तविक जरूरत इससे कहीं अधिक है। वहीं, शहर के प्रमुख इलाकों जैसे कि कोकर, डोरंडा, बरियातू, हरमू और कांके जैसे इलाकों में हर गली में दर्जनों आवारा कुत्ते देखने को मिलते हैं।

शहर में कुत्तों की तादाद की रांची नगर निगम को जानकारी नहीं

- पिछले 6 सालों से शहर में नहीं की गई है गणना
- कैचिंग एंड स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया भी पड़ गई है धीमी
- होप एंड एनिमल ट्रस्ट को नगर निगम ने दे रखा है काम
- कोकर, डोरंडा, बरियातू, हरमू और कांके जैसे इलाकों में हर गली में देखने को मिलते हैं दर्जनों कुत्ते

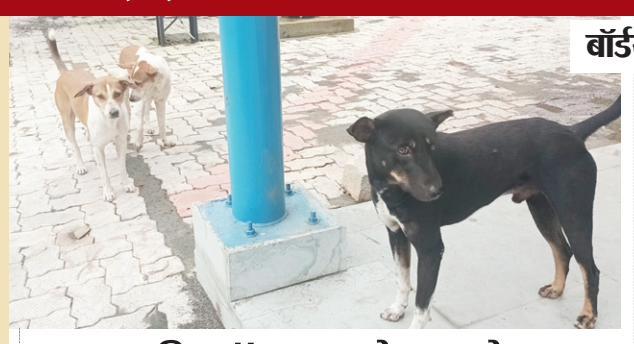

हर दिन डॉग बाइट के 200 केस

राजधानी में हर दिन 200 के करीब डॉग बाइट के केस आ रहे हैं। जिससे ये तो साफ है कि कुत्तों का शहर में आतंक बढ़ रहा है। कुत्ते के काटने पर लोगों को एंटी रेबीज की 5 डोज लेनी होती है। इस वजह से लोग भी परेशान हैं। वैक्सीन लगाने के लिए भी लोगों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।

बॉर्डर वाले एरिया का बहाना

नगर निगम की असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉ. किरण कुमारी का कहना है कि जल्द ही पूरे शहर में एक व्यापक सर्वे कराया जाएगा, ताकि कुत्तों की वास्तविक संख्या का आंकलन किया जा सके। इसके आधार पर नसबंदी, टीकाकरण और पुनर्वास की योजनाओं को गति दी जाएगी। साथ ही कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुत्तों की आबादी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र के बॉर्डर वाले इलाके में बाहर के कुत्ते आकर आबादी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्य योजना बनाई जा रही है, लेकिन सर्वे और संसाधनों की कमी है। फिलहाल रेंट पर गाड़ी लेने का निर्देश नगर प्रशासक ने दिया है।

NEWS BOX

सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला एनएचआरसी में दर्ज, आजसू ने की सीबीआई जांच की मांग

RANCHI : सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला दिल्ली की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) तक पहुंच गया है। आयोग ने आजसू के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता के आवेदन पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आजसू पार्टी ने इस घटना को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार, आजसू ने घटना के बाद लगातार 10 दिनों तक तथ्य जुटाए और 21 अगस्त को आयोग को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके आधार पर आयोग ने 27 अगस्त को केस संख्या 1031/34/9/2025 के तहत मामला दर्ज कर लिया। संजय मेहता ने कहा कि सूर्या हांसदा मुख्याधारा से जुड़े व्यक्ति थे और चार बार चुनाव भी लड़ चुके थे। किसी भी मामले में अदालत ने उसे वांटेड घोषित नहीं किया था। ऐसे व्यक्ति की पुलिस एनकाउंटर में मौत होना बेहद गंभीर मामला है। मेहता ने आगे कहा कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। सजा देने का अधिकार अदालत का है, पुलिस का नहीं। आजसू पार्टी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, ताकि सच सबके सामने आए।

मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनोज पुनमिया को झारखंड हाईकोर्ट से झटका

RANCHI : पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी मनोज पुनमिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया है। इससे पहले रांची पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने मनोज पुनमिया के खिलाफ आरोप गठित कर दिया था और डिस्चार्ज याचिका भी खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उसने वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई। मनोज पुनमिया की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने बहस की। क्रिमिनल रिवीजन खारिज होने के बाद अब मनोज पुनमिया के विरुद्ध ट्रायल जारी रहेगा।

मगध-आम्रपाली कोल परियोजना में लेवी वसूलने वाले की जमानत याचिका खारिज

RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट ने मगध-आम्रपाली कोल परियोजना में लेवी वसूलने के आरोपी प्रदीप राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रदीप राम के पास से लेवी के रूप में वसूले गये 57.57 लाख रुपये नकद जब्त किये गये थे। ईडी ने अम्रपाली परियोजना में त्रितीय प्रतुति कमेटी (टीपीसी) द्वारा लेवी वसूलने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को इसीआईआर के रूप में दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। इसमें यह पाया गया था कि प्रदीप राम टीपीसी के लिए काम करता था। प्रदीप राम कोल परियोजना में लगे ठेकेदारों सहित अन्य से टीपीसी के लिए लेवी वसूलता था। साथ ही वह लेवी की रकम को शेल कंपनियों के सहारे बैंकिंग चैनल में डालता था। यह हथकंडा अपना कर वह लेवी के पैसों को जायज कमाई साबित करने की कोशिश करता था। ईडी ने अम्रपाली-मगध परियोजना में लेवी वसूली के इस मामले में वर्ष 2016 में इसीआईआर दर्ज किया था। इसके बाद प्रदीप राम को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रदीप राम ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से उसके पास से मिली राशि को जायज आमदनी बताने की कोशिश की गयी थी। वहीं ईडी की ओर से सुनवाई के दौरान प्रदीप राम द्वारा लेवी वसूलने और उसकी लॉन्ड्रिंग करने की बात कही गयी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद प्रदीप राम की जमानत याचिका रद्द कर दी।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के पूरे हुए 11 वर्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी बधाई

RANCHI : नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के 11 सफल वर्षों पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल बैंक खाते खोलने तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान और नारी सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बनकर एक नई क्रांति लेकर आई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौर में स्थिति ऐसी थी कि दिल्ली से भेजा गया 1 रुपया गरीब तक पहुंचते-पहुंचते मात्र 10 पैसे रह जाता था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुलवाकर डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया। बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है।

दो माह में 2,56,683 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई

बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से रोजाना वसूला जा रहा 42.78 लाख रुपये जुर्माना

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों विशेष रूप से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में हर दिन बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से औसतन 42.78 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। झारखंड पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो महीने में राज्य के 24 जिलों में 2,56,683 दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़ा गया है। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले 4,278 चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके हिसाब से एक दिन में 42.78 लाख रुपये और दो महीनों में 25.66 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, हजारीबाग और रांची में सबसे ज्यादा चालान काटे गए हैं। जबकि कई अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है।

हजारीबाग और रांची में सबसे ज्यादा काटे गए चालान

- 60 दिनों में 25.66 करोड़ रुपये का वसूला गया जुर्माना
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत- बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये तक की लगाई जा सकती है फाइन

कमल भूषण हत्याकांड : गृह विभाग के सचिव से शिकायत, न्याय की गुहार

सरकारी गवाह से जेलकर्मियों ने की मारपीट चार हजार छीन डिग्री पैक करने का आरोप

PHOTON NEWS RANCHI : चर्चित व्यवसायी कमल भूषण हत्याकांड में सरकारी गवाह मुनव्वर अफाक से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में जेल कर्मियों द्वारा मारपीट व अवैध वसूली का गंभीर आरोप सामने आया है। इस मामले में मुनव्वर के पिता कांटाटोली के रहने वाले अफाक अहमद ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है।

क्या लिखा है पत्र में : पत्र में आरोप लगाया गया है कि उनका पुत्र जो लंबे समय से न्यूरो और गैस्ट्रो संबंधी बीमारियों से पीड़ित है। उसे इलाज के लिए 26 अगस्त को रिम्स ले जाया गया था। वापस लौटने पर जेल के छोटा जमादार उदय करमाली और सुरक्षाकर्मी रमेश राम ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और जरूरी खर्च के लिए दिए गए 4,000 रुपये जबरन छीन लिए। इतना ही नहीं उसे सजा स्वरूप पगला सेल में डिग्री पैक कर दिया गया। जहां न उसे भोजन मिल रहा है और न ही दवाइयां। पिता ने ये भी आरोप लगाया है कि जेल कर्मियों द्वारा उससे 1 लाख की मांग की जा रही है, नहीं देने पर दूसरी जेल में स्थानांतरण की धमकी दी गई है। अफाक ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुनव्वर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, उसे चक्कर आना और नाक से खून बहना जैसी गंभीर समस्याएं हो रही हैं।

न भोजन मिल रहा, न दवाइयां, मांगे जा रहे ₹1 लाख

- दूसरी जेल में स्थानांतरण की दी गई है धमकी
- जेल के छोटा जमादार उदय करमाली और सुरक्षाकर्मी रमेश राम पर है गंभीर आरोप

सोशल मीडिया का असर | आईपीएस से लेकर सिपाही स्तर के कर्मियों में परवान चढ़ रही रुचि

झारखंड पुलिस में रील्स बनाने का बढ़ता जा रहा क्रेज

PHOTON NEWS RANCHI : आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जहां आम लोग से लेकर अफसर तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की होड़ में दिख रहे हैं। समाज के सभी वर्गों के लोग किसी न किसी रूप में इस पर सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। हल्के समय में झारखंड में भी पुलिस महकमे में सोशल मीडिया रील्स बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आईपीएस, एएसपी, डीएसपी, दरोगा से लेकर सिपाही स्तर तक के कर्मी पुलिस की वर्दी में रील्स बनाकर इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर रहे हैं। अक्सर ये रील्स काम करने की जगह यानी थाने या फील्ड ड्यूटी के दौरान ही शूट की जाती हैं, जिससे न सिर्फ वर्दी की मयार्दा बल्कि पुलिस की पेशेवर छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं।

अक्सर काम करने की जगह यानी थाने या फील्ड ड्यूटी के दौरान बनाई जाती हैं रील्स

वर्दी की मर्यादा और पुलिस की पेशेवर छवि पर समाज में लोग उठाने लगे हैं सवाल

- कई राज्यों में पुलिस विभाग ने अपने कर्मियों के लिए बनाई है सोशल मीडिया पॉलिसी
- विभागीय आचरण संबंधी नियमों के खिलाफ है वर्दी पहनकर रील्स बनाना और शेयर करना

पर्सनल अकाउंट का न करें अनावश्यक इस्तेमाल

झारखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में यह भी निर्देश दिया गया है कि कार्यालय समय के दौरान कर्मचारी अनावश्यक रूप से अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल न करें। कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल से संबंधित शिकायतों या मुद्दों को वीडियो, फोटो या किसी अन्य रूप में सोशल मीडिया पर साझा करने से मना किया गया है।

वर्दी की गरिमा को बनाए रखना जरूरी

देश के कई राज्यों में पुलिस विभाग ने अपने कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई है, ताकि वदीधारी कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के अनुचित उपयोग को रोका जा सके। कारण साफ है कि वर्दी पहनकर रील्स बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना विभागीय आचरण संबंधी नियमों के खिलाफ मानी जाती है। इससे वर्दी की गरिमा और पुलिस की छवि दोनों प्रभावित हो सकती है। झारखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल पर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन 4 फरवरी 2025 को कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई है।

'आदि कर्मयोगी अभियान' से 545 गांवों में हुई विकास की नई शुरुआत

जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ना है उद्देश्य : सौरभ भुवनिया

PHOTON NEWS RANCHI : जिला प्रशासन ने आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत 545 अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों के समग्र विकास हेतु जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्घाटन उप-विकास आयुक्त सौरभ भुवनिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। अभियान का उद्देश्य शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य और सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थान के माध्यम से जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ना है। सौरभ भुवनिया ने कहा, यह अभियान उत्तरदायी शासन और सामुदायिक विकास का मॉडल है, जिससे हर ग्राम आत्मनिर्भर बन सकेगा।

उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आईटीडीए निदेशक संजय भगत, डीआरडीए निदेशक सुदर्शन मुर्मू और शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, समाज कल्याण पदाधिकारी सुरभि सिंह, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि व स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया। उप-विकास आयुक्त ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक जनजातीय बाहुल्य गांव आत्मनिर्भर बने, और वहां के निवासियों को बेहतर अवसर मिलें। उन्होंने यह भी बताया कि इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों, स्थानीय संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

समाचार सार

एमबीएनएस के छात्रों ने दिखाई प्रतिभा

JAMSHEDPUR : रेड एफएम तशनबाज के तत्वावधान में गुरुवार को एमबीएनएस ग्रुप के संस्थान में भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें नृत्य, गायन सहित अन्य प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रीति कुमारी कुम्भाकर, शख्या कुमारी व अशोक प्रमाणिक ने अपने प्रदर्शन से खूब प्रशंसा प्राप्त की।

सोना देवी विश्वविद्यालय में फ्रेशर्स वीक शुरू

GHATSILA : सोना देवी विश्वविद्यालय में फ्रेशर्स वीक मनाया जा रहा है। पहले दिन गुरुवार को कुलपति डॉ. जेपी मिश्रा ने विश्वविद्यालय परिसर में बने वातानुकूलित ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इसमें करीब 200 लोगों की बैठने की क्षमता है। कुलाधिपति प्रभाकर सिंह ने स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों की उपस्थिति को यादगार बताया। 28 अगस्त से 6 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई आयोजन होंगे।

ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणेश पूजा पंडाल

GHATSILA : पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड में धूमधाम से गणेश पूजा हो रही है। शहरी क्षेत्र में कई भव्य पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें व्हाइट इलेवन क्लब फुटबॉल ग्राउंड मऊभंडार में सिल्वर जुबिली मना रहा है। एवरग्रीन क्लब लालडीह ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर भव्य पंडाल बनाया है। पूरा पंडाल सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। पंडाल के अंदर कई आकर्षक मिसाइल बनाए गए है। इससे श्रद्धालुओं की भीड़ की खिंची चली आ रही है। यहां गुरुवार को भोग वितरण किया गया। इसके साथ ही दाहीगोड़ा सहित अन्य क्षेत्रों में पंडाल बनाकर पूजा की जा रही है। लालडीह पूजा पंडाल में लगातार चार दिन तक धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं।

पुलिस ने 19 किलो डोडा ले जा रहे व्यक्ति को दबोचा

BAHRAGORA : पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में करकट्टा गांव स्थित एनएच-18 पर बुधवार शाम पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दादा होटल के पास बाइक से डोडा ले जाते हुए एक व्यक्ति को दबोचा। पुलिस ने बरसोल थाना क्षेत्र के खंडामौदा गांव निवासी अतुल कुंवर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से करीब 19 किलो डोडा बरामद हुआ। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

ईटीवी के पूर्व सीनियर कैमरामैन रीतेश का निधन

JAMSHEDPUR : ईटीवी के पूर्व सीनियर कैमरामैन रीतेश कुमार का गुरुवार सुबह टीएमएच में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे एक साल से कोमा में थे। वे गत वर्ष बिष्टुपुर में हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ब्रेन इंज्यूरी के बाद में वे कोमा में चले गए थे। बेटे रितिक ने बताया कि पिता का अंतिम संस्कार शुक्रवार को बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट पर होगा। शुरूआत में रीतेश का इलाज टीएमएच में हुआ था, जिसके बाद परिजन पहले रिम्स रांची और फिर दिल्ली ले गए थे। विभिन्न अस्पतालों में इलाज के बाद पिछले महीने उन्हें दिल्ली से रांची रिम्स लाया गया था। शहर के लोगों, पत्रकारों, विधायक सरयू राय,अमरप्रीत सिंह काले समेत कई लोगों ने आर्थिक सहायता की थी। 22अगस्त को उन्हें रिम्स के ट्रॉमा सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके बाद परिजन रीतेश को आदित्यपुर स्थित आवास लेकर आ गए थे। यहां 24 अगस्त को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें टीएमएच में दाखिल कराया गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल हो चुकी है। इलाज कराते-कराते वे कर्ज में डूब चुके हैं। हालात को देखते हुए झामुमो के प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने टीएमएच प्रबंधन से बात करके बिल माफ कराया।

टाटानगर स्टेशन चौक पर भाजपा 4 को देगी धरना

JAMSHEDPUR : भाजपा, जमशेदपुर महानगर 4 सितंबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन चौक स्थित शिव मंदिर के समीप सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक धरना देगी। इसमें सुंदरनगर, घाघीडीह, बागबेड़ा, जुगसलाई और परसुडीह क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न जनसमस्याओं को उठाया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को साकची स्थित जिला भाजपा कार्यालय में महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि धरना के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा।

टाटा स्टील के कर्मचारियों को ₹ 3,92,213 तक मिलेगा बोनस

कंपनी प्रबंधन व टाटा वर्कर्स यूनियन ने किया वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए समझौता

PHOTON NEWS JSR : वित्तीय वर्ष 2024-2025 के वार्षिक बोनस के भुगतान के लिए टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच 28 अगस्त को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अनुसार, वर्ष 2024-2025 के लिए वार्षिक बोनस के रूप में कंपनी के सभी संबंधित प्रभागों-इकाइयों के पात्र कर्मचारियों को 303.13 करोड़ रुपये भुगतान किया जाएगा। इसके तहत वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम (पूर्ण उपस्थिति पर) 39,004 रुपये और अधिकतम (वास्तविक उपस्थिति पर) 3,92,213 रुपये दिया जाएगा। इसमें से, जमशेदपुर के ट्यूब सहित अन्य अनुषंगी कंपनियों के लिए, लगभग 11,446 कर्मचारियों में 152.44 करोड़ रुपये की राशि वार्षिक बोनस के रूप में वितरित की जाएगी। चूंकि स्टील कंपनी के हमारे अधिकांश कर्मचारी बोनस भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2015 में निर्धारित सीमा से अधिक वेतन/मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वे अधिनियम के तहत बोनस के पात्र नहीं हैं। हालांकि, अपनी पुरानी परंपराओं का सम्मान करते हुए, कंपनी संघबद्ध श्रेणी के सभी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने जा रही है। इस समझौते पर गुरुवार को प्रबंधन की ओर से टीवी नरेंद्रन (सीईओ एवं एमडी), अत्रेयी सान्याल (मुख्य जन अधिकारी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और यूनियन की ओर से टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी व महासचिव सतीश कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने उप श्रम आयुक्त अरविंद कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

समझौते की प्रति दिखाते एमडी टीवी नरेंद्रन, अत्रेयी सान्याल व यूनियन नेता

6 सितंबर को बैंक खाते में जाएगी राशि

टाटा स्टील में कर्मचारियों को 16.68 प्रतिशत के हिसाब से बोनस मिला है। इसकी राशि 6 सितंबर को कर्मचारियों के बैंक खाते में जाएगी।

ट्यूब कंपनी के कर्मियों को भी मिलेगा बोनस

ट्यूब कंपनी के कर्मचारियों को न्यूनतम 39,004 रुपये व अधिकतम 1,10,547 रुपये मिलेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार का बोनस थोड़ा कम है।

इस तरह निर्धारित हुआ बोनस

टाटा स्टील व टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच जो बोनस समझौता हुआ, उसे इस प्रकार निर्धारित किया गया।

- कंपनी के 9255.05 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट का 1.5 प्रतिशत : 138.83 करोड़ रुपये
- 14.83 टन स्टील उत्पादन का 1.5 प्रतिशत मूल्य : 41.5 करोड़ रुपये
- उत्पादकता बोनस : 87.5 करोड़ रुपये
- सुरक्षा (सेफ्टी) बोनस : 5 करोड़ रुपये
- **कुल : 272.83 करोड़ रुपये**
- अतिरिक्त राशि प्रबंधन द्वारा 30.30 करोड़ रुपये
- **कुल बोनस : 303.12 करोड़**

बारिश से दो मकानों की दीवारें गिरीं, मुआवजे की मांग हुई तेज

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के हल्दीपोखर स्थित कुम्हार पाड़ा में गुरुवार को भारी बारिश के कारण दो कच्चे मकानों की दीवारें अचानक ढह गईं। हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन घरों में रह रहे परिवारों को हल्की चोटें आईं और उनका काफी सामान नष्ट हो गया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और पीड़ित परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। घटना की जानकारी के अनुसार, बारिश के कारण राजेश तामान और भगत दास के कच्चे मकानों की दीवारें भरभराकर गिर गईं। घटना के समय घर के सदस्य अंदर ही मौजूद थे, लेकिन समय रहते बाहर निकल जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, दीवार गिरने से घर के कई जरूरी सामान मलबे में दब गए और खराब हो गए। दोनों परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और अब उनके पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची है। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मदद की अपील की है। उनका कहना है कि लगातार हो रही बारिश से उनके घर पहले ही कमजोर हो गए थे, लेकिन किसी तरह गुजर-बसर कर रहे थे। अब पूरी तरह से बेघर हो जाने के बाद वे बेहद मुश्किल स्थिति में पहुंच गए हैं।

बाइक के नंबर से पकड़े गए छिनतई करने वाले दो बदमाश

डोबो पुल के पास बुधवार को ट्रक चालक से छीना था सोने का लॉकेट

PHOTON NEWS JSR : सोनारी थाना क्षेत्र में डोबो पुल के पास ट्रक चालक नवीन कुमार के साथ बुधवार को हुई छिनतई की वारदात ने शहर में सनसनी फैला दी थी। बाइक सवार दो बदमाशों ने नवीन के गले से सोने का लॉकेट (ताबीज) चेन समेत छीन ली और फरार हो गए थे। इसके बाद सोनारी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। डीएसपी ने गुरुवार को एसएसपी ऑफिस में प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि ट्रक चालक ने डोबो पुल के पास ट्रक रोका और वह लघुशंका के लिए गाड़ी से उतरा। इसके बाद जैसे ही वह गाड़ी पर चढ़ा। दो बदमाश बाइक से ट्रक के पास पहुंचे और इनमें से एक बदमाश ट्रक की केबिन में चढ़ गया और चालक के गले से सोने का लॉकेट छीन कर फरार हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। इसी दौरान बदमाशों की बाइक का नंबर सामने आया, जिसके आधार पर उनकी पहचान की गई। गिरफ्तार बदमाशों में एक का नाम विक्की सिंह है, जो गोलमुरी सर्कस मैदान का निवासी है, जबकि दूसरा आरोपी हरदीप सिंह बजरंग नगर, गोलमुरी का रहने वाला है। पूछताछ के बाद साकची से सोने की ताबीज को बरामद किया गया, जिसका वजन तीन ग्राम है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे पहले भी जेल जा चुके हैं।

गिरफ्त में आरोपी व मामले की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी

विहिप के स्थापना दिवस में धर्मांतरण व घुसपैठ पर जताई गई चिंता

JAMSHEDPUR : विश्व हिंदू परिषद का 61वां स्थापना दिवस गुरुवार को बिष्टुपुर स्थित हिंदूपीठ में मनाया गया। इस मौके पर सिंहभूम विभाग मंत्री अरुण सिंह ने धर्मांतरण व घुसपैठ को झारखंड के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासियों का धर्मांतरण कर ईसाई और मुस्लिम बनाना एक बडी समस्या है। इससे झारखंड की डेमोग्राफी मे बदलाव आया है। इसे रोका नहीं गया तो झारखंड मे हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ऐसी चुनौतियों से विहिप की लडाई जारी रहेगी। जनजागरण के माध्यम से धर्मांतरण पर रोक लगाने का काम विहिप करेगी। कार्यक्रम में कई जनमानस उपस्थित रहे।

तीन महिलाओं की हत्या में 5 को हुआ आजीवन कारावास

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र में गत वर्ष हुए एक हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन अभियुक्तों में मंगल सिंह सिंकू, मोटरा सिंकू, जोगेन सिंकू, सोमा सिंकू और टुपरा सिंकू शामिल हैं। सभी हाटगम्हरिया थाना अंतर्गत बड़ानूरदा गांव के चेतान साई ऊपरटोला निवासी हैं। इन पांचों अभियुक्तों पर आरोप था कि इन्होंने जमीन विवाद के कारण हाटगम्हरिया थाना अंतर्गत बड़ानूरदा गांव के रोयवारी सिंकु, रायमुनी सिंकु और रसिका सिंकु की हत्या कर दी थी और शव को केंदपोसी व तालाबुरू के बीच रेलवे लाइन पर फेंक दिया था। सभी अभियुक्तों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत कुटीयापदा निवासी हामिद अंसारी के पुत्र मानसुर अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मानसुर अंसारी पर 2020 में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप है। अभियुक्त पर 20,000 रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया है।

टेल्को के थीम पार्क स्थित तालाब में मिला छात्र का शव

थीम पार्क में शव देखने के लिए लगी भीड़ ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : टेल्को थीम पार्क स्थित तालाब से गुरुवार को 15 वर्षीय छात्र कुणाल कुमार का शव बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि युवक की हत्या कर शव तालाब में फेंका गया है। शव मिलने की सूचना मिलने के बाद इलाके के लोग इसे देखने के लिए तालाब के किनारे जुट गए। पुलिस ने युवक का शव बाहर निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों को भी आशंका है कि कुणाल की हत्या की गई है। गौरतलब है कि बारीगोड़ा (देवभूमि टोला) निवासी कुणाल 26 अगस्त की सुबह व्यायाम के लिए थीम पार्क गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, तभी तालाब में शव मिलने की सूचना मिली। शव की पहचान कपड़ों और गले में तिल के निशान से हुई। कुणाल एबीएमपी हाई स्कूल (राहड़गोड़ा) में कक्षा 10 का छात्र था। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम होने के बाद जांच आगे बढ़ेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि युवक की मौत कैसे हुई है। कुणाल की हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।

नहीं पकड़े जा सके बाल बंदी, डीसी-एसपी पहुंचे संप्रेक्षण गृह

CHAIBASA : चाईबासा स्थित संप्रेक्षण गृह से मंगलवार की आधी रात को फरार हुए दो बाल बंदी अब तक नहीं पकड़े जा सके हैं। इसी बीच गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने संप्रेक्षण गृह और बाल कुंज का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। घटना के बाद से ही जिला पुलिस लगातार छापामारी अभियान चला रही है। सुबह उठने के बाद रिमांड होम प्रशासन को उनकी अनुपस्थिति का पता चला। दो बच्चे विभिन्न आरोपों में रिमांड होम में लाए गए थे। उनकी गैरहाजिरी ने रिमांड होम प्रशासन की हवा निकाल दी। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे दीवार फांदकर वहां से फरार हुए हैं।

पायल सिनेमा की ओर मानगो फ्लाईओवर में बन सकते दो रैम्प

PHOTON NEWS JSR : जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने गुरुवार को विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मानगो फ्लाईओवर की डिजाइन में संशोधन कर पायल सिनेमा की ओर से आने-जाने वाले ट्रैफिक के लिए रैम्प को दोतरफा करने, अन्ना चौक से गोविंदपुर पथ को शीघ्र आरंभ करने, भुइयांडीह-लिट्टी चौक से भिलाईपहाड़ी तक जाने वाले स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन पुल का काम शुरू करने, कदमा-शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर-4 से खरकई नदी के किनारे होते हुए जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण करने तथा गोविंदपुर एवं जेम्को-जोजोबेड़ा में रेल ऊपरी पथ बनाने का मामला उठाया। उनके इस ध्यानाकर्षण के उत्तर में सरकार ने मानगो फ्लाईओवर के पायल सिनेमा की ओर जाने वाले रास्ते में रैम्प को दोतरफा करने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। लिट्टी चौक से एनएच-33 को जोड़ने वाले सड़क पर पुल का काम शीघ्र शुरू करने की भी बात कही गई।

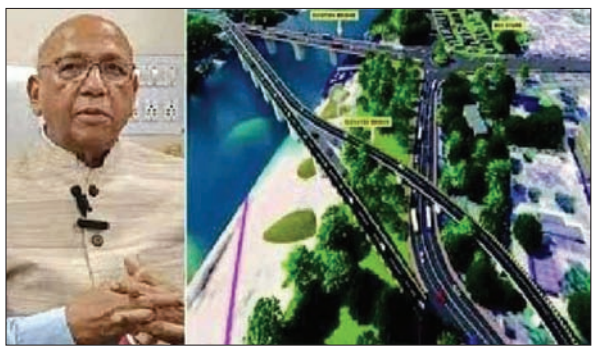

अन्ना चौक से गोविंदपुर पथ तक फोरलेन ऊपरी पथ के मामले में सरकार ने ठोस वादा नहीं किया। सरकार ने कदमा-शास्त्री नगर नदी किनारे सड़क का चौड़ीकरण के बारे में भी फिलहाल कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। हां, इन दोनों योजनाओं पर विचार करने का आश्वासन जरूर दिया। मानगो फ्लाईओवर के बारे में सरकार ने सरयू राय की बात मानने का आश्वासन दिया है।

फॉलोअप करीब 15 वर्षों से चल रहा था जॉब रैकेट का अवैध कारोबार, डर से अभ्यर्थी नहीं खोलते थे जुबान

‘यस सर और नो सर’ के नाम से थी संस्था की पहचान

RAJESH CHOUBEY @ GHATSILA : नौकरी दिलाने के नाम पर युवक और युवतियों से ठगी करने का खेल नया नहीं है। घाटशिला के लिए, यह खेल विगत 10 से 15 वर्षों से बिना किसी रूकावट के चला आ रहा था, यदि कहा जाए तो प्रशासन का अप्रत्यक्ष सहयोग भी इसमें रहा। इसके कारण ही निरंतर लंबे समय तक बिना किसी रोक-टोक के यह धंधा चलता रहा। इससे पहले कभी ग्लेज इंडिया के नाम से इस क्षेत्र में यह धंधा चल रहा था। इन सबके बावजूद डर के मारे अभ्यर्थी जुबान नहीं खोलते थे। अखबारों के माध्यम से दबाव बनने के कारण पुलिस की कार्रवाई से कुछ महीनो के लिए यह धंधा बंद पड़ गया था, लेकिन फिर से यह धंधा प्रारंभ हो गया। जिसका खुलासा गुरुवार को वरीय आरक्षी अधीक्षक पीयूष पांडेय ने किया। ग्रुप में कुछ एक्सपर्ट होते थे, जो फोन के माध्यम से भोले-भाले युवक-युवतियों को फांसते थे। अनुभवी नेटवर्क वाले लोग मायाजाल में फांसकर उन्हें बड़े-बड़े सपने दिखाते थे। प्रारंभ में निबंधन के नाम पर 10,000 फिर 15,000 और अब 25,000 रुपये वसूला जाने लगा था। यहां आने के बाद उन्हें एक कमरे में रखा जाता था, जहां कई सदस्य रहते थे। इन सदस्यों को कठोर अनुशासन में रखा जाता था। यहां खाने-पीने तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। यहां आने के बाद उन्हें एक ड्रेस कोड दिया जाता था। रोज उन्हें ऊंचे-ऊंचे बड़े सपने दिखाए जाते थे, जिससे प्रारंभ में इस गिरोह में फंसे हुए युवकों को यह लगता था कि वह भी बहुत कम समय में लखपति और करोड़पति बन सकते हैं। इस क्लास में केवल यस सर और नो सर की आवाज सुनाई पड़ती थी, जिसके कारण घाटशिला वासी इन बच्चों को यस सर-नो सर के नाम से भी पुकारते थे।

घाटशिला से मुक्त कराए गए युवक (फाइल फोटो)

बनारस की युवती के कारण हो चुका था विवाद

आज से एक वर्ष पहले बनारस की एक पढ़ी-लिखी युवती को गिरोह के सदस्यों ने अपने चंगुल में फसाया था। वह यहां आकर वास्तविकता जान गई और कुछ ही दिनों के अंदर वह इससे मुक्ति चाहती थी, लेकिन गिरोह के लोग उसे बाहर नहीं जाने देते थे। मौका निकाल कर युवती ने स्थानीय लोगों से शिकायत की, जिस पर पुलिसिया कार्रवाई भी हुई, लेकिन उस लड़की को मुक्त करने के बाद गिरोह के संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इसी प्रकार घाटशिला अनुमंडल के ही एक स्थानीय युवक को भी इस गिरोह के सदस्यों ने अपने चंगुल में फंसाया था। उसे भी प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा था। चूंकि वह स्थानीय था, जिसके कारण उसके मित्र और अन्य लोगों ने आकर संचालक पर दवाब बनाया और युवक को लेकर यहां से निकल गए। उस समय भी पुलिस को इन सब घटना की जानकारी थी, लेकिन इस अवैध कारोबार को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। कई लोगों का कहना है कि घाटशिला की अर्थव्यवस्था में इन युवकों का बड़ा योगदान था। प्रतिदिन यहां के युवक होटल, ठेलों व दुकानों से एक-डेढ़ लाख रुपये की खरीदारी करते थे। कई लोगों का रोजगार बाहर से आए हुए इन युवकों की सहायता से ही चलता था।.घाटशिला के अधिकांश क्षेत्रों में इस गिरोह ने ऊंचे किराए पर आवास लिया था। अब इनके चले जाने से घाटशिला में प्रतिदिन एक लाख से भी अधिक का लेन-देन बंद हो गया है।

आपसी विवाद के कारण हुआ खुलासा

बताया जा रहा है कि ग्रुप को लेकर इस गिरोह के सदस्य दो अलग-अलग खेमो में बट गए थे। दाहीगोड़ा में रहने वाले युवकों का नेतृत्व बिहार के एक युवक द्वारा किया जाता था, जबकि लालडीह और राजस्टेट में रहने वाले युवकों का नेतृत्व जमशेदपुर के गोविंदपुर निवासी युवक द्वारा किया जाता था। इस बीच बिहार के युवकों का नेतृत्व करने वाले टीम को गोविंदपुर के युवक ने तोड़ दिया, जिसके कारण यह शिकायत एसएसपी कार्यालय तक पहुंची और कार्रवाई हुई।

कपाली में भी फर्जी जॉब रैकेट का भंडाफोड़, चार युवक हिरासत में

हिरासत में लिए गए फर्जी जॉब रैकेट के आरोपी ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से मोटी रकम वसूल रहे ठगों को कपाली ओपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक तामोलिया क्षेत्र में रहकर भारत के अलग-अलग राज्यों से आए भोले-भाले युवकों को कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। हाल ही में उन्होंने कई युवकों से 30 से 35 हजार रुपये तक वसूले और उन्हें नौकरी के नाम पर प्रोडक्ट प्रचार कार्य में लगा दिया। करीब 200 से अधिक युवक इस ठगी का शिकार हो चुके हैं। आज सुबह कुछ पीड़ित युवकों ने स्थानीय लोगों को ठगी की जानकारी दी। इसके बाद लोगों ने मौके पर मौजूद चार सुपरवाइजरों को रोककर पूछताछ की और कपाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को ओपी ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवकों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश चल रही है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन शामिल है।

मधुमेह से बचाव में फायदेमंद होती है खड़े रहने की आदत

अक्सर स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए चहलकदमी और व्यायाम का सुझाव दिया जाता है, लेकिन इस मामले में खड़े रहने की आदत भी मददगार साबित हो सकती है। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक टाइप 2

फिनलैंड में हुए इस अध्ययन में खड़े रहने की आदत और बेहतर

रोजमर्रा की जिंदगी में खड़े होने का समय बढ़ाने से पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है।

खराब इंसुलिन प्रणाली मधुमेह की वजह

एनर्जी मेटाबॉलिज्म और रक्त शर्करा के नियमन में इंसुलिन एक प्रमुख हार्मोन है। कई बार वजन अधिक होने से शरीर में इंसुलिन के सामान्य फंक्शन में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो जाती है और टाइप 2 मधुमेह और हृदयरोगों का खतरा बढ़ जाता है। टाइप 2 मधुमेह दुनियाभर में सबसे आम जीवनशैली की बीमारियों में से एक है। इसकी शुरुआत आमतौर पर बिगड़ी हुई इंसुलिन संवेदनशीलता या इंसुलिन प्रतिरोध से होती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें शरीर सामान्य रूप से इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है।

एक हालिया अध्ययन के मुताबिक टाइप 2 मधुमेह से बचाव के मामले में खड़े रहना फायदेमंद होता है। फिनलैंड में हुए इस अध्ययन में खड़े रहने की आदत और बेहतर इंसुलिन संवेदनशीलता के बीच संबंध पाया गया है। इतना ही नहीं रोजमर्रा की जिंदगी में खड़े होने का समय बढ़ाने से पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है।

गतिहीन व्यवहार से इंसुलिन प्रणाली प्रभावित

जीवनशैली का इंसुलिन में रुकावट और टाइप 2 मधुमेह के विकास पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं की रोकथाम में नियमित शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि अब तक इंसुलिन की रुकावट पर गतिहीन व्यवहार, लगातार बैठे रहने के बीच ब्रेक और खड़े रहने की आदत के प्रभावों के बारे में बहुत कम जानकारी है। तुर्कू पीईटी सेंटर और यूकेके संस्थान के हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इंसुलिन में बाधा और गतिहीन व्यवहार के बीच संबंध की जांच की। इसके

निष्क्रियता के साथ टाइप 2 मधुमेह और हृदयरोगों के विकास के बढ़ते जोखिमों को भी देखा।

अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि रोजमर्रा की नियमित शारीरिक गतिविधि या बैठने के समय, फिटनेस स्तर से अलग स्वतंत्र रूप से खड़े रनहा बेहतर इंसुलिन संवेदनशीलता से जुड़ा

एवं तुर्कू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तारू गर्थवेट का कहना है कि अध्ययन के निष्कर्ष रोजाना बैठने के समय के एक हिस्से में लोगों को खड़े रहने के लिए प्रेरित करेंगे। खासकर अगर शारीरिक गतिविधि की जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है तो यह तरीका मददगार हो सकता है।

जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम होगी

भी जोर देता है। अध्ययन परिणाम बताते हैं कि शारीरिक गतिविधि, फिटनेस या बैठने में लगने वाले समय की तुलना में शरीर में वसा के प्रतिशत में इजाफा इंसुलिन संवेदनशीलता के मामले में अधिक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरी ओर खड़े होना शरीर की संरचना के बावजूद इंसुलिन संवेदनशीलता से जुड़ा था। शोधकर्ताओं का कहना है कि नियमित व्यायाम को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है।

मगर ऐसा लगता है कि शारीरिक गतिविधि, फिटनेस और गतिहीन व्यवहार भी इंसुलिन मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन परोक्ष रूप से यह शरीर की संरचना पर उनके प्रभाव के माध्यम से जुड़े हैं। जर्नल ऑफ साइंस एंड मेडिसिन इन स्पोर्ट में प्रकाशित इस अध्ययन के आधार पर अभी तक कारण प्रभावों का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार परिणाम बताते हैं कि यदि पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं की जा रहीं तो रोजाना खड़े होने का समय बढ़ाने से जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में मदद मिल सकती है।

कम नींद लेने से हो सकती हैं गंभीर बीमारियां

कम सोने की वजह से इन लोगों को जो बीमारियां होती हैं, उसकी जानकारी कम ही लोगों को होती है। दरअसल, कई लोगों को तो यह मानना भी मुश्किल-सा लगता है कि कई वर्षों तक कम सोते रहने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, स्ट्रोक इत्यादि जैसी अन्य गंभीर बीमरियां घंटों की सही नींद न लेने की वजह से हो सकती हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार 60% से ज्यादा भारतीय सोचते हैं कि नींद लेना कोई प्राथमिकता नहीं है। पिछले कुछ सालों में नींद के महत्व और आवश्यक नींद पूरी न होने से जुड़े खतरों के बारे में बताए जाने के बाद भी लोग नींद को उतनी अहमियत नहीं देते जितना कि व्यायाम को देते हैं। हाल ही में देशभर में हुए सर्वेक्षणों से पता चला है कि देश में नींद की कमी गंभीर चिंता का कारण क्यों है?

यहां तक देखा गया है कि लोगों को यह कहने में फख महसूस होता है कि वे 4-5 घंटे ही सोते हैं और अपने बाकी के सभी कामों को प्राथमिकता से करते हैं। यदि इस तरह के कम सोने वाले लोग अपनी नौकरी, व्यवसाय व घर-परिवार में कुशल हों तब तो ऐसे लोगों का उदाहरण दूसरे लोगों के लिए पेश किया जाता है कि 'देखो फलाना व्यक्ति ज्यादा सोने में समय बर्बाद नहीं करता है इसलिए तो उसने जीवन में इतना कुछ पा लिया है।'

यह बात और है कि आगे जाकर कम सोने की वजह से इन लोगों को जो बीमारियां होती हैं, उसकी जानकारी कम ही लोगों को होती है। दरअसल, कई लोगों को तो यह मानना भी मुश्किल-सा लगता है कि कई वर्षों तक कम सोते रहने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, स्ट्रोक इत्यादि जैसी अन्य गंभीर बीमरियां घंटों की सही नींद न लेने की वजह से हो सकती हैं। हमारे देश में कई लोग आज भी ऐसे हैं, जो ये मानते हैं कि खर्राटे आना गहरी नींद की निशानी है। उन्हें यह समझाना चुनौतीपूर्ण काम है कि दरअसल खर्राटे आना भी एक गंभीर नींद विकारों के कारणों में से एक है।

एक अन्य हाल ही के सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि 19 फीसदी भारतीय वयस्कों की नींद में बाधा का कारण उनके काम करने की शिफ्ट का बदलते रहना है। 32% युवा वयस्क टेक्नोलॉजी के ज्यादा और देर रात तक प्रयोग की वजह से पूरी नींद नहीं ले पाते हैं।

एक वयस्क के लिए भी 7 से 9 घंटे की नींद बेहद जरूरी है। कई मामलों में जो लोग इतना सोते हैं उन्हें देखकर अन्य लोग ऐसे लोगों के लिए राय बना लेते हैं कि 'फलाना व्यक्ति आलसी व कमजोर है', तो कुछ लोगों को तो खुद ही यह कहने में शर्म महसूस होती है कि 'उन्हें इतना सोने की जरूरत है।' सिर्फ 1 दिन यदि आप 4-5 घंटे से कम सोते हैं, तब आपके शरीर की वे प्राकृतिक कोशिकाएं, जो कैंसर की कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें खत्म करने में सक्षम होती हैं, 70% तक कम हो जाती हैं। आपको कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाएं आपके शरीर में प्रतिदिन बनती हैं। रिपोर्ट के अनुसार नींद की कमी से आंत, प्रोस्टेट और स्तन कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि आप प्रतिदिन नियमित समय पर सोएं और नियमित समय पर उठें।

क्यों नहीं आती है आपको मीठी नींद

दिनभर की मेहनत और थकान के बाद एक सुहानी नींद पर आपका पूरा हक है लेकिन कई लोगों को बेवजह नींद न आने की शिकायत होती है। आइए मीठी नींद के लिए क्या करें जतन.

- रोज सुबह उठकर कसरत करनी चाहिए।
- अच्छी नींद लेने के लिए कभी भी दिन में न सोएं और सोने से कुछ देर पहले एल्कोहल या कैफीन का सेवन भूलकर भी न करें।
- धूम्रपान न करने से भी नींद अच्छी आती है क्योंकि सिगरेट में पाए जाने वाला निकोटिन नींद में बाधा उत्पन्न करता है।
- कई प्रकार के ड्रग्स भी आराम की नींद लेने में बाधक सिद्ध होते हैं।
- अगर आप शाम को कसरत करेंगे तो आपको सोने में परेशानी हो सकती है।
- जिन महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी होती है उन्हें अक्सर नींद कम आती है। इसलिए शरीर में आयरन की कमी का विशेष ख्याल रखें।
- सुबह जब आप उठें तो सूर्य की तेज रोशनी को कमरे में अंदर आने दें। क्योंकि सही प्रकाश की वजह से शरीर को सही ऊर्जा मिलती है।
- एक बात और ध्यान रखें कि रात को सोते वक्त बेडरूम में रोशनी कम ही रहनी चाहिए, जिससे अच्छी और भरपूर नींद आ सके।

...तो जनाब अच्छी व गहरी नींद लीजिए और फिर जिंदगी को पूरी ऊर्जा के साथ जी लेने के लिए खुद को तैयार पाइए।

सूखा नारियल सेहत के लिए है कुदरत का वरदान

सूखे नारियल का इस्तेमाल घरों में खीर, आइसक्रीम, स्वीट डिश वगैरह में होता है। ज्यादातर लोग इसे स्वाद बढ़ाने के लिए रेसिपीज में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसकी न्यूट्रीशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है। इस बात पर कम लोगों का ध्यान जाता है। नारियल आपके हार्ट और ब्रेन के लिए अच्छा होता है। साथ ही इसे चबाने से फेशियल एक्सरसाइज भी होती है। इसमें ऐंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बढ़िया होते हैं।

ऐंटीऑक्सिडेंट्स का भंडार

नारियल में फिनॉलिक कंपाउंड होते हैं, जो कि ऐंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपकी सेल्स के ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकते हैं। इसमें गैलिक एसिड, कैफिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, पी-कोम्यूरिक एसिड होता है। नारियल आपकी धमनियों में प्लाक बनने से रोकता है जो कि हार्ट ब्लॉकेज की वजह होती हैं।

कनेक्टिव टिश्यूज के लिए फायदेमंद

नारियल में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज को मजबूत बनाते हैं। नारियल को डायट में शामिल करने से गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं होने का खतरा कम होता है। इसके अलावा ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है।

आयरन की कमी को दूर करता है

महिलाओं में आयरन की कमी बड़ी समस्या है। सूखे नारियल में आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है। डेली डायट में नारियल खाने से आयरन की कमी पूरी होती है। बच्चा पैदा होने के बाद महिलाओं को नारियल की कई मिठाइयां इसीलिए बनाकर खिलाई जाती हैं।

पोषकतत्वों का भंडार

सूखे नारियल में प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज और सेलिनियम पाया जाता है। ये पोषक तत्व इम्यूनिटी मजबूत करके शरीर को रोगों से बचाते हैं।

दिमाग रखता है मजबूत

नारियल खाने से किसी का आईक्यू तो नहीं बदलता लेकिन आपके ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। स्टडीज में सामने आ चुका है कि नारियल का तेल अल्जाइमर्स होने से रोकता है।

सेहत का रखना है ख्याल तो अर्जुन फल का करें इस्तेमाल

ऐसे कई लोग होते हैं जो सांसों की बदबू के कारण परेशान रहते हैं और ऐसे में उन्हें किसी से बात करने में भी शर्मिन्दगी महसूस करते हैं। अगर आपका नाम भी ऐसे ही लोगों की लिस्ट में शामिल है तो आप अर्जुन के फल का सेवन करें।

अर्जुन के वृक्ष को भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद ही गुणकारी माना गया है। दरअसल, इसमें एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल जैसे विभिन्न औषधीय गुण होते हैं। अर्जुन हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत और टोन करता है और हृदय के समुचित कार्य में मदद करता है। इतना ही नहीं, यह उच्च रक्तचाप से लेकर दस्त, अस्थमा और खांसी आदि कई तरह की समस्याओं को दूर करने में सहायक है। अर्जुन के फल से मिलने वाले कुछ बेमिसाल फायदे -

सांसों की दुर्गंध से मिलता है छुटकारा

ऐसे कई लोग होते हैं जो सांसों की बदबू के कारण परेशान रहते हैं और ऐसे में उन्हें किसी से बात करने में भी शर्मिन्दगी महसूस करते हैं। अगर आपका नाम भी ऐसे ही लोगों की लिस्ट में शामिल है तो आप अर्जुन के फल का सेवन करें। इस फल में ऐसे होते हैं जो आपके मसूड़ों की समस्याओं और दांतों से खून बहने में भी मदद कर सकते हैं और आपको ताजा सांसें प्रदान करते हैं।

हड्डियों का रखते हैं ख्याल

अगर आप किसी किसी भी प्रकार की हड्डी की समस्या से पीड़ित हैं, तो आपको अपने आहार में अर्जुन फल को अवश्य शामिल करना चाहिए। आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं या इसे कच्चा खा सकते हैं। यह आपको ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसी हड्डियों की परेशानी में भी मदद कर सकता है।

ओरल हेल्थ की समस्याओं को करें दूर

अर्जुन फल खाने से वास्तव में आपकी मसूड़ों की समस्याओं को कम करने और दांतों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। यह दांतों से खून बहने से लेकर दांत दर्द, मसूड़ों में दर्द या मसूड़ों से खून बहना आदि समस्याओं के उपचार में प्रभावी है। आप इस फल को जूस या कच्चा खा सकते हैं। इसके अलावा, अर्जुन के फल के पाउडर का सेवन भी कर सकते हैं और इसे पेस्ट के रूप में उस जगह पर लगा सकते हैं जहां आपको मसूड़े या दांतों की समस्या हो रही है। हालांकि, यह उपाय अपनाने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।

सेंधा नमक को करें डाइट में शामिल, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

सेंधा नमक कब्ज, हार्ट बर्न, सूजन, पेट दर्द आदि जैसी पाचन समस्याओं के लिए एक उत्कृष्ट घरेलू उपाय है। सेंधा नमक खनिजों और विटामिनों से भरपूर होता है, जो पाचन में सुधार करता है, मल त्याग को बढ़ावा देता है, और आंत से विषाक्त उत्पादों को साफ करने में मदद करता है।

नमक एक ऐसा इंग्रीडिएंट है, जिसका इस्तेमाल हम सभी नियमित रूप से करते हैं। यह भोजन में एक स्वाद शामिल करता है। नमक के बिना भोजन पकाने या उसे खाने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि घरों में लोग टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नमक को अपने स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाना चाहते हैं तो आज ही सेंधा नमक खाना शुरू कर दें। सेंधा नमक में सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक आदि तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत को लाभ पहुंचाते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में सेंधा नमक का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह स्वस्थ त्वचा और बालों से लेकर वजन घटाने तक कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। सेंधा नमक से मिलने वाले कुछ बेमिसाल फायदे -

पाचन तंत्र के लिए लाभदायक

सेंधा नमक कब्ज, हार्ट बर्न, सूजन, पेट दर्द आदि जैसी पाचन समस्याओं के लिए एक उत्कृष्ट घरेलू उपाय है। सेंधा नमक खनिजों और विटामिनों से भरपूर होता है, जो पाचन में सुधार करता है, मल त्याग को बढ़ावा देता है, और आंत से विषाक्त उत्पादों को साफ करने में मदद करता है। यह भूख की कमी की समस्या को सुधारने में भी मदद करता है।

प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है

सेंधा नमक विटामिन के से भरपूर होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यह शरीर की हड्डियों के चयापचय को भी बढ़ाता है, जो कई बीमारियों से बचाता है। मांसपेशियों में ऐंठन से राहत सेंधा नमक में सोडियम क्लोराइड का शुद्ध रूप और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम और नमक असंतुलन मांसपेशियों में ऐंठन के लिए एक जोखिम कारक हो सकता है। तो, सेंधा नमक पोटेशियम की कमी को संतुलित कर सकता है और मांसपेशियों में ऐंठन को रोक सकता है।

गले की खराश का करता है इलाज

गले में खराश के लिए खारे पानी से गरारे करना एक आम घरेलू उपाय है। सेंधा नमक में डिकॉन्गेस्टेंट गुण होते हैं जो आपकी बंद नाक, खांसी को दूर करने में मदद करते हैं। यह टॉन्सिलिटिस अस्थमा के लिए भी एक प्रसिद्ध उपाय है, और यह आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।

रक्तचाप को करे बैलेंस

सेंधा नमक में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। शोध बताते हैं कि सेंधा नमक रक्तचाप को संतुलित रखता है।

मोदी का नव पंचशील सिद्धांत नया भारत, नई रणनीति

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने 12वें उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत और राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखते हुए एक तरह से नव पंचशील सिद्धांत का उद्घोष किया। अप्रैल 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पीएम चाऊ एन लाई ने पंचशील सिद्धांत का निरूपण किया था, जो पारस्परिक सम्मान, अहस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित था, पर 1962 में चीन ने हमारे हजारों किमी भू-भाग पर कब्जा कर उसकी अंत्येष्टि कर दी। प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में विरासत में विषम आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां मिलीं। उनका सामना करते हुए उन्होंने पंचशील सिद्धांत का पालन किया। विगत 11 वर्षों में उन्होंने भारत की वैश्विक छवि और शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन किया है। पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से पहलगाम में लोगों का मजहब पूछकर हत्या के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य शक्ति से विश्व को परिचित कराया। मोदी ने विश्व को संदेश दिया कि यह नया भारत है, जो पुराने पंचशील सिद्धांत का अनुपालन करते हुए एक नव पंचशील सिद्धांत का उद्घोष करता है। मोदी का नव पंचशील सिद्धांत नई सैन्य रणनीति, कुशल विदेश नीति, चतुर कूटनीति, नवीन आर्थिक संकल्पना और हिंदुत्ववादी समावेशी राजनीति पर आधारित है। यह उभरते भारत की अस्मिता है। भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम की चर्चा पूरे विश्व में हमेशा रही है, पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और रणनीतिक कमजोरियों के चलते कई बार सेना का सामर्थ्य व्यर्थ हो गया, वह चाहे 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो या 1971 में बांग्लादेश युद्ध। 1965 और 1971 में भारत अपनी विजय के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इससे पाकिस्तान को भ्रम हो गया कि भारत उसके प्रति आक्रामक रुख नहीं अपना सकता। नाभिकीय शक्ति प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान और भी आश्वस्त हो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने लगा, पर मोदी ने देश की सैन्य रणनीति का गियर बदल दिया है। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि अब आतंकी गतिविधियों का प्रत्युत्तर भारत कैसे देगा। मोदी की घोषणा कि आतंकी हमलों को युद्ध की संज्ञा दी जाएगी, भारतीय सैन्य रणनीति को एक नया आयाम देती है। ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करना पाकिस्तान पर सदैव लटकने वाली तलवार है, जो न केवल उसके नाभिकीय ब्लैकमेल को दरकिनार करती है, वरन वहां की सरकार और सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाती है। 15 अगस्त को मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कर मोदी ने बाहरी आक्रमण से संवेदनशील प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना और सशक्त प्रत्युत्तर देना भी सैन्य रणनीति में शामिल किया है। विदेश नीति में वैश्विक शक्तियों से समान दूरी के सिद्धांत का परित्याग कर मोदी ने सबसे समान निकटता का सिद्धांत अपनाया है, जो वसुधैव कुटुंबकम् के अनुरूप है। उन्होंने अगस्त 2025 तक 78 देशों की यात्राएं की हैं और 27 देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। वे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों जैसे अमेरिका-रूस, रूस-यूक्रेन, अरब-इजरायल, अमेरिका-चीन तथा अन्य छोटे-बड़े सभी देशों से बात कर सकते हैं। उनकी विदेश नीति में पंचशील से आगे पंचामृत के दर्शन होते हैं, जो सम्मान, संवाद, संवृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता से निर्मित है। मोदी भारतीय सम्मान से समझौता किए बिना सभी देशों से संवाद करते हैं, ताकि सभी का हित हो और किसी की सुरक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता पर आंच न आए। इसीलिए चीन से तमाम तनाव के बावजूद वे चीन जा रहे हैं। कूटनीतिक कुशलता नव पंचशील का तीसरा तत्व है, जिसमें यथार्थवाद और नैतिकता का अद्भुत समन्वय है। अपनी कूटनीति से मोदी सबको चकित करते हैं। उनमें चातुर्य के साथ सहनशीलता है। वे साम, दाम, दंड और भेद का समुचित प्रयोग करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी ओर से विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना इसका उदाहरण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत-पाकिस्तान के बीच टकराव पर बार-बार मध्यस्थता का श्रेय लेने की कोशिश और असभ्य राजनयिक भाषा के प्रयोग का जवाब देने की विपक्षी चुनौती को अनदेखा कर मोदी ने दृढ़ता से, पर सभ्य राजनयिक भाषा में प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने ट्रंप के अमेरिका आने के आमंत्रण को सधन्यवाद अस्वीकार किया और संसद में स्पष्ट किया कि भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम बिना किसी मध्यस्थ के पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ। उनकी कूटनीति भारतीय बाजार के हितों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है, ताकि भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। वे किसी सामरिक संघर्ष में उलझना नहीं चाहते। नव पंचशील का चौथा तत्व आर्थिक सामर्थ्य है, जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के स्तंभों पर खड़ा है। गांधीजी ने स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। पीएम मोदी भी स्वदेशी का आह्वान कर नव साम्राज्यवाद से लड़ रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले भारत की वैश्विक निर्णयन में बराबरी की भूमिका हो, इसके लिए मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे भारतीय बाजार को अमेरिकी लूट के लिए नहीं खोलेंगे और भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेगा। फाइटर जेट इंजन, सेमीकंडक्टर आदि का देश में निर्माण कर वे भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। उनके नव पंचशील का पांचवां तत्व समावेशी राजनीति है, जो जातिवादी अस्मिता की राजनीति से आगे निकल वर्ग राजनीति की ओर जाती है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर कसता शिकंजा

ANALYSIS

✍ डॉ. मयंक चतुर्वेदी

नारायणपुर की घटना ताजा उदाहरण है, जहां दो महिलाओं समेत आठ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इनमें से कई कुख्यात माओवादी नेता थे। सुखलाल एक डिविजनल कमेटी सदस्य और माओवादी डॉक्टर के रूप में सक्रिय था, उस पर आठ लाख का इनाम था। इसी तरह हुर्रा भी कंपनी नंबर एक पीपीसीएम से जुड़ा था और उसके सिर पर भी आठ लाख का इनाम था। पोडियाम एरिया कमेटी मेंबर और लोकल ऑर्गेनाईजेशन स्क्वॉड का डिप्टी कमांडर था। कमला और दीपा जैसी महिला सदस्य भी संगठन में अहम जिम्मेदारी संभाल रही थीं। इन आत्मसमर्पणों से यह स्पष्ट होता है कि जंगलों के भीतर भी माओवादियों का मनोबल लगातार टूट रहा है। वस्तुत: यह सिलसिला केवल नारायणपुर तक सीमित नहीं है। बीते वर्षों में बस्तर, सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों ने कई बड़े ऑपरेशन चलाए। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों ने मिलकर ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन डॉन जैसी मुहिमें चलाईं, जिनमें एक के बाद एक बड़े नक्सली ढेर हुए। कुख्यात माओवादी नेता हिड़मा, जो बस्तर डिवीजन कमेटी का सबसे खतरनाक चेहरा माना जाता था, लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर रहा।

छत्तीसगढ़ की धरती लंबे समय से लाल आतंक की त्रासदी झेलती रही है। कभी दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर और नारायणपुर तक नक्सलियों का बोलबाला था, जंगलों में बंदूक की आवाजें गूंजती थीं और जनजाति समाज भय और असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर थी, परंतु अब पिछले कुछ वर्षों में इस तस्वीर में निर्णायक बदलाव आया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की समन्वित रणनीति, सुरक्षा बलों की लगातार दबिश और विकास व पुनर्वास की समानांतर नीतियों ने वह काम किया है जो वर्षों तक एक असंभव प्रतीत होता था। देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य की भाजपा सरकार के नेतृत्व और नक्सल मुक्त भारत के उनके दृष्टिकोण के तहत, ऐसी कई पहलें देश के उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, जो कभी देश के वर्जित क्षेत्र रहे हैं। नारायणपुर की घटना ताजा उदाहरण है, जहां दो महिलाओं समेत आठ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इनमें से कई कुख्यात माओवादी नेता थे। सुखलाल एक डिविजनल कमेटी सदस्य और माओवादी डॉक्टर के रूप में सक्रिय था, उस पर आठ लाख का इनाम था। इसी तरह हुर्रा भी कंपनी नंबर एक पीपीसीएम से जुड़ा था और उसके सिर पर भी आठ लाख का इनाम था। पोडियाम एरिया कमेटी मेंबर और लोकल ऑर्गेनाईजेशन स्क्वॉड का डिप्टी कमांडर था। कमला और दीपा जैसी महिला सदस्य भी संगठन में अहम जिम्मेदारी संभाल रही थीं। इन आत्मसमर्पणों से यह स्पष्ट होता है कि जंगलों के भीतर भी माओवादियों का मनोबल लगातार टूट रहा है। वस्तुतः यह सिलसिला

केवल नारायणपुर तक सीमित नहीं है। बीते वर्षों में बस्तर, सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों ने कई बड़े ऑपरेशन चलाए। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों ने मिलकर ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन डॉन जैसी मुहिमें चलाईं, जिनमें एक के बाद एक बड़े नक्सली ढेर हुए। कुख्यात माओवादी नेता हिड़मा, जो बस्तर डिवीजन कमेटी का सबसे खतरनाक चेहरा माना जाता था, लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर रहा। उसके नेटवर्क को जिस तरह से तोड़ा गया, वह राज्य की सुरक्षा रणनीति की सफलता का उदाहरण है। इसके अलावा मांडवी हिड़मा, गुडसा उसेंडी और अन्य कई कुख्यात कमांडरों के मारे जाने या आत्मसमर्पण से संगठन की रीढ़ टूट चुकी है। नक्सलवाद केवल बंदूक की लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई भी है। माओवादी संगठन लंबे समय तक आदिवासियों के नाम पर उन्हें बरगलाता रहा, उनके विकास और हक की बातें कर उन्हें सरकार और व्यवस्था से दूर रखता रहा। परंतु जब केंद्र और राज्य सरकार ने यह ठाना कि विकास को ही हथियार बनाया जाएगा, तब तस्वीर बदलने लगी। सड़कें बनीं, पुल बने, स्कूल और अस्पताल खुले, मोबाइल टावर खड़े हुए और आदिवासी इलाकों में पहली बार शासन-प्रशासन की मौजूदगी महसूस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि नक्सलवाद बंदूक की गोलियों से नहीं, विकास की रोशनी से खत्म होगा। यही सोच छत्तीसगढ़ की रणनीति की रीढ़ बनी हुई दिखाई देने लगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हाल ही में कहा कि हमारी प्राथमिकता केवल कानून-व्यवस्था नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें भयमुक्त वातावरण देना है। पुनर्वास नीति इसी सोच का हिस्सा है। यह वही नीति है, जिसने नारायणपुर के आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को हथियार छोड़ने के लिए प्रेरित किया। राज्य सरकार ने उन्हें पचास-पचास हजार रुपये की तत्काल सहायता दी है और आगे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक पुनर्वास की गारंटी भी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बार यह दोहराया है कि 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करना सरकार का लक्ष्य है। उनके शब्दों में नक्सलवाद इस देश के विकास और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी बाधा रहा है। हमने पिछले दस वर्षों में इसे जड़ से खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की है और अब यह आतंक अपने अंतिम चरण में है। वास्तव में आंकड़े इस दावे की पुष्टि करते हैं। बीते एक दशक में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या आधी रह गई है। जहां कभी छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार समेत 126 से अधिक जिले इस लाल आतंक से प्रभावित थे, आज इनकी संख्या सिमटकर 18 से भी कम रह गई है, जिसमें छह जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं, छत्तीसगढ़ के बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली। वहीं, छह जिले चिंताजनक श्रेणी में हैं, आंध्र प्रदेश (अल्लूरी सीताराम राजू), मध्यप्रदेश (बालाघाट), ओडिशा (कालाहांडी, कंधमाल, मलकानगिरी), तेलंगाना (भद्राद्री-कोठागुड़ेम)। इसी तरह से अब अन्य प्रभावित जिले में छत्तीसगढ़ (दंतेवाड़ा, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी), झारखंड (लातेहार), ओडिशा (नुआपाड़ा), तेलंगाना (मुलुगु) शामिल हैं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए बनाई गई नीति के सख्त और सुनियोजित क्रियान्वयन से देश भर में 2010 की तुलना में नक्सली हिंसा में 81% की कमी आ चुकी है, जबकि सुरक्षाबलों और आम नागरिकों की मौतों में 85% की गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में भी यही तस्वीर है। नारायणपुर जिले में इस साल अब तक 148 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बीजापुर और सुकमा में भी सौ से अधिक नक्सली या तो मारे गए हैं या सरेंडर कर चुके हैं। इनमें कई मोस्ट वांटेड नाम भी शामिल हैं। 2023 में दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए एनकाउंटर में बस्तर डिवीजन के बड़े कमांडरों का खात्मा हुआ। कांकेर जिले में भी हाल ही में सुरक्षाबलों ने कई माओवादी नेताओं को ढेर किया। इन सबका नतीजा यह है कि माओवादी संगठन के पास अब वैसा ढांचा और नेतृत्व नहीं बचा है जैसा कभी था। नक्सलवाद को खत्म करने में सरकार ने दोहरी रणनीति अपनाई हुई है- एक ओर सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन, ट्रैकिंग तकनीक और बेहतर इंटेलिजेंस से लैस किया गया है तो दूसरी ओर आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया। यह संतुलन ही सफलता की कुंजी बना। पहले केवल सैन्य दबाव से नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वह असफल रही, क्योंकि जंगलों में छिपे नक्सली बार-बार लौट आते थे, पर जब विकास का विकल्प सामने आया, तब आदिवासी समाज ने नक्सलियों से दूरी बनानी शुरू की। आज स्थिति यह है कि खुद गांव के लोग पुलिस और प्रशासन को सूचना देने लगे हैं, जिससे माओवादियों की जड़ें और कमजोर हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक रैली में कहा था, छत्तीसगढ़ की धरती अब रक्तरंजित नहीं, विकास की धरती बन रही है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इस दशक के अंत तक देश नक्सलवाद की चुनौती से मुक्त होगा।

हमारा स्वास्थ्य ढांचा और मोहन भागवत का विचार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पिछले दिनों इंदौर में महंगी स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले भारत में महंगी चिकित्सा सुविधाएं निःसंदेह चिंता का विषय है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि निजी अस्पताल मरीजों को एटीएम समझते हैं। असल में भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र गंभीर विसंगतियों से भरा हुआ है। एक तरफ तो हम सस्ती दवाओं और वैक्सीन के उत्पादन में विश्व भर में शीर्ष पर है, लेकिन हमारे ही नागरिक दुनिया में अपने स्वास्थ्य पर अपनी जेब से सर्वाधिक पैसा भी खर्च करते हैं। देश में आर्थिक भेदभाव कम हो रहा है। इसे दुनिया के तमाम संगठन मान रहे हैं, लेकिन यह भी तथ्य है कि देश में करीब 7 फीसद लोग महंगे इलाज के कारण गरीबी के गर्त में हर साल पहुंच जाते हैं। पिछले साल दिल्ली के एक निजी अस्पताल का किडनी उपचार सम्बंधित बिल 2473894 रुपये का बनाया गया था। यह बानगी भर है कि निजी क्षेत्र का स्वास्थ्य तंत्र किस तरह काम कर रहा है। एसीकेओ इंडिया हेल्थ इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट कहती है कि देश में हर साल इलाज महंगा होने की दर 14 फीसद है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक, आयुष्मान भारत जैसी बेहतरीन योजना के बाबजूद देश में अभी भी 40 फीसद लोग अपने स्वास्थ्य पर अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, जिसे ओओपीई (आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर) कहा जाता है। यह आंकड़ा वैश्विक औसत 18 फीसद से काफी अधिक है। हालांकि आयुष्मान भारत के बाद स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 29 से बढ़कर 48 प्रतिशत हुआ है, यह एक अच्छा संकेतक है। मोहन भागवत ने जिस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह आम आदमी के दर्द को अधोरेखित करने वाला है, क्योंकि 23 फीसद लोग अभी भी अस्पताल के खर्चों के लिए उधार लेने पर मजबूर हैं। महंगी स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे अहम पहलू दवाओं से जुड़ा है, क्योंकि दवाएं अभी भी बहुत महंगी है। निजी क्षेत्र में उपचार के दौरान 70 से लेकर 90 फीसद तक एलोपैथी दवाएं ब्रांडेड ही उपयोग में आ रही हैं,जबकि सरकार ने सस्ती जेनरिक दवाओं के लिए प्रधानमंत्री जन औषिधि केंद्र आरंभ किए हैं। इन केंद्रों पर 90 फीसद तक दवाओं के दाम ब्रांडेड दवाओं की तुलना में कम होते हैं। जेनेरिक दवाओं के लिए सरकारी प्रयास फार्मा लॉबी के दबाव में फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक देश भर में 15057 जेनेरिक स्टोर खुल पाए हैं और विसंगति यह है कि इन स्टोरों में ब्रांडेड दवाओं की बिक्री भी जेनेरिक के साथ में की जा रही है। भारत में एलोपैथी दवाओं का सालाना कारोबार 4.2 लाख करोड़ का है। करीब 3 लाख करोड़ की खपत भारतीय बाजार में है और 1.2 लाख करोड़ की दवाएं निर्यात की जाती हैं। सरकार को सर्वोपरि प्राथमिकता पर इसी क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। अभी जेनेरिक दवाओं की तुलना में ब्रांडेड दवाओं की कीमतें 30 से 2000 फीसदी तक महंगी बिक रही हैं। ब्रांडेड दवाओं के इस संगठित कारोबार को रोक कर महंगे इलाज को झटके में जमीन पर लाया जा सकता है। असल में देश को हरित क्रांति की तरह दवा क्रांति की आवश्यकता भी है, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में कोई खास विनियमन नहीं है। आजादी के समय यूरोपीय पेटेंट वाली दवाएं इसलिए महंगी थीं, क्योंकि हमारे यहां उत्पादन ही नहीं था। 1970 में पेटेंट एक्ट के बाद भारत ने दवाओं के निर्माण में अभूतपूर्व काम किया। आज हम विश्व के अग्रणी उत्पादक हैं। कोरोना वैक्सीन में भारत का यह दम दुनिया ने देखा ही है। महंगे इलाज का दूसरा कारक स्वास्थ्य क्षेत्र के कॉर्पोरेटाइजेशन (निगमीकरण) का है, क्योंकि देश में 1980 तक स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में धर्मार्थ न्यास या फाउंडेशन ही सक्रिय थे और सबका उद्देश्य मुनाफा नहीं सेवा मुख्य था। इसके बदले में सरकार ने गरीबों को सस्ते इलाज और स्थानीय रोजगार के नाम पर मुफ्त जमीनें दी और टैक्स रियायतें उपलब्ध कराई। आज इस क्षेत्र में नए खिलाड़ी आ गए हैं, जिनका उद्देश्य कारपोरेट घरानों की तरह कारोबार करना है। यही कारण है कि देश के दो तिहाई अस्पताल शहरी क्षेत्रों में हैं और इन अस्पतालों से महज एक तिहाई आबादी को ही सेवाओं का कवरेज मिल रहा है। निजी अस्पतालों की सघनता शहरी क्षेत्रों में घनीभूत है, क्योंकि निवेशकों की नजर ज्यादा पैसे वाले क्षेत्रों में ही होती हैं। ध्यान देने वाला तथ्य यह है कि इन शहरी क्षेत्रों में आने वाले अधिसंख्य मरीज उन बीमारियों के होते हैं, जिनको आरम्भिक शिकायत पर ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक सेवाओं का ढांचा ग्रामीण कस्बाई स्तर पर मृतप्राय है। नतीजतन शहरी स्वास्थ्य सेवाओं पर आम आदमी की निर्भरता मजबूरी बन जाती है। यह तथ्य है कि आजादी के बाद पहली मर्तबा स्वास्थ्य और संबद्ध सेवाओं पर सुव्यवस्थित ढंग से काम आरंभ हुआ है। पेयजल, स्वच्छता और आवास के तीन प्रमुख स्वास्थ्य से सम्बद्ध क्षेत्रो में मोदी सरकार ने पिछले दस साल में बुनियादी काम किए हैं। इन तीनों विषयों पर मिशन मोड में काम भी प्रगति पर है। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना ने भी स्वास्थ्य पर निजी खर्च (ओओपीई)को 63 से 40 प्रतिशत पर लाने का काम किया है। जनवरी 2025 तक 36.9 करोड़ आयुष्मान कार्ड देश में क्रियाशील है। योजना के तहत 8.5 करोड़ लोगों के इलाज पर सरकार ने 1.40 लाख करोड़ की राशि अब तक खर्च की है। इस तस्वीर के पीछे दो धब्बे भी हैं, जिन पर चर्चा नहीं हो रही है। पहला यह कि 4.3 करोड़ मरीजों के इलाज आयुष्मान के तहत निजी अस्पतालों में हुए है और सरकारी अस्पतालों में यह आंकड़ा 4.2 है। देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है, जहां आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों ने फजीवाडा नही किया हो। यानी मरीज को बिना भर्ती किए ही उसे भर्ती दिखाकर अरबों रुपये का गोलमाल हुआ है। भागवत देशभर में सतत प्रवास करते हैं और उनके कहने का सार इन्हीं विसंगतियों की ओर ही है।

Social Media Corner

सच के हक में...

सभी को नुआखाई की हार्दिक शुभकामनाएँ। यह प्रिय त्यौहार उन किसानों के प्रति हमारी गहरी कृतज्ञता का स्मरण कराता है जिनकी कड़ी मेहनत हम सभी का भरण-पोषण करती है। हर घर में उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियां बनी रहें।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

11 वर्ष पूर्व गरीबों, महिलाओं, किसानों, वंचितों के वित्तीय समावेशन हेतु मोदी जी ने विश्व इतिहास की सबसे बड़ी बैंकिंग पहल 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' की शुरूआत की। देश के उस बड़े तबके को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य हुआ, जो दशकों से इससे वंचित रहा था। आज 56 करोड़ से अधिक जन धन लाभार्थी, जिनमें लगभग 56 प्रतिशत महिलाएं हैं, बैंकिंग, बीमा, पेंशन जैसी अनेक सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ प्राप्त कर रहे हैं और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में जुटे हुए हैं।

(अमित शाह का 'एक्स' पर पोस्ट)

ये हेमंत सरकार की तानाशाही है या झारखंड पुलिस की मनमानी कि अपने समाज के लिये हक की लड़ाई लड़ने एवं सैकड़ो गरीब आदिवासी बच्चों की शिक्षा का भार संभालने वाले एक संताल आदिवासी को गलत तरीके से हिरासत में लेकर प्रताड़ित कर मार दिया जाता है, जबकि एक कुख्यात अपराधी, जिसे सुप्रीम कोर्ट, ईडी और सीबीआई सब मिलकर अपराधी घोषित कर चुके हैं, उसे गिरफ़्तार करने से झारखंड पुलिस कतरा रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, राजेश उर्फ.डाहू यादव के बारे में जो झारखंड में बालू और पत्थर के अवैध खनन व काले कारोबार का बड़ा हिस्सा चलाता है। झारखंड पुलिस को बताना चाहिए कि कहां है वो।

(बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

राहुल गांधी के झूठे दावे बेनकाब

देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इन दिनों अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगा रही है। वे उसके अधिकारियों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और निचले व्यवहार पर उतरकर उनके परिवार तक को निशाना बना रहे हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में शर्मनाक है। राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी चुनाव आयोग तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चोर कहते हुए निशाना बना रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीनों चुनाव आयुक्त सुन लें... एक दिन आएगा, जब बिहार और दिल्ली में हमारी सरकार होगी। फिर हम आप तीनों को देखेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकताओं के सोशल मीडिया हैंडल देख आप सन्न रह जाएंगे। राजनीति इतने नीचे स्तर पर गिर जाएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी की राजनीति देश में डरावने दृश्य प्रस्तुत कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस का यह व्यवहार पहली बार नहीं है। पिछले लगभग सात वर्षों से राहुल गांधी की राजनीति का एक स्थापित पैटर्न बन गया है। राहुल गांधी पहले भी कई संस्थाओं को धमकी दे चुके हैं। वे प्रधानमंत्री का नाम लेकर सार्वजनिक रूप से ऐसा कह चुके हैं कि मोदी अब सड़कों पर निकलेगा तो लोग डंडों से पीटेंगे। उनके नेतृत्व में अब कांग्रेस ऐसी राजनीति कर रही है, जिसमें मयार्दा, पद की गरिमा, भाषा की शालीनता, व्यवहार का संतुलन तथा सच और झूठ के भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे ही राहुल गांधी किसी को निशाना बनाते हैं, उनकी पूरी पार्टी उस व्यक्ति, अधिकारी या उनके खानदान को ढूंढ़ कर चरित्र हनन और बदनाम करने का अभियान चलने लगती है। डिजिटल मीडिया कई बार बहुत विषाक्त हो जाता है। इसकी अनदेखी न की जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिसरी को डिजिटल मीडिया पर किस तरह निशाना बनाया गया। निम्न राजनीति पहले सामने वाले के विरुद्ध संदेह पैदा करने के लिए कथित तथ्य गढ़ती है, फिर नारे एवं मुहावरे बनाती है। अब वह संस्थाओं को भी निशाना बना रही है। इन दिनों संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग इस राजनीति के निशाने पर है। आज पूरे देश के सामने प्रश्न है कि इस तरह के राजनीतिक व्यवहार का प्रतिकार कैसे हो। राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त सहित पूरे चुनाव आयोग को वोट चोर कह रहे हैं, लेकिन अपने आरोपों के पक्ष में कोई ठोस तथ्य नहीं दे रहे हैं। अब तो वे सार्वजनिक रूप से गलत साबित हो रहे हैं। गत दिनों बिहार में उनकी वोट अधिकार यात्रा के दौरान रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के एक गांव की रंजू देवी उनके सामने यह कहती देखी गईं कि उनका और परिवार के सभी छह लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। राहुल ने इसे वोट चोरी का मुद्दा बना दिया। बाद में उन्हीं रंजू देवी ने कहा कि मतदाता सूची में उनके परिवार के सभी लोगों के नाम हैं। उनके अनुसार वार्ड सचिव ने कहा था कि राहुल आ रहे हैं, उनके सामने बता देना कि हमारा नाम मतदाता सूची से कट गया है। उन्होंने माना कि वार्ड सचिव ने जैसा कहा, वैसा राहुल के सामने बोल दिया। यह एक प्रसंग राहुल और वोट चोरी के आरोप लगाने वालों के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। राहुल के महाराष्ट्र चुनाव संबंधी आरोप भी गलत साबित हो चुके हैं। बंबई उच्च न्यायालय संबंधित याचिका खारिज कर चुका है। महाराष्ट्र के रामटेक और देवली विधानसभा में लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा में क्रमशः 38.45 प्रतिशत तथा 36.82 प्रतिशत मतदाताओं की कमी का आंकड़ा भी गलत साबित हो गया। इसे सामने लाने वाले सीएसडीएस के चुनाव विश्लेषक ने न केवल संबंधित पोस्ट को हटाया, बल्कि गलत उत्तर देने के लिए माफी भी मांगी। इसके बावजूद वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के तेवर और भाषा देखकर लगता है कि उनका मुद्दा चुनाव आयोग या सत्ता प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि कुछ और है। लगता है वे सब कुछ पहले से निर्धारित किसी योजना के अनुसार कर रहे हैं। अध्ययन बताते हैं कि किसी संवैधानिक संस्था पर नेताओं द्वारा राजनीतिक आरोप लगाने के पीछे निश्चित उद्देश्य होते हैं।

भारत-चीन संबंध

दोनों पक्षों के बयानों और खबरों से पता चलता है कि इस हफ्ते चीन के विदेश मंत्री वांग यी की दो-दिवसीय भारत यात्रा बेहद ही सार्थक रही। वांग जहां सीमा के मसले पर 24वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के निमंत्रण पर दिल्ली आए थे, वहीं उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चार साल के सैन्य गतिरोध के बाद सामान्यीकरण प्रक्रिया के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात की। वांग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वागत किया, जिन्होंने कहा कि वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के लिए तियानजिन की यात्रा करेंगे। मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली में, भारत और चीन तीन स्थानों पर सीमा व्यापार फिर से शुरू करने, सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा स्लॉट का विस्तार करने और वीजा में ढील देने पर सहमत हुए। चीन द्वारा उर्वरकों, दुर्लभ मृदा उत्पादों और बोरिंग मशीनरी पर निर्यात प्रतिबंध हटाने पर जहां सकारात्मक चर्चा हुई, वहीं यह साफ नहीं है कि चीन की इस मांग पर कोई प्रगति हुई है या नहीं कि भारत भारतीय कंपनियों में चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की जांच को हटा ले। दोनों पक्ष 3500 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा से जुड़ी समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सहमत हुए। इस बीच चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने कहा कि चीन भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के अमेरिका के धमकाने वाले कदम का विरोध करता है। नतीजों से संकेत मिलता है कि दिल्ली ने फैसला किया है कि वह अब पीएलए के उल्लंघनों, गलवान झड़पों और गतिरोध से आगे बढ़ सकती है। जहां डोभाल ने कहा कि सीमाएं शांत हैं, वहीं सरकार को असहज रूप से इस बात से अवगत कराया गया कि सीमा पर स्थिरता आने के साथ भी, अन्य दीर्घकालिक समस्याओं की छाया आपसी रिश्तों पर पड़ती रहेंगी।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Democracy on trial: From the rule of law to rule by law

The surest way to throttle democracy is to weaponise laws and target those opposing the government. This government seems to have converted this into an art.I recall the day the amendment to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA), was taken up for discussion in Parliament. The Home Minister openly stated that this was necessary, for none could oppose the inclusion of terrorists and terrorist organisations in the First Schedule of the UAPA, seeking to destabilise our Republic. I intervened and expressed my fears that these laws are likely to be used against our citizens; it has turned out to be a reality.The prosecution of young students, like Umar Khalid and Sharjeel Imam, under those laws has resulted in them languishing in jail for years without a trial. Such laws have been used against journalists, academics, and members of religious communities in this country. The obvious intent was to silence them.The weaponisation of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) is evident in its widespread use against political opponents, including chief ministers and ministers from opposition-ruled states, such as Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Satyendra Jain, Hemant Soren, and Farooq Abdullah, among others. Valiant attempts were made to move against Siddaramaiah, but they came to nought. These laws have also been used to instil fear in several leaders who were once part of the opposition but have been persuaded to join the BJP to save themselves from prosecution and imprisonment.The BJP has, particularly in Maharashtra, rewarded opposition leaders against whom serious allegations of corruption were publicly made for causing a split in their erstwhile parties. They are now part of the coalition ruling Maharashtra.The latest example of weaponisation of laws is the introduction of two Constitution (Amendment) Bills in Parliament on August 20, 2025. It is claimed that this is being done in public interest, for the welfare of the people and to uphold the principles of constitutional morality, and good governance—concepts that are alien to the functioning of this government.What is likely to serve is not public interest, but the political interest of the ruling dispensation. This is clear from the fact that the proposed law provides that the chief ministers and ministers being investigated for offences punishable for more than five years and being in custody for more than 30 days will, on the 31st day, if they have not resigned, be dismissed by the governor of the state.The principle of law that our Republic has embraced is that a person is innocent till proven guilty. In this case, a minister or a chief minister can be removed on a mere allegation without any proof. We are all aware that many such cases have been pending trial for over a decade and that the conviction rate in several of these prosecutions is abysmally low.

If the proposed constitutional amendments become law, it is most likely that trumped-up allegations will be made to target sitting chief ministers and ministers, and after 30 days in custody, they will be dismissed from those positions. Such allegations in the past have served the political interests of the BJP. The present establishment seeks to utilise these laws for its own political purposes.This weaponisation is also evident from how laws such as PMLA or UAPA have been used against influential ministers seeking to coerce them to join the BJP, or even public servants not belonging to any political party, in opposition-ruled states.Ironically, since 2014, these laws have never been invoked against any minister in any of the BJP-ruled states, or, for that matter, against any minister within the ruling establishment at the Centre. Obviously, the selective use of such laws serves the political interest of the party in power.

The silent scourge of hysterectomy

From Dima Hasao to Jaintia Hills, who owns the region's wealth?

There is a quiet but serious epidemic in the country—hysterectomy. It is a surgical procedure involving the removal of a woman's uterus, sometimes accompanied by the removal of the ovaries, fallopian tubes and cervix. According to the National Family Health Survey 2019-21 (NFHS 5), the prevalence of hysterectomy among women aged 40-49 years was as high as nearly 10 percent. The numbers are far higher in states such as Andhra Pradesh (22.5 percent), Telangana (21.2 percent), Bihar (17.2 percent) and Gujarat (11.7 percent). More worryingly, the median age of women who had undergone hysterectomy is 34 years for rural and 36 years for urban areas, more than 10 years before natural menopause.The common reasons for getting a hysterectomy include excessive menstrual bleeding/ pain, fibroids/ cysts, and uterine disorders. While it may be sometimes unavoidable, the surgery poses serious risk to women's health by inducing early menopause. Research has established its links with increased risk of illnesses like cardiovascular disease, metabolic disorders, ovarian failure, vasomotor symptoms, thyroid cancer, urinary tract cancer, pelvic prolapse, bone density loss, and mental health issues. Therefore, it is not a procedure that should be taken lightly.

Despite such obvious health consequences, why is hysterectomy among young women in India on the rise? Data consistently indicates a higher prevalence among less educated rural women, despite the limited access to surgical procedures in rural areas. Moreover, women agricultural workers have been hit hard by this trend as they are led to believe that it avoids loss of wages and improves endurance for demanding work hours without menstrual discomfort. This is widely documented among sugarcane workers in Maharashtra's Beed district, where the prevalence was at a staggering 56 percent in 2024, with an average age of 35 years among women who migrated for work. Similar trends were observed among women agricultural workers in Telangana and Bihar, where the prevalence was 18 percent and 10 percent, respectively, according to NFHS 4.This grim choice, thought to be a short-term solution to avoid financial penalties, ironically reduces the woman's active working lifespan and quality of life because of its impact on bone mineral density and cardiovascular health, among other ailments.From global experience, we know that the structure of the medical system, the quality of medical advice and the extent of insurance coverage influence unnecessary surgeries. For instance, the prevalence of hysterectomy has always been much higher in the US (325 per 100,000 females in 2008) compared to average European OECD nations (212 in 2010), despite similar socioeconomic and health indicators.Europe's largely public healthcare system leaves less incentive for private medical practitioners for invasive procedures. In contrast, the dominant private healthcare in the US, covered by insurance, exhibits the issue of moral hazard where health insurance coverage drives overprescription of surgeries or diagnostics.

Note that as per NFHS 5, 70 percent of the hysterectomies in India were done at private clinics. Bharath Bhushan Mamidi and Venkat Rao Pulla's research, published in 2013, found in Andhra Pradesh that healthcare providers advised poor rural women as young as 20 years to have a hysterectomy even for routine gynaecological issues, such as abdominal pain and white discharge, without offering any alternatives due to the profit motive. Such nudges are common due to the lack of awareness about the importance of the womb for their overall health and longevity.In addition, insurance coverage clearly plays a role. Gaurav Gunnal and Sudeshna Roy (2024), and Angad Singh and Dipti Govil (2021) used data from NFHS 4 to show that women covered under insurance were more likely to undergo a hysterectomy. There are widespread media reports of unnecessary surgeries being done, particularly covered underCentre and state-funded insurance schemes.Taking cognisance, the National Health Authority, that administers the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, brought out a working paper in 2019 highlighting that hysterectomy claims under the scheme comprised almost 2 percent of claims for all female packages in 24 states in the first nine months (September 2018 to May 2019). The paper stressed the need for monitoring claims over time. Following this, the NHA in 2019 introduced pre-authorisation requirements for claims. For instance, a mandatory second gynaecological opinion and uploading of clinical or USG findings on the portal is required for women under 40 years.

The Union health ministry is clearly aware of this issue and noted in an advisory that "private empanelled healthcare providers are proceeding with the surgery (hysterectomy) without waiting for pre-auth approval, even after preauth processing doctor has asked a query/ clarification". In 2022, it issued guidelines on unnecessary hysterectomies, including the creation of monitoring committees at district, state and national levels to gather data on surgeries across public and private facilities.

This issue requires a multi-pronged approach. Firstly, more recent and detailed data are needed on the prevalence of hysterectomy. NFHS should include questions on how women paid for the surgery to ascertain the role of public health insurance in rising cases. Secondly, greater awareness needs to be spread among women about the harmful effects of early hysterectomy. For heavy menstrual bleeding, which is the most cited reason, conservative treatment options like hormonal contraceptive pills and hormonal IUDs need to be promoted. Lastly, there should be stricter surveillance and medical audits.It is also worth examining whether such practices are guided by the misplaced perpetuation of population control policies/ mindset, as it has implications not just for women's health but also for our demography at a time when India's fertility rate is already below replacement level.The trend of unnecessary hysterectomies highlights a deeper challenge in healthcare delivery. When private providers operate within insurance-funded systems, without transparency and accountability, there is hardly any pushback from patients as they are insured. This presents a classic case of market failure due to asymmetric information, which heavily burdens the medical system with overprescription, drives up health costs, and strains public finances.

India in right stance to face extra tariff

The urea stock with the Centre at the beginning of this month was about half of what it was last August

Those who had hoped for a last-minute pause of the additional 25 percent tariffs on Indian exports to the US would be disappointed.With no settlement signed or even negotiated, the US department of homeland security on Tuesday notified "the punitive tariffs on Indian goods entered for consumption, or withdrawn from warehouse for consumption" from 9.31 am IST on Wednesday would attract the heightened levies.The signals have been pointing in this direction. First, the US trade team, expected in India on August 25, deferred its visit. American rhetoric has been aggressive too; Vice President J D Vance on Sunday stated "aggressive economic leverage" including "secondary tariffs on India" had been applied to force Russia to stop bombing Ukraine.

It is to the credit of India that it has stood up to the armtwisting. Speaking in Ahmedabad on Sunday, Prime Minister Narendra Modi stated, "No matter how much pressure comes, we will keep increasing our strength to withstand it… The government will never let harm come the way of small entrepreneurs, farmers, livestock rearers."The government has also rightly decided to diversify its trading options. Russian crude purchases, which were suspended in July, have been resumed, with several Indian refiners placing orders for loading in September and October.While the PM called for 'self-reliance', RBI Governor Sanjay Malhotra pledged the central bank "would not be found wanting" in providing additional liquidity to guard against the tariff impact.

ndia, which has been reaching out to Russia and China, has made it clear it intends to more than double its trade with Russia, targeting $100 billion by 2030. Meanwhile, it must keep its US options open too, as the latter needs India as a counterweight to China.India has surpassed China as the top smartphone exporter with a 44 percent share of the US market, largely driven by Apple's strategy to diversify production. Indian exports to the US are at about $85 billion and cannot be replaced overnight without hurting American consumers.Peace or a pause in Ukraine could soon end the rationale behind the punitive tariffs. Thus, the expectation among some pundits that the trade talks could resume after a short hiatus is not misplaced. The government should use this period, meanwhile, to develop domestic demand and stronger, alternative regional trade routes.

Money gaming ban set to play spoilsport

The creation of a strong regulatory system could have been the first step before imposing a ban

DREAM11, RummyCircle, Pokerbaazi — these are just some of the familiar names associated with the online gaming industry. The first is well known due to its connections with cricket and football as fantasy sports games have become hugely popular. The others are linked to popular games of skill played all over the world at social and professional levels. The online versions of these and innumerable other games are played largely with real money, and this practice has now come under scrutiny.The outcome is the Promotion and Regulation of Online Gaming Act that bans all real money games (RMG) but seeks to support social and educational online games as well as electronic sports.At the outset, one must explain what defines a real money game. The new law says an RMG is any online game, which could be based on skill or chance, where a user deposits money or places a stake with the hope of winning something valuable, usually money. This is completely different from simply purchasing a game online.The passage of the law has created an uproar in the country's burgeoning real money gaming sector. Industry associations estimate that about two lakh people are directly employed by such platforms, with another one lakh in related jobs. They argue that the ban on RMG could lead to most losing their livelihoods at a time when the IT industry in general is going through a shakeout, with jobs being lost due to the advent of artificial intelligence.

The ban will undoubtedly have a devastating effect on those employed in the sector and will equally impact the government's tax revenue of Rs 20,000 crore. Venture capitalists are also worried about the $2 billion raised for investments made in this sector. Most online RMG platforms now have few options — either to shut down or pivot to the much-less-lucrative advertisement-based model. The beleaguered gaming industry may even be gearing up to make a legal challenge to the new Act.In its defence, the government claims that these gaming platforms have caused addiction and financial ruin to millions of families. It says that as many as 45 crore people have been negatively affected and faced losses of over Rs 20,000 crore because of these platforms.

The question is: what prompted the government to take such a hard line on real money gaming, after allowing the industry to carry on operations in an unchecked manner for so long? One reason given is the failure of the industry to do self-regulation. It has not been able to implement measures to safeguard players from the danger of addiction, which often leads to financial distress. In addition, there are now concerns over terror financing and money laundering being linked to RMG entities. What is unique about this legislation is the bipartisan support to it. Apparently, online gambling addiction has become such an endemic problem that politicians of all hues feel the need to protect their constituents from its disastrous impact.

Besides, it may appear as if the law has been imposed suddenly, but there were clear indications over the past two years that the industry was treading on thin ice. The Information Technology Ministry laid down rules in 2023 to allow the creation of self-regulatory bodies for online gaming. These were aimed at certifying games and blocking illegal offshore betting platforms. Such self-regulation efforts did not meet with much success.

Subsequently, Goods and Services Tax (GST) levies on the full face value of deposits in RMG were hiked to 28 per cent. Thus, the gaming industry should have been cautious, given the nudges being given to regulate RMG with more care.As for the need to protect users of these online games, even young gamers recognise the pitfalls. It starts out as a catchy game and the user is then lured into pumping more and more money into it. The suggestion of gamers, as well as of industry associations, is that the ban on RMG should be replaced by a strict regulatory framework. This is based on the premise that bans rarely work effectively. Those who are desperate to gamble are bound to move to unregulated offshore platforms to satisfy their urge to play these games.

The decision to impose an outright ban may have been influenced by revelations in the Rs 6,000-crore Mahadev online betting scam. It involved a betting platform that enabled illegal gambling on card games and sports. It engaged in match-fixing, money laundering via crypto currency and manipulating games to ensure huge profits for its UAE-based promoters.The creation of a strong regulatory system, however, could have been the first step before imposing a ban on RMG. It could have given gaming platforms some time to pivot to non-money games as well as to adopt an advertising-based model. The sheer size of the industry and the potential for India to grow into a global hub for gaming also need to be taken into account while formulating such policies.

A report by RMG platform Winzo and the Interactive Entertainment and Innovation Council gives an indication of the size of a sector considered a sunrise industry till now. It says revenues of the online gaming industry were $3.7 billion in 2024 and are expected to reach $9.1 billion by 2029. The report says India has 591 million gamers, comprising 20 per cent of the total global gaming community along with 1,900 gaming companies employing 1.3 lakh skilled professionals. What is significant in the context of the latest ban is the estimate that RMG contributed 85.7 per cent of the sector's revenue at $3.2 billion.

The new gaming law is thus a harsh step that could affect the growth of a sunrise sector. A rigorous regulatory system could have been adopted initially before deciding to go for a complete RMG ban. At the same time, the widening arc of gambling addiction and financial distress must not be allowed to expand further. For the time being, the industry must evolve to utilise the space available for promotion of social, educational and e-sports that have a huge following in India and abroad.

Swadeshi-style startups breathing life into rural economy, generating employment

Kolkata. (Agency)

India cannot be imagined without its rural hinterland and the vast rural economy is being invigourated by Swadeshi startups that are based on indigenous practices and resources. These ventures draw upon the age-old Ayurvedic practices of India. It also creates an economic ecosystem that links local farmers, women groups, small entrepreneurs. The resources, practices, consumers and markets are India's own having drawn nourishment from the centuries-old traditions of India.

A significant part of the raw materials and resources are medicinal plants such as tulsi, neem, turmeric, ashwagandha etc. These are cultivated organically and numerous village-based processing units turns them into extracts, oils and powders. apart from linking producers, processors and users, these ventures provide an invaluable service to the economy — they prevent migration of workers from the rural areas to the cities. It is achieved by generating employment for both males and females at the village level from production to processing from packaging to delivery and sales of the products in the countryside.

The wellness and agrifood sectors are two domains where these startups are becoming active quickly.Grassroot-level employment

Developing job opportunities at the grassroots level is the key challenge of policymakers. Ayurveda-driven startups serve this purpose well by generating livelihoods at the local level. The process starts with the cultivation of medicinal flora. Medicinal plants offer a way of crop diversification for the local farmers. Once the crop is harvested, the raw material moves to processing plants where they offer employment opportunities to local women. Young men from the villages also find employment in these units.

The model can also work in large-scale units which Patanjali has proved. This company has adopted organic cultivation. The net result of this model: farmers get more remunerative prices for their crops.

Challenges for the sector

Needless to say, like any other industry sectors, swadeshi startups too face difficulties. The obstacles typically relate to the financing and technology, both of which are required to scale up these units. Another challenge is maintaining uniform quality standards. For some products certification needs are also there.

Also in these startups formal training is one of the vital needs that are not widely found. If these gaps can be addressed, vast opportunities wait for this sector. Rural incubation programs are gradually coming up to offer a platform to rural entrepreneurs. The two basic requirements are hand holding of the entrepreneurs for the initial years and providing them access to markets.

AIF commitments surge past Rs 14.2 tln; funds deployments nears Rs 6 tln

MUMBAI . (Agency)

Despite the Reserve Bank capping investments by banks and other financial institutions in alternate investment fund (AIF) schemes at 10%, overall investor commitments to AIFs rose 20% on-year to a record Rs 14.2 trillion as of June 2025, with funds raised touching Rs 6 trillion and deployments from such funds crossing Rs 5.72 trillion, according to Sebi data.

The AIF industry has been rocking with the rising inclination of ultra high-networth individuals and family offices to deploy their monies in high yielding investment options like AIFs. These schemes have gained traction also because of their ability to diversify investments in early stage startups, unlisted assets, and complex trading strategies. As a result the total commitments for AIFs surged to Rs 14.2 trillion as of June 2025, which is a 20% jump on-year and 5% growth sequentially.

Also, total funds raised inched closer to Rs 6 trillion mark while total investments made through such funds rose to Rs 5.72 trillion, according to the latest data from the Securities and Exchange Board (Sebi).AIFs are pooled investment vehicles catering to the niche segment with high entry investments. Recently, the market regulator has pushed for accreditation among investors for certain schemes.Category II AIFs focus on private equity, debt, and other unlisted assets, continue to dominate the segment with highest commitments at Rs 10.78 trillion. But of late there is also a rising inclination towards category III AIFs which include hedge funds. According to the report by the industry

association IVCA, category III AIFs accounted for 47% of the total launches this financial year so far.In terms of investments, real estate is the largest accounting for nearly 12.5%, followed by financial services, IT, NBFCs, and banks.It can be noted that in early June, the Reserve Bank, which has been frowning upon the mushrooming of AIFs for quite sometimes, has capped the cumulative investments by banks, non-banks and all-India financial institutions at 10% of their corpus of any single entity exposure 20%. The new directions will be in force from January 1, 2026 and will apply to all banks, cooperative banks, non-banks.

India on track to become 2nd largest economy by 2038: Report

New Delhi. (Agency)

India could become the world's second-largest economy by the year 2038, reported EY. With strong economic fundamentals, a young population, and a sustainable fiscal position, India is expected to continue its robust growth despite global uncertainties.

The report, called the 'EY Economy Watch', mentioned that if current growth trends continue, India may become the world's second-largest economy by 2038 in PPP terms, with a GDP projected at $34.2 trillion.WHY IS INDIA DOING SO WELL?

Unlike many other big economies in the world, India has some unique advantages. The average age of people in India in 2025 is just 28.8 years. This means there's a huge number of young, working people who can drive the economy forward for

decades.Further, India has the second-highest savings rate among the world's largest economies. This is great because it means more money is available for big projects and new businesses.Moreover, the government's borrowing is actually going down. While other countries are seeing their debt pile up,

India's debt-to-GDP ratio is expected to fall from over 81% in 2024 to about 75% by 2030.The report also mentions that India's strong economy doesn't rely too much on what's happening in other countries. Our huge domestic market means people within India are buying and selling things, which keeps the economy healthy even when global trade is slow.

WHAT ABOUT THE REST OF THE WORLD?The report compares India to other major economies like the USA, China, Germany, and Japan. While they are all very successful, they face some big challenges that India doesn't. For example, China is dealing with an ageing population, and the USA has a lot of debt. Germany and Japan also have older populations and are very dependent on global trade, which can be a risk.

In simple terms, India's mix of a young population, high domestic demand, and good financial health gives it the most promising path for long-term growth.According to EY India's Chief Policy Advisor, DK Srivastava, the country's strong points will help it grow even when the world economy is facing problems. He says India is well on its way to achieving its goal of becoming a "Viksit Bharat" (developed India) by 2047.India is also expected to become the third-largest economy in market exchange rate terms by 2028, surpassing Germany. Even potential disruptions, like US tariffs affecting 0.9% of GDP, are projected to have only a minor impact on growth if countered with export diversification and stronger domestic demand.

With a combination of a young population, rising domestic consumption, fiscal discipline, and structural reforms, India appears well-positioned to climb the global economic ladder in the coming decades.

Why is Trump targeting India with tariffs? Raghuram Rajan explains

New Delhi. (Agency)

Former Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan has said that US President Donald Trump's decision to impose steep tariffs, including a 50% duty on Indian goods, is part of a wider strategy that goes beyond trade economics.Speaking to Rajdeep Sardesai, Consulting Editor, India Today TV, Rajan explained that tariffs are being used not only as a trade tool but also as a means of exerting political and economic power.

He added that tariffs were also increasingly being seen as a tool of force.

"It can be a way for the US to essentially use force when it doesn't want to use its military," Rajan said. He cautioned that the outcome is often that "other countries suffer."IS INDIA BEING SINGLED OUT?Rajan said there were several reasons behind Trump's tariff push. "I think certainly he believes that a current account deficit, trade

deficit is evidence that other countries are taking advantage of the United States rather than sending goods cheaply to the United States, which the US consumer benefits from," he said.According to him, Trump has held this view since the 1980s, when he was critical of Japan. Rajan pointed out that the former US President sees tariffs as a way to "level the playing field."Another reason, Rajan noted, is Trump's belief that tariffs act as a tax on outsiders rather than on US consumers. "Therefore it's a cheap way of getting revenues, which can then help offset some of the tax cuts that he has made," Rajan said.When asked if India had been targeted more harshly than other Asian nations, Rajan agreed. "It is. I think there's no true questions about that," he said.He explained that India was initially in discussions to be placed in the same tariff category as other Asian countries, with rates of around 20%.

GST 2.0 boost for textile, fertiliser sectors as Trump's 50% tariff kicks in

New Delhi. (Agency)

The government is preparing a fresh round of changes to the Goods and Services Tax (GST) structure, with a focus on sectors that are under pressure after the United States imposed a 50% tariff on Indian exports.The textile and fertiliser industries are expected to be among the biggest beneficiaries of the upcoming GST 2.0 rationalisation, as the Council looks to ease costs, improve competitiveness, and resolve long-standing issues of inverted duty structures.

TEXTILES TO SEE MAJOR RELIEF

In the textile sector, the fitment committee has recommended a steep cut in GST rates across several categories. Woven fabrics of cotton, man-made fibres, wool, apparel, hosiery, and some blended textiles are being considered for a reduced 5% rate, down from the current higher slabs.Industry associations have long argued that higher tax on inputs compared to finished garments creates a blockage of working capital, making it harder for small weavers, powerloom operators, and garment makers to stay competitive.

Lowering GST will reduce this imbalance, ease cash flow pressures, and make Indian textiles more attractive in global markets at a time when exports are already facing headwinds due to the US tariff.

FERTILISER RATE CUTS TO EASE COSTS

Beyond textiles and

The fertiliser industry is another major focus area. The GST Council is weighing a reduction in tax on key inputs, including urea, diammonium phosphate (DAP), muriate of potash (MOP), single super phosphate (SSP), and complex fertilisers.The proposal is to bring the rate down from 12% to 5%.Officials say this move will reduce production costs for fertiliser companies, lower the subsidy burden for the government, and make essential farm inputs more affordable for farmers.It will also fix the inverted duty problem, where raw materials are taxed more heavily than the finished product, leading to refund delays and blocked funds for businesses.

BROADER RATE RATIONALISATION

Beyond textiles and fertilisers, the GST Council is also expected to approve several consumer-friendly changes at its 56th meeting in New Delhi on 3–4 September. These include widening the nil rate slab, lowering the 12% slab, and reducing rates on selected 18% goods.As part of the proposals, several everyday food products may soon attract no GST.This includes UHT milk, pre-packaged paneer (chena), pizza bread, khakhra, chapati, and roti. Paratha and parotta, which were earlier taxed at 18%, are also being considered for the nil rate as suggested by the Group of Ministers on rate rationalisation.

Cheaper milk, chocolates, clothes and more: How GST 2.0 could slash your bills

New Delhi. (Agency)

The Goods and Services Tax (GST) Council is preparing some major changes under GST 2.0 that could reduce costs for households, students, farmers, and businesses.The proposed changes, to be discussed at the Council's meeting on September 3–4 in New Delhi, focus on widening the nil rate, lowering the 12% slab, and reducing rates on selected 18% goods.MORE TAX FREE ITEMSThe GST Council is likely to expand the nil tax slab, bringing a range of essential products under zero GST. Everyday food items such as UHT milk, pre-packaged paneer (chena), pizza bread, khakhra, chapati, and roti are expected to move from the 5% and 18% slabs to zero. Paratha and parotta, previously taxed at 18%, are also included in the proposed nil rate, according to the Group of Ministers on Rate Rationalisation.Education-related items are also set to benefit. Maps, atlases, globes, printed charts, pencil sharpeners, pencils (including crayons, pastels, tailor's chalk, and drawing charcoals), exercise books, graph books, and laboratory notebooks could move from the 12% slab to nil. If approved, these changes

would provide relief for households and students while simplifying GST compliance and improving transparency.

MANY ESSENTIALS AND TREATS TO GET CHEAPER

Several commonly purchased foods may see GST reduced from 12% to 5%. Proposed items include butter, condensed milk, jams, mushrooms, dates, nuts, and namkeens. These changes are expected to lower prices for families and benefit bakeries, sweet shops, and packaged food manufacturers.Butter and condensed milk—widely used in cooking and desserts—are likely to see noticeable price reductions. Similarly, jams, namkeens, mushrooms, and dry fruits such as dates and nuts would become more affordable. The move is part of the Council's effort to remove the 12% slab and streamline GST into fewer, clearer rates for mass-consumption goods.

Chocolates with cocoa, cereal flakes, pastries, and ice cream, currently taxed at 18%, are proposed to fall under a 5% rate. This would lower prices for common breakfast items and everyday indulgences, as well as pastries, which are central to India's bakery and caf culture. The changes aim to make the indirect tax system more uniform and reduce inflationary pressures on frequently purchased products.

BIG BREAKS FOR TEXTILES AND FERTILISERS

The textile sector could see GST cuts on woven fabrics of cotton, man-made fibres, wool, apparel, hosiery, and blended textiles, with rates reduced to 5% from higher brackets. The reduction is expected to ease working capital constraints, boost exports, and make fabrics and clothing more affordable in the domestic market.In agriculture, key fertilisers—including urea, diammonium phosphate (DAP), muriate of potash (MOP), single super phosphate (SSP), and complex fertilizers—may move from the current 12% slab to 5%. Lower rates would reduce cultivation costs for farmers, extend subsidy efficiency, and simplify the tax structure for manufacturers.The proposed changes reflect the government's aim to rationalise the GST rate structure, reduce the number of slabs, and resolve classification issues. Expanding the nil slab and eliminating the 12% rate could simplify compliance, provide savings for consumers, and support businesses without significantly affecting overall GST collections.The final decision rests with the GST Council at its meeting in early September. If approved, GST 2.0 could introduce a simpler, more transparent tax system and provide tangible savings on essentials .

Scholarships, work prospects — and Chinese dramas: Mandarin finds new takers in Delhi

New Delhi. (Agency)

On a humid August day at MeiYu Chinese Centre in Delhi's Karol Bagh, a native Mandarin teacher, Claire Laoshi, guides a group of beginner-level students through simple sentences. "Wo he kafei," she says. "It means I drink coffee."

The students repeat it as she explains how he means drink and that adding le turns the action into the past tense.

She then introduces a practical scenario. "If your colleague asks you in the morning, 'Did you drink coffee?' you can answer, 'Wo he le (I drank)'…," she says. "In Chinese, the adverbs always go with adjectives."

The students nod, as they jot down the grammar lesson — some writing down the structure: Subject + Verb + Object. "Next Saturday, when I ask you if you did the homework, you will say, 'Wo xie le (I wrote it),'" says Laoshi. The next sentence is tougher. "Ta men ti zuqiu (they play football)." Some stumble at first, until the teacher pronounces zuqui as dzoo chyoh.

By the end of the lesson, the students are familiar with simple Mandarin greetings.

"A says 'Ni hao', B replies 'Ni hao ma?'…" Laoshi demonstrates.

One by one, the students respond: "Wo hen hao. Ni ne? (I'm fine. How are you)?" — marking their first attempt at a tiny dialogue in Mandarin.

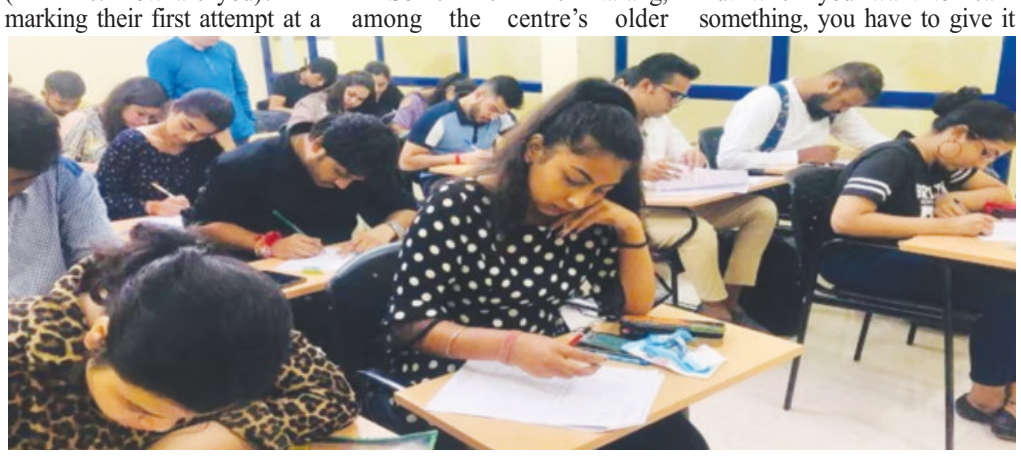

They are part of the HSK 1 (Hanyu Shuiping Kaoshi or Chinese Proficiency Test) batch at the centre. It comprises 10 students, mostly in their 20s.

Mandarin has been steadily gaining popularity in the city among those seeking foreign scholarships and global career prospects.

According to data shared by Mandarin instructors in Delhi-NCR, learners come from a wide range of professional backgrounds: around 55% are corporate professionals, 25% are business owners from manufacturing and export sectors, and around 20% are university students or young professionals aiming to study or work abroad.

Some like Princi Narang, among the centre's older students, were drawn to the language through social media and Chinese Dramas.

A digital marketing professional, the 21-year-old says she started learning Mandarin in May 2023. She initially travelled from her hometown in Muzaffarnagar to Delhi for classes, later shifting to Noida for convenience.

"I became interested in the language because of short reels on Instagram and binge-watching Chinese dramas. The characters and phrases fascinated me, and I thought — why not learn the language?" she says. Narang has since progressed to the HSK 4 level.

She adds, "Initially, it was overwhelming — tones, characters, sentence structures. But when you want to learn something, you have to give it your all. My sister's friends told me that Mandarin has great career opportunities, so it kept me motivated."Learning the language has helped her secure the Huayu Enrichment Scholarship to study at Ming Chuan University, which she will join later this year.

At Han You Chinese Language Institute in South Delhi's Hauz Khas, batches are limited to 15-20 students. The co-founder, Arun Jaiswal, says that it is a deliberate choice as language learning requires individual attention and a focused approach. Noting that Mandarin has been gaining popularity, he adds that awareness is still limited.

"People are fascinated, but ultimately, they approach it from a career perspective," says Jaiswal. "Chinese is a highly practical language and can be very rewarding, offering excellent salary packages."

Earlier, job opportunities for those proficient in Mandarin were largely thought to be limited to tour guides or the tourism industry. But now, Jaiswal notes, the scope has significantly expanded to include roles such as interpreters, translators, positions in multinational companies, the travel industry, embassies and diplomatic missions, as well as government-linked posts.

The institute itself has come a long way from when it started with six students in 2018. "Initially, foreign languages were a niche… We wanted to focus on one language properly. Over the years, we evolved, added courses, and adjusted to student needs," he adds.

Many college students are also choosing Mandarin over traditionally popular options like French and German.

At Delhi University, Prof. Payal Maggo, Director of the School of Open Learning (SOL), points to a university-led survey that highlighted the growing interest in Mandarin.

'City has over 300 villages': PIL seeks HC directions to implement Delhi Panchayati Raj Act

New Delhi. (Agency)

The Delhi High Court on Thursday sought a note from the Delhi government on the legislative history of the Capital, and also asked if the provisions of Delhi Panchayat Raj Act are applicable or if it stands repealed.

The bench of Chief Justice DK Upadhyaya and Justice Tushar Rao Gedela was dealing with a public interest litigation by Satish Aggarwal, former vice-president of Akhil Bharat Hindu Mahasabha, seeking the court's directions to the authorities to immediately implement the Delhi Panchayati Raj Act in the villages of NCT of Delhi.

Submitting that the Act has been in existence since 1954 with elections to Delhi's panchayats held only up to 1989, the PIL claims that the municipal corporations in the Capital have "encroached upon the territorial jurisdiction of gaon panchayats, and municipal laws are being applied to rural areas/villages of Delhi", depriving villagers of their constitutional rights, including of self governance.

> As per the available data, it added. more than 300 villages are notified as rural or partially urbanised, where residents are engaged in agriculture and other "allied village activities".

The PIL has also claimed that Delhi, despite being a union territory with a legislature, has failed to implement the Panchayati Raj system in its village areas, and contrary to general perception of the city being entirely urban, "several notified rural villages still exist in the National Capital Territory". As per the available data, it added. more than 300 villages are notified as rural or partially urbanised, where residents are engaged in agriculture and other "allied village activities".

2 members of Lawrence Bishnoi gang arrested in Delhi after exchange of gunfire

> The Delhi Police said the arrested men are associated with US-based Harry Boxer, who claimed to have commissioned the firing outside comedian Kapil Sharma's cafe in Canada.

New Delhi. (Agency)

Two members of the Lawrence Bishnoi gang were arrested after a brief exchange of fire in Delhi's New Ashok Vihar area late Wednesday night, the police said.

The police identified the arrested men as Kartik Jhakkad and Kavish, who allegedly work for US-based Harry Boxer, who claimed to have commissioned the recent firing outside comedian Kapil Sharma's cafe in Canada's Surrey.

According to the police, Sub Inspector Vijender received information about the presence of Jhakkad, a key henchman of Boxer."A team led by Inspector Sanjay Gupta and Inspector Pawan reached the area and spotted two suspicious men on a bike. When they were asked to stop, the pillion rider opened fire," a Special Cell officer said.

The police recognised the man on the pillion as Jhakkad and fired back in self-defence as the accused tried to escape. "One of the bullets struck Jhakkad's left leg, causing the bike to become unbalanced. Both accused were then detained. The bike rider was identified as Kavish, who had recently joined the Boxer gang," the officer said.

Jhakkad, the police said, has more than 10 cases against him, including that of extortion. "He recently demanded Rs 2 crore from a businessman at Ganga Nagar in the New Ashok Vihar area. The reason for the presence of the two in the capital is being probed," the officer added.

Boxer, who hails from the Alwar district in Rajasthan, is known to be close to Bishnoi's brother Anmol and is believed to have reached the United States via 'dunkey' route in 2024.

"The Bishnoi gang has used him to oversee their extortion business both in the US and in Punjab, Delhi and Rajasthan. He allegedly called a businessman in GTB Enclave on August 23 and on August 25 to demand an extortion payment of Rs 5 crore," the officer said.

Bishnoi is currently housed in a high-security cell at Sabarmati Central Jail in Ahmedabad. Despite being imprisoned, he has been connected to several high-profile crimes, including the murder of Punjabi singer Sidhu Moose Wala in 2022 and threats against actor Salman Khan.

Soon, apply for a marriage certificate or driver's licence — on WhatsApp

New Delhi. (Agency)

Need to apply for a marriage certificate, caste certificate, or driver's licence? Soon, Delhi residents will be able to access all these services through their phone — via WhatsApp.

Officials said the Delhi government is planning to launch the initiative called 'WhatsApp governance', and residents will be able to apply for services, verify documents, and download certificates — all from the comfort of their homes.

"Through this service, citizens of Delhi can avail multi-departmental services from the convenience of their WhatsApp account, without the need for additional applications or physical visits to government offices, thereby improving accessibility, transparency, and governance efficiency," said a senior official.

The previous AAP government had launched a similar "doorstep delivery"

scheme, which provided access to more than 30 services — across government departments — from the convenience of a person's home. The Indian Express reported in June that the scheme, which has been inactive for over a year, is likely to be discontinued soon.

"For the past year, people have struggled with long queues and touts just to get basic certificates. To ease this, the government is working to launch the 'WhatsApp Governance' initiative, using AI and modern technology to make public services more accessible," said a senior government official.

The new project aims to strengthen citizen service delivery by integrating key services with the WhatsApp platform using its API and Generative AI (Gen AI) capabilities, a senior official said.

How will it work?

Officials said initially, 25-30 services available on the district portal and other departments will be added to the WhatsApp governance platform. More services will be added gradually.

They explained: "A dedicated mobile number will be generated for the platform. Citizens can send a 'Hi' to the number on WhatsApp to begin the process. They will be directed to different departments where they can apply for a service and fill out forms. Following a verification process, the certificates can be downloaded from WhatsApp through a QR code."

Day after ED raids at home, AAP's Bharadwaj alleges coercion, tampering of statements

New Delhi. (Agency)

A day after Enforcement Directorate (ED) carried out searches at his residence, Aam Aadmi Party's (AAP) Delhi unit chief Saurabh Bharadwaj on Wednesday accused the central probe agency of coercion, tampering with his statement, and seizing public documents as "incriminating evidence". Delhi BJP president Virendra Sachdeva later countered Bharadwaj's allegations, claiming that he was trying to deflect the attention.

The ED action against Bharadwaj has stemmed from an FIR registered by Delhi's Anti-Corruption Branch (ACB) on June 26, which had alleged cost escalations and corruption in the construction of hospitals across the Capital.

Addressing a press conference at the party office, Bharadwaj on Wednesday carried a printer of his home as "evidence," claiming that it contained logs of the original statement he gave to ED officers.

"Today I will expose an agency — the Enforcement Directorate — that has been spreading terror in India for several years," he said.

The ED officials, he said, questioned him for nearly 14 hours on Tuesday and pressured him to sign a "doctored statement". "I answered 43 questions calmly, but when I accused L-G VK Saxena of hatching a conspiracy against me, the officers refused to record my words. They cut out entire portions and returned with a 'pre-written script' asking me to sign," the AAP leader alleged.

He further claimed that ED seized only two documents from his residence — his election affidavit and an affidavit filed by the Delhi Health Department in the High Court. "Both are public documents. Yet, in the seizure memo, my election affidavit — available to the whole world — has been called 'incriminating'," he said.

The AAP leader also alleged that witnesses produced during the searches were "ED's own people". He said officers intimidated him and his family, warning he could be arrested that night.

"They kept creating fear… They told me, 'This is good for you, agree to what we are saying.' I told them clearly: it is not your job to want my good. Your job is only to send me to jail," he said. The AAP leader also questioned ED's claim of raiding 13 of his premises.

Delhi Police bust human trafficking ring, rescue 3 children from J-K

New Delhi. (Agency)

The Delhi Police recently busted a network of agents allegedly targeting minors and labourers at railway stations and transporting them to Jammu and Kashmir for exploitation as domestic workers and bonded labourers. They rescued three minors, arrested four men and are looking for more members of the network.

The police probe began in December 2024, when a woman complained at the Bhalswa Dairy police station that two children were missing: her 15-year-old daughter and her 13-year-old friend, who lived in the neighbourhood.

"The 15-year-old left her house in anger after he parents scolded her. She asked her friend to accompany her," a police officer said.

The probe made no progress for the next seven months. Then in June, a man from Jammu contacted the local police, saying that a girl had contacted him on Instagram.

"The man claimed that he had been talking with a girl from Delhi for months on Instagram. He said she had then suddenly contacted him using another number registered in Jammu," a police officer said. The police found out that it was the 15-year-old girl who had left her Bhalswa Dairy home in December.

The police then tracked the number and found that it belonged to a woman working as a maid in Jammu. "The two girls who disappeared from Delhi were working as domestic help with the maid at a house in Jammu. They were trafficked from Delhi," a police officer said.

On June 15, the police conducted a raid at the house in Jammu and brought back both the girls.

Hareshwar Swami, Deputy Commissioner of Police (Outer), said, "Their statements before the Child Welfare Committee (CWC) revealed that they were lured by traffickers from the Old Delhi railway station, transported via Jammu, and forced into unpaid domestic work in Srinagar."

On August 14, based on technical surveillance, the police arrested Suraj, 31, a resident of Begampur, who was allegedly transporting children to Jammu at the behest of Delhi-based agents. On Suraj's instance, the police arrested another man, Salim.

"Upon interrogation, Salim disclosed that he runs an agency in the name of V A Manpower Private Limited, Bemina, Srinagar, through which he trafficked nearly 500 people in the last two years, charging huge commissions per victim," DCP Swami said.

On August 19, the police took Salim to Srinagar and conducted a raid, leading to the arrests of two other agents, Md Talib and Satnam Singh. On their instance, the police rescued another 16-year-old victim.

Visa fraud busted in Delhi: 19 from Nepal lured with jobs in Serbia, duped of Rs 70 L; 2 held

New Delhi. (Agency)

Last April, Sujan Khadka (22), a Nepalese national, along with 18 of his fellow countrymen, thought that they were on the brink of an opportunity of a lifetime. He had met a man named Jayakab in Northeast Delhi's Seelampur who allegedly lured them with job opportunities in Serbia. He said that all the formalities would be taken care of by him.

"To win their confidence, he showed scanned copies of purported Serbian employment visas and job offer letters, thereby convincing the victims of the authenticity of his claims," a police officer said.

It was a well-planned fraud with Jaykab and his associate, Rupesh, allegedly duping the 19 aspiring job seekers of Rs 70 lakh as part of "visa processing fees", the Delhi Police said. The duo were nabbed on Tuesday.

According to the police, on August 22, a written complaint was received by the team of Crime Branch (Eastern Range) from Khadka. "A Nepali national, currently residing at Neel Gagan Hotel, Paharganj, alleged that he, along with 18 other Nepali citizens, had been duped by a fraudulent visa racket allegedly operated by Jayakab," DCP (Vikram Singh) said. Jaykab, after taking the 19 men into confidence, took their Nepali passports for visa processing last April, the police said. Over a month later, Jaykab allegedly demanded that the 19 Nepali nationals pay €3,500 each for the processing of the documents. "Acting on the instructions of the accused, all 19 victims travelled from Nepal to Delhi in July, hoping they could collect their passports, Serbian visas and board their onward flights," DCP Singh said. However, once they reached India, Jaykab started avoiding them, the police said. After staying in lodges in India for over a month, the Nepali citizens finally tracked Jaykab to his Seelampur residence, where he threatened them and flatly refused to return their money, the police said.

"Acting on inputs, the Crime Branch team arrested Jayakab (41) from Noida and found Serbian visas shown by the accused were forged and fabricated," DCP Singh said.

During questioning, Jayakab revealed the involvement of his associates Sachin, George aka Bijoj and Rupesh. Rupesh was then arrested from Trishul Colony in Chhawla, the police said. Further investigation to arrest the other accused is ongoing, officers added.

Pope demands end to 'collective punishment' and forced displacement of Palestinians in Gaza

ROME. (Agency)

Pope Leo XIV demanded Wednesday that Israel stop the "collective punishment" and forced displacement of Palestinians in Gaza as he pleaded for an immediate and permanent ceasefire in the besieged territory amid preparations by Israel for a new military offensive.Leo was interrupted twice by applause as he read aloud his latest appeal for an end to the 22-month war during his weekly general audience attended by thousands of people in the Vatican's auditorium.History's first American pope also called for the release of hostages taken by Hamas in southern Israel, 50 of them remain in Gaza and for both sides and international powers to end the war "which has caused so much terror, destruction and death.""I beg for a permanent ceasefire to be reached, the safe entry of humanitarian aid to be facilitated and humanitarian law to be fully respected," Leo said. He cited international law requiring the obligation to protect civilians and "the prohibition of collective punishment, indiscriminate use of force and the forced displacement of the population."Palestinians in Gaza are bracing for an expanded offensive promised by Israel in some of the territory's most populated areas

including Gaza City, where famine has been documented and declared.Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said Israel will launch its Gaza City offensive while simultaneously pursuing a ceasefire, though Israel has yet to send a negotiating team to discuss a proposal on the table.

He has said the offensive is the best way to weaken Hamas and return hostages, but hostages' families and their supporters have pushed back, saying it will further endanger them.Hamas took 251 hostages on Oct. 7, 2023, in the attack that also killed about 1,200 people. Most hostages have been released during previous ceasefires or other deals. Israel has rescued eight hostages alive. Of the 50 still in Gaza, Israeli officials believe around 20 are still alive.

Leo drew attention to a joint statement by the Latin and Greek Orthodox patriarchs of Jerusalem, who announced that the priests and nuns in the two Christian churches in Gaza City would stay put, despite Israeli evacuation orders ahead of the Gaza City offensive. They said the people sheltering in the churches were too weak and malnourished to move and that doing so would be a "death sentence."

The Holy Family Catholic church and the Saint Porphyrius Orthodox church have sheltered hundreds of Palestinian civilians during the war, including elderly people, women and children as well as people with disabilities. Pope Francis, even during his final days in the hospital, stayed in daily touch with the parish priest of Holy Family to offer his solidarity and support to the people there, cared for by the nuns of Mother Teresa's Sisters of Charity religious order.

In their joint statement, Catholic Cardinal Pierbattista Pizzaballa and Orthodox Patriarch Theophilos III noted that just last weekend, Leo issued a strong statement about the rights of people to remain in their homelands and not be forced to move."

All peoples, even the smallest and weakest, must be respected by the powerful in their identity and rights, especially the right to live in their own lands; and no one can force them into exile," Leo said in comments Saturday to a group of forced refugees from the Indian Ocean archipelago Chagos that were clearly destined for a broader audience.Netanyahu has said Gaza's population should be relocated to other countries through what his government has described as voluntary emigration.

Mass Russian drone and missile attack kills three and injures 24 in Kyiv

KYIV. A mass Russian drone and missile attack on Ukraine's capital early Thursday killed at least three peope and injured 24, local authorities said.Among the dead was a 14-year-old girl, said Tymur Tkachenko, the head of Kyiv's city administration, citing preliminary information. The numbers are expected to rise.A five-story residential building in the Darnytskyi district was hit directly. "Everything is destroyed," Tkachenko said. A strike in central Kyiv left a major road strewn with shattered glass.The attack affected over 20 locations across the capital, local authorities said. Rescue teams were on site to pull people trapped underneath the rubble.Thursday's attack is the first major combined Russian mass drone and missile attack to strike Kyiv since U.S.

Trump's trade adviser Peter Navarro blames India for prolonging Ukraine war, calls it 'Modi's war'

WORLD. (Agency)

White House Trade Advisor Peter Navarro has stirred another controversy by calling the Russia-Ukraine conflict "Modi's war," blaming India's continued oil trade with Moscow for prolonging the conflict.In an interview with

Bloomberg, Navarro accused India of undercutting global efforts to isolate Russia. He claimed that India's discounted oil purchases from Russia are indirectly forcing the US and Europe to fund Ukraine's defense."Ukraine comes to us and Europe and says give us more money.

Everybody in America loses because of what India is doing. Consumers lose, businesses lose, workers lose because of high Indian tariffs. And the taxpayer? They fund Modi's war," said Navarro.

He also slammed India for asserting its sovereignty in energy decisions, calling the stance "arrogant.""India, you're the biggest democracy in the world. Act like one. Side with the democracies," Navarro urged, taking a jab at India's ties with Russia and China, whom he labelled "authoritarians."Navarro's remarks follow the implementation of steep 50% tariffs on Indian goods by the Trump administration, half of which he says are tied to India's oil and arms imports from Russia.India's Ministry of External Affairs called the move "extremely unfortunate," emphasizing that its energy decisions are market-driven and essential for securing fuel for its 1.4 billion people.External Affairs Minister S. Jaishankar hit back, pointing out the hypocrisy in Washington's stance."We are not the biggest buyer of Russian oil, that's China. Nor of LNG, that's the EU. We were actually encouraged to stabilise global energy markets, including through Russian oil purchases.

'Nuke India', 'Kill Donald Trump' scribbled on gun used in Minneapolis Catholic school shooting that killed two children

WORLD. (Agency)

A gunman who opened fire through the windows of a Catholic church in Minneapolis and struck children celebrating Mass during the first week of school had the words "Nuke India" and "Kill Donald Trump" inscribed on his weapons, according to video footage circulating online.

The shooter, identified as Robin Westman, 23, of Minnesota, opened fire at the Annunciation Catholic School on Wednesday, killing two children aged 8 and 10, and injuring 17 others.Westman reportedly died by suicide shortly after the attack.Footage shared on social media appears to show Westman displaying a cache of weapons, including rifles, handguns, and loaded magazines.The phrase "Nuke India" was clearly visible in white lettering on one of the firearms. The magazines were marked with other inflammatory messages such as

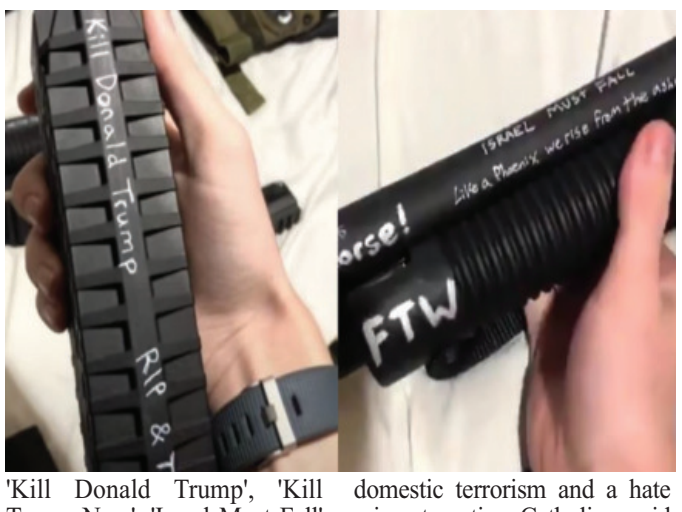

'Kill Donald Trump', 'Kill Trump Now', 'Israel Must Fall' and 'Burn Israel'.At least two videos were uploaded to a YouTube channel titled "Robin W" prior to the attack. One of the videos, approximately 10 minutes long and shot on a mobile phone, displayed several firearms and large quantities of ammunition.The Federal Bureau of Investigation (FBI) is treating the incident as an act of domestic terrorism and a hate crime targeting Catholics, said FBI Director Kash Patel. He confirmed the shooter's identity as Robin Westman, who was born as Robert Westman.

According to court records, Westman legally changed name and gender in 2020 and identified as a transgender woman.The incident has reignited debate in the United States over the easy availability of firearms and the increasing frequency of school shootings.

According to the Gun Violence Archive, there have been at least 287 mass shootings in the country this year alone.In a post on social media platform X, Homeland Security Secretary Kristi Noem described the attack as "unthinkable" and noted that the suspect was "claiming to be transgender."However, Minneapolis Mayor Jacob Frey urged restraint in public discourse, warning against the scapegoating of transgender individuals. "Anybody who is using this tragedy as an opportunity to vilify our trans community, or any other community, has lost their sense of common humanity," he told reporters."We have more guns in this country than people. We can't continue to express outrage after every shooting and then allow it to happen again and again," he added.

Trump administration to change H1B programme, Green Card process

WASHINGTON. (Agency)

The Trump administration is planning to change the H1B programme, the most sought after non-immigrant visa among Indian IT professionals, and also bring changes to the Green Card process, US Secretary of Commerce Howard Lutnick has said."I'm involved in changing the H1B programme. We're going to change that programme, because that's terrible," Lutnick said in an interview to Fox News on Tuesday.He added that the Trump administration is also going to change the Green Card process that provides permanent residency in the US.

"You know, we give green cards. The average American makes USD 75,000 a year, and the average green card recipient USD 66,000, so we're taking the bottom quartile, like, why are we doing that? That's why Donald Trump is going to change it. That's the Gold Card

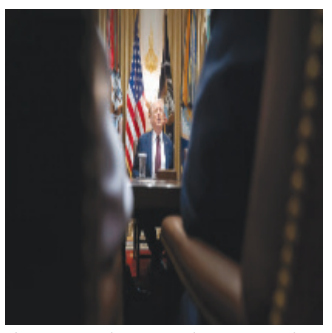

that's coming. And we're going to start picking the best people to come into this country. It's time for that to change," he said.

Indians are the main beneficiaries of the H-1B visas, which bring in the best of the talent and brains from across the world.

Highly skilled professionals from India walk away with the overwhelming number of H-1B visas, which is Congressional-mandated 65,0000 every year and another 20,000 for those who received higher education from the US.

In a social media post on Tuesday, Lutnick said, "The current H1B visa system is a scam that lets foreign workers fill American job opportunities. Hiring American workers should be the priority of all great American businesses. Now is the time to hire American."Florida Governor Ron DeSantis said in an interview to Fox News that the H1B has become a "total scam."

"These companies game the system. You have some of these companies that are laying off large numbers of Americans while they're also getting new H1Bs and renewing H1Bs," he said.

DeSantis said that people used to say that America is getting the "cream of the crop "from all around the world through the H1B visa system.""The reality is that's not actually what H1B are. Most of them are from one country, India. There's a cottage industry about how all that people make money off this system.

A shooting at Minneapolis Catholic school kills two children, injures 17 people

MINNEAPOLIS. (Agency)

A shooter opened fire with a rifle through the windows of a Catholic church in Minneapolis and struck children celebrating Mass during the first week of school, killing two and wounding 17 people in an act of violence the police chief called "absolutely incomprehensible."

Minneapolis Police Chief Brian O'Hara said the shooter — armed with a rifle, shotgun and pistol — approached the side of the church and shot dozens of rounds through the windows toward the children sitting in the pews during Mass at the Annunciation Catholic School just before 8:30 a.m. Police believe the shooter then killed himself.The children who died were 8 and 10, and 14 other kids were among the wounded, the chief said. Dozens of youngsters were inside.Michael Simpson said his 10-year-old grandson, Weston Halsne, was nicked by a bullet as he sat near the church windows. His voice shaking as he left the area around the school, Simpson said the violence during Mass on the third day of school left him wondering whether God was watching over."

I don't know where He is," Simpson said.Official identifies the shooterThe police chief said the shooter was in his early 20s, did not have an extensive known criminal history and is believed to have acted alone, but did not release the name or information on possible connections to the school. A law enforcement official told The Associated Press authorities have identified the shooter as Robin Westman. That official was not authorized to discuss the ongoing investigation and spoke on condition of anonymity.

White House fires US health agency head after she refused to quit

WASHINGTON. (Agency)

The Trump administration confirmed Wednesday it was firing the head of the top US public health agency after she refused to step down during a stand-off with vaccine skeptic Health Secretary Robert F. Kennedy Jr.The escalating dispute over Kennedy's sweeping overhaul of US vaccine policy also led to five other senior officials at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) announcing their resignations, according to a union representing some of the agency's workers.Susan Monarez, a health scientist and longtime civil servant, had been the CDC's head for less than a month when Kennedy's Department of Health and Human Services (HHS) announced on X that she "is no longer director."But Monarez "neither resigned nor received notification from the White House that she has been fired," her lawyers said in a statement sent to AFP."As a person of integrity and devoted to science, she will not resign," the lawyers said, accusing Kennedy of "weaponizing public health for political gain and putting millions of American lives at risk."Monarez was targeted after she "refused to rubber-stamp unscientific, reckless directives and fire dedicated health experts," it added.

However, the White House later confirmed that Monarez had been fired."As her attorney's statement makes abundantly clear, Susan Monarez is not aligned with the

President's agenda of Making America Healthy Again," White House spokesman Kush Desai said in an emailed statement to AFP."Since Susan Monarez refused to resign despite informing HHS leadership of her intent to do so, the White House has terminated Monarez from her position with the CDC," he added.The Washington Post, which first reported Monarez's dismissal, said Kennedy pressured her to resign after she refused to commit to supporting his vaccination policy changes.In the aftermath, five high-ranking CDC officials emailed in their resignations, according to a union representing more than 2,000 CDC workers."We were shocked to hear of the sudden resignation of multiple experienced public health leaders at CDC," the AFGE Local 2883 union said in a statement."Many felt forced to walk away from the jobs they loved because politics left them no choice," the union said, adding: "Vaccines save lives."

"Enough is enough," said Demetre Daskalakis, who resigned as director of the CDC's National Center for Immunization and Respiratory Diseases."I am unable to serve in an environment that treats CDC as a tool to generate policies and materials that do not reflect scientific reality and are designed to hurt rather than to improve the public's health," he wrote on X.The CDC's chief medical officer Debra Houry and Daniel Jernigan, director of the agency's National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, were also among those who resigned, according to US media citing notes sent to staff.Public health under attackSince taking office, RFK Jr, as he is known, has overhauled US vaccine policy, dismissing renowned immunization experts, restricting access to Covid-19 shots and new vaccines.

France Beheaded An African King 100 Years Ago. His Skull Is On Its Way Home

Antananarivo. (Agency)

France has returned three human skulls, including one believed to be that of a 19th-century Malagasy King Toera of the Sakalava people, to Madagascar. This comes 128 years after

they were carried to France. The restitution was carried out in a ceremony held at the French Ministry of Culture on August 26. It marks the first use of the 2023 French law that enables the return of human remains to a country for funeral purposes.

The other two skulls belonged to Sakalava warriors who fought with King Toera and were also put to death during the bloody uprising against the Menabe kingdom in western Madagascar, CNN reported.

French troops defeated the Sakalava kingdoms in the late 19th century and colonised Madagascar. King Toera was killed and beheaded by French forces during the August 1897 massacre. His skull was then taken as a trophy to Paris and placed in the National Museum of Natural History, along with numerous other remains from Madagascar.

"These skulls entered the national collections in circumstances that clearly violated human dignity and in a context of colonial violence," said French Culture Minister Rachida Dati.Her Madagascar counterpart, Volamiranty Donna Mara, hailed the handover as a groundbreaking gesture that ushers in a new era of cooperation between the two nations, Al Jazeera reported.

"Their absence has been, for more than a century, 128 years, an open wound in the heart of our island," she said.Since taking office in 2017, French President Emmanuel Macron has admitted to certain previous wrongdo

ings by France in Africa. While visiting the capital Antananarivo in April, Macron mentioned that he was seeking "forgiveness" for France's "bloody and tragic" colonisation of Madagascar.The country gained independence in 1960 after more than 60 years of colonial control. The skulls are scheduled to return to the Indian Ocean island on Sunday for their burial.

Lionel Messi powers Inter Miami past Orlando City to Leagues Cup final

New Delhi. (Agency)

Lionel Messi once again proved decisive as Inter Miami advanced to the Leagues Cup final with a 3-1 victory over Orlando City in Fort Lauderdale on Wednesday night. The Argentine forward scored twice and provided an assist in a devastating late spell, ensuring the Herons reached their second final in three years.

Orlando, who had beaten Miami twice in Major League Soccer this season, began confidently and took the lead just before the interval. In first-half stoppage time, Marco Pasalic capitalised on a defensive lapse. After being briefly dispossessed by Maximiliano Falcon, the ball ricocheted kindly off his chest and he lashed a half-volley beyond Oscar Ustari to give the visitors a 1-0 advantage.Miami pressed after the restart but struggled to find a breakthrough until the turning point arrived in the 74th minute.

Tadeo Allende got in behind David Brekalo and directed a header on target, which Pedro Gallese parried. However, referee Walter Lopez judged that Brekalo had pulled Allende back in the process. The defender received a second yellow card and was dismissed, leaving Orlando with 10 men.Messi seized the moment. From the resulting penalty in the 77th minute, he coolly struck low to the right. Gallese dived the right way but was unable to keep it out, and Miami were level. The equaliser galvanised the hosts, who sensed an opportunity to punish their short-handed rivals.

In the 88th minute, Messi combined brilliantly with Jordi Alba, rekindling their Barcelona chemistry.

A swift exchange of passes unlocked Orlando's defence before Messi finished neatly into the bottom corner to complete the turnaround.The 37-year-old was not done. In stoppage time, he linked with Telasco Segovia, slipping a pass that the Venezuelan midfielder converted from close range to seal the result and spark celebrations at Chase Stadium.

Miami, winners of the 2023 Leagues Cup, will now travel to face the Seattle Sounders in Sunday's final. The Sounders earned their place with a 2-0 victory over LA Galaxy earlier in the evening. The winner will secure direct entry into the round of 16 of the 2026 CONCACAF Champions Cup.

England's batting line-up will be unbelievable in Ashes: Josh Hazlewood

New Delhi. (Agency)

Australian fast bowler Josh Hazlewood has admitted that the upcoming Ashes series will be one of the biggest tests of his career as he prepares to take on what he calls a formidable England batting lineup. He heaped praise on Joe Root and Harry Brook, two of England's finest Test batters, who headline a side that has not won the Ashes in Australia since the 2010-11 series.Hazlewood commended the strength of England's top order, calling it the most dangerous unit he has faced in an Ashes contest. Among the key players, he highlighted Harry Brook, ranked No. 2 in the world, and Joe Root, Test cricket's second-highest run-scorer, who he feels is in the form of his career.

"England has obviously played on quite flat wickets in recent years, and it's been a really dry summer as well, so they are probably starting to get tired and spin now. I think [Brook] will adapt. He's a good player. He's at the top of the rankings for a reason, and he'll be a tough challenge," Hazlewood said.The experienced pacer also believes that vice-captain Brook's aggressive style could suit Australian conditions, even though this will be his first Ashes tour down under. The 25-year-old has already amassed 2,820 runs at an average of 57.55, including 10 centuries in just 30 Tests."I think a fresh face like Harry Brook might find it easier. There's no baggage behind him and he can

just come out and play with freedom as he does. Joe's [Root] probably in the form of his life as well. So they're an unbelievable batting line, to be honest. The top seven have done really well... so it's a challenge," e added. Hazlewood's preparations underline how seriously he is taking the series. While bowling partners Pat Cummins and Mitchell Starc opted to rest and manage workloads, the 33-year-old chose to keep himself in rhythm by playing in the white-ball series against South Africa, featuring in three T20Is and two ODIs."

It felt like over the last 12 months, the best way for me to go about it is just keep on ticking over, keep playing, not having too long off bowling. I find getting back to that intensity and volume is quite tough for me. So if I can just keep staying up there.

Ever-improving Neeraj eyes Diamond Trophy before World Championship showdown

New Delhi. (Agency)

Neeraj Chopra is no stranger to the podium. The two-time Olympic champion, however, hasn't lifted a major title since his triumph at the World Championships in Budapest in 2023. The Diamond League Final in Zurich now offers India's golden boy a chance to end that drought, as he arrives as the clear favourite in a seven-man field on Thursday, August 28.Neeraj, who etched history as the first Indian to win the prestigious Diamond Trophy in 2022, has had to settle for second place in the last two editions. After conquering the world in Budapest in 2023, he went into the Paris Olympics as the man to beat. But this time it was Pakistan's Arshad Nadeem who edged him out, forcing the Indian ace to finish with a silver medal.Now, with two major events crammed into a matter of weeks—the Diamond League

Final and the World Championships - Neeraj is chasing more than just titles. His sights are firmly set on pushing his own limits, continuing a relentless pursuit of progress and perfection that has defined his career.Few athletes have been as consistent as Neeraj over the last two Olympic cycles. With podium finishes in each of his last 36 appearances at the elite level, he has turned winning into a habit. Since that unforgettable gold-medal throw in Tokyo, the javelin star has crossed 88 metres on 19 occasions - a staggering measure of his dominance and consistency in men's javelin.

EVER-IMPROVING NEERAJThe number that once defined him, though, is finally behind him. Earlier this year in Doha, Neeraj became the first Indian to breach the magical 90m mark. It was a moment of vindication after years of expectation. "I was waiting so long for 90m," he admitted. "People have been asking me about it since I threw 88m in 2018. It was always in my head. Now, it's over. I am happy that people are no longer asking this question."But for Neeraj, Doha was not a finish line - it was a starting point. "I really want to throw more and more consistently over 90m," he said. "It was early in the season, and my focus has been on zoning in on good technique. In training, I am doing really good with my coach Jan elezn. I want to ensure I compete with the same technique in competition."Technique is the obsession that drives him forward. Even his best throws, he insists, leave room for improvement. "In Doha, the throw was good, but I won't say my technique was perfect. If my left leg can be straighter and if I use the perfect block, that will be a really good throw. Then I will be satisfied with the speed," he explained.Jan Zelezny's influence looms large in Neeraj's evolution, particularly when it comes to refining the finer points of his craft. Training under the Czech legend - the man who has crossed 90 metres more times than anyone in history - is, for Neeraj, a privilege.

"When Jan competed, he was on another level," Neeraj reflected."I have looked up how to manage pressure and be consistent.

Dhruv Jurel, Abhimanyu Easwaran miss Duleep ties with fever and groin injury

New Delhi. (Agency)

Central Zone captain Dhruv Jurel and East Zone skipper Abhimanyu Easwaran were absent as the Duleep Trophy quarter-finals got underway in Bengaluru on Thursday, dealing a blow to their respective sides.

North Zone, too, entered the match with a leadership change. Original skipper Shubman Gill was sidelined after failing to recover from a fever in time. Vice-captain Ankit Kumar stepped up to lead the team, while Shubham Goel was added as Gill's replacement.Central Zone faced a similar challenge with Jurel missing the clash against NorthEast Zone due to a groin niggle that flared up on the eve of the match. Although the Test specialist was present for pre-match proceedings, team management advised him to sit out to avoid further aggravating the injury. In his absence, Rajat Patidar, who captained Royal Challengers Bengaluru to their IPL title

earlier this year and was Central Zone's vice-captain, took over the leadership role in the high-stakes knockout game.East Zone faced an even bigger crisis. Abhimanyu Easwaran fell ill with a fever on the morning of their quarter-final against North Zone at the BCCI Centre of Excellence. His absence left a void in the top order, compounded by the unavailability of pacer Akash Deep and wicketkeeper-batter Ishan Kishan. Assam all-rounder Riyan Parag was handed the captaincy, stepping into the leadership void to guide a weakened side in a tough encounter.Easwaran's absence was particularly disappointing, given his recent stint on the five-Test tour of England, where he remained on the bench throughout. Like Jurel, he has been part of India's squad in the longest format but has struggled for opportunities.

India is ahead in clean energy commitments, achieves 2030 goal five years early

New Delhi. (Agency)

Most of the "common man items" are proposed to be moved to the lower GST slab rate of 5 per cent under the GST rationalisation initiative, government sources said on Friday, noting that the Centre will closely engage with states to build a broad-based consensus in the coming weeks.

The sources said that food items and daily use items will fahe proposal on restructuring and new GST slabs will have marginal negative effect on GST collection. They said the proposal has been sent to the Group of Ministers (GoM) to enable constructive and inclusive dialogue. "This will have a big impact on reinvigorating core economic sectors like agriculture, textiles, fertilisers, renewable energy, automotive, handicrafts, healthcare, insurance, construction, transportation," a source said. Sources said a meeting of the GST Council is likely to be held in September-October to consider the proposal.

Referring to the pillars of structural reforms, rate rationalisation and Ease of Living, the sources said that structural reforms include correction on invested duty structure (IDS), aligning input and output tax in key sectors to eliminate IDS, supporting domestic value addition and improving liquidity specially for MSMEs. Classification issues would be resolved and there will be streamlining of tax

structure on namkeen, savouries. Charith Asalanka will captain the side, with experienced names like Kusal Mendis, Pathum Nissanka and Dasun Shanaka providing stability. In Hasaranga's absence, the onus will fall on young all-rounders Dunith Wellalage and Kamindu Mendis to step up. The tour also provides an opportunity for fringe players such as Kamil Mishara and Vishen Halambage to make a case for Asia Cup selection.Sri Lanka's tour of Zimbabwe begins with two ODIs in Harare, scheduled for August 29 and 31. The sides then meet in a three-match T20I series, also in Harare, with games on September 3, 6, and 7, serving as vital preparation ahead of the Asia Cup 2025.

Sri Lanka, who finished as the runners-up in the previous edition, are scheduled to begin their upcoming Asia Cup campaign on Saturday, September 13 at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi.

Sri Lanka squad for Zimbabwe T20Is

Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Vishen Halambage, Dasun Shanaka, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushan Hemantha, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana.

US Open 2025, Day 5, Order of Play: Swiatek, Sinner, Gauff aim for Round 3 berths

New Delhi. (Agency)

Day 5 of the 2025 US Open offers a packed line-up featuring top seeds and home favourites across the show courts. At Arthur Ashe Stadium, World No. 2 Iga Swiatek opens against Suzan Lamens, aiming to maintain her dominant form.

Top seed Jannik Sinner follows with a testing clash against Alexei Popyrin, while American No. 3 seed Coco Gauff meets Donna Vekic in a highly anticipated battle.

At Louis Armstrong Stadium, 10th seed Lorenzo Musetti takes on Belgian veteran David Goffin in the

opening match. Naomi Osaka, seeded 23rd and looking to continue her strong return, faces Hailey Baptiste in a match sure to attract attention.Third seed Alexander Zverev then meets Jacob Fearnley, before eighth seed Amanda Anisimova plays Maya Joint to round off the session.

The Grandstand also features plenty of action. Fifteenth seed Andrey Rublev faces Tristan Boyer, while Sorana Cirstea challenges 11th seed Karolna Muchova.

Later, doubles action sees Venus Williams and Leylah Fernandez take on Lyudmyla Kichenok and Ellen Perez, with the day closing as 26th seed Stefanos Tsitsipas battles Daniel Altmaier.

RCB's first post in 3 months after Bengaluru stampede: The silence was grief

New Delhi. (Agency)

Royal Challengers Bengaluru (RCB) on Thursday ended their three-month silence on social media with an emotional message addressed to their fans - the self-styled "12th Man Army" - while announcing the launch of "RCB Cares," an initiative aimed at honouring supporters and assisting families affected by the stampede that marred the team's title celebrations in June.

The tragedy occurred on 4 June 2025, when thousands gathered outside the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru to celebrate RCB's maiden Indian Premier League (IPL) triumph. Eleven people lost their lives, and 56 others were injured in the crush, even as festivities continued inside the venue. The contrast drew widespread outrage, with the franchise facing heavy criticism for its muted response.In the aftermath, RCB announced compensation of Rs 10 lakh for each of the deceased families and launched the "RCB Cares" fund to support injured fans and provide medical assistance. These measures were presented as a way to reaffirm the club's solidarity with its supporters in a time of grief.The Karnataka state government also placed responsibility for the incident on RCB, further fuelling public anger. While the franchise had issued a brief statement of condolence immediately after the tragedy, their prolonged silence remained a source of mounting scrutiny.On Thursday, RCB returned to Instagram with a candid post, acknowledging the grief and unveiling their new initiative:"It's been close to three months since we last posted here.

The silence wasn't absence. It was grief. This space was once filled with energy, memories and moments that you enjoyed the most. But June 4th changed everything.

Jasmin Bhasin

Looks Cute In Polka Dot Mini Dress With A Pop Of Red Glam

Jasmin Bhasin knows how to slay in every outfit, and her recent Instagram post is the proof. In the latest photoshoot, Jasmin opted for a beautiful flowy white mini dress featuring black polka dot designs printed over it. The gown featured balloon sleeves with cut-out detailing and a plunging V-neckline, giving the overall appearance a touch of glamour.In the snaps shared on her Instagram, Jasmin could be seen striking stunning poses as she paired her outfit with contrasting red footwear. For the hair, the actress left them open, cascading down her shoulder with soft curls at the end. Jasmin knows how to let her natural beauty shine with minimal to no makeup look, and for this appearance, she wore a light pink nude lipstick and elongated mascara.

For accessories, the actress chose a chic bracelet along with tiny earrings that matched her footwear. In one of the pictures, the actress could be seen sitting on the edge of the sofa, giving sensual vibes.While sharing the snaps, Jasmin wrote, "Blessing your feed with polka dots".

About Jasmin Bhasin

Jasmin Bhasin recently joined boyfriend Aly Goni and filmmaker Farah Khan for the latter's YouTube vlog, where the two talked about their relationship. Jasmin and Aly found love on Bigg Boss 15, and since 2020, they have been going strong. Now, they have their own house where the two are in a live-in relationship.

In the vlog, Farah talked about their interfaith relationship and asked if their parents had asked them to get married. To this, Jasmin said, "Nahi, mummy daddy hum dono ke hi kamal ke hain." To which Farah said, "Of course, and considering your relationship is cross-communal, it's so lovely." To this, Aly replied, "Koi issue nahi hai."Aly Goni and Jasmin Bhasin met each other in 2018 during their participation in Rohit Shetty's reality show Khatron Ke Khiladi. Their time together in Argentina for the show's shoot led to a deep friendship, which blossomed into a love story after Aly entered the Bigg Boss house as a wildcard entry, where Jasmin was already locked as a contestant. During the stint, he secretly confessed his feelings to Jasmin, and ever since, they have been together.

SRK, Deepika Padukone Sued For THIS Reason; Sunita Ahuja Dismisses Govinda Divorce Rumours

Bollywood stars Shah Rukh Khan and Deepika Padukone, along with six officials from Hyundai, have been named in an FIR in Bharatpur, Rajasthan, over allegations of fraud linked to the promotion of a vehicle said to have manufacturing defects. The case stems from a complaint filed by a local resident, who alleged that his Hyundai Alcazar SUV, purchased in 2022, developed major technical issues within months, and despite repeated follow-ups, the problems were not resolved.

It's a big day for Bonrad fans! It's official! The wedding the finally off and Belly is on her way to Paris. Episode 8 of The Summer I Turned Pretty was released today, and it has Bonrad fans in a chokehold. From Conrad being open about his love for Belly to Taylor asking Belly to confront her feelings, and from Jeremiah calling off the wedding to Belly seeing Conrad at the airport, this episode was an emotional journey for fans.

Bollywood actor Govinda and his wife Sunita Ahuja have been in the headlines due to rumours surrounding their marriage. On the occasion of Ganesh Chaturthi, the couple made their first appearance together as they welcomed Ganpati Bappa home. While addressing the media, Sunita spoke about the growing rumours and confirmed that everything is fine between them, adding that no one can separate the two.

Janhvi Kapoor and Sidharth Malhotra are gearing up for the release of their next movie, Param Sundari. On Wednesday, a screening of the film was held in Mumbai, which was attended by the two stars along with their loved ones. For the occasion, Janhvi sported an uber-cool outfit and grabbed everyone's eyeballs.Popular music director and singer Amaal Mallik has revealed that he used to have a crush on Shraddha Kapoor when they were in school. He said Shraddha was his senior and wore dentures in school. He said that Shraddha's simplicity and honesty won him over, and are the real reason behind her humongous Instagram following.

Gurmeet Choudhary, Wife Debina Bonnerjee 'Embrace Ganpati Bappa With Open Arms'

Ganesh Chaturthi is being celebrated with a lot of joy, fervour and enthusiasm across the nation today. The festival is observed by installing clay idols of Ganesha in homes and public pandals. Keeping up with the auspicious tradition, the television couple Gurmeet Choudhary and Debina Bonnerjee have also welcomed Ganpati Bappa at their home.Gurmeet and Debina were joined by their daughters, Lianna and Divisha. Debina shared a glimpse of the celebration on Instagram.

Gurmeet and Debina's Ganesh Chaturthi celebration

The opening frame featured the family of four standing around the Ganesha deity with folded hands. Debina wore an orange saree, while Gurmeet donned a yellow kurta pyjama set with a matching embellished jacket. Their daughters looked adorable in matching pink tops and skirts.

Further in the post, Debina and Gurmeet were seen performing the aarti. The couple also clicked some more pictures in front of the Ganesha idol. In the caption, the actress wrote, "Our Bappa is Home. This year is extra special as we welcome him into our new home, filled with love, positivity, and gratitude."

She added, "As a family of four, we promise to embrace Bappa with open arms, and may his blessings fill our lives today and in all the years to come. To everyone who visits, may you receive his blessings, joy, and endless love always."

A day ago, Gurmeet Choudhary and Debina Bonnerjee were seen visiting an idol shop before bringing their Ganpati idol home. In the viral video making rounds on the internet, the couple was seen accompanied by their daughters as they lovingly transported the idol.

As per tradition, the Ganpati idol's face was covered with a cloth, which was unveiled during the official Ganesh Chaturthi celebrations. Debina was seen sitting in the car with one of their daughters, while Gurmeet travelled in the tempo van with the idol and their other child.

Gurmeet and Debina's relationship

Gurmeet Choudhary and Debina Bonnerjee secretly eloped and got married in 2006. A more public and traditional wedding ceremony took place in February 2011. The couple welcomed their elder daughter, Lianna, in April 2022 and their second daughter, Divisha, in November that same year.

Janhvi Kapoor

Rocks In An Orange Short Skirt As She Attends Param Sundari Screening

Janhvi Kapoor and Sidharth Malhotra are gearing up for the release of their next movie, Param Sundari. On Wednesday, a screening of the film was held in Mumbai, which was attended by the two stars along with their loved ones. For the occasion, Janhvi sported an uber-cool outfit and grabbed everyone's eyeballs.

Janhvi Kapoor was snapped by the paparazzi as she arrived at the screening. In a video that surfaced on social media, the actress was seen posing for the cameras in a white top with an orange short skirt. She also opted for green heels and colourful bangles. Watch the video here:

On the other hand, Sidharth Malhotra arrived at the screening in a blue shirt with matching denims. Even though the actor kept his look simple, he looked dashing as always.

What Do We Know About Param Sundari?

Directed by Tushar Jalota, Param Sundari follows the lives of a North Indian boy and a South Indian girl, delving into the enchantment and difficulties that develop when two opposing worlds collide. Param Sundari, which stars Sidharth Malhotra and Janhvi Kapoor, combines modern love with Maddock Films' signature charm and visual flair.

Param Sundari has already received a U/A 13+ certificate from the censor board. A report by Bollywood Hungama had recently claimed that the board asked the makers to mute certain words and replace some terms in the subtitles. The word bastard was swapped for idiot, while church and bloody were muted and dropped from subtitles.

Even the word father was asked to be muted. With these edits in place, the film was passed without any visual cuts.Originally set for July, the film was pushed back to avoid a clash with Son of Sardaar 2. Param Sundari is now set to hit theatres on August 29, 2025.